डालटनगंज (मेदिनीनगर), बुधवार | 17 जून 2026 | वर्ष-32, अंक-241, पृष्ठ-12 | शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 03, संवत 2083 | डालटनगंज (मेदिनीनगर) एवं रांची से एक साथ प्रकाशित | रजिस्ट्रेशन नं: 61316/94

मूल्य 2 रु.

ईश्वर में हमारा विश्वास

राष्ट्रीय नवीन मेल

सत्यमेव जयते

www.rastriyanaveenmail.com

हर पक्ष की खबर | हर पक्ष पर नजर

हमारे क्रिटिकल मिनरल्स में अमेरिका की दिलचस्पी, निवेश पर चर्चा

मुख्य सचिव और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की बैठक में दुर्लभ खनिजों की खोज, खनन एवं प्रसंस्करण की संभावनाओं पर मंथन

- लिथियम, टाइटेनियम, वैनेडियम और ग्रेफाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के दोहन पर अमेरिकी कंपनियों ने दिखाई रुचि, खुली नीलामी में भागीदारी के संकेत

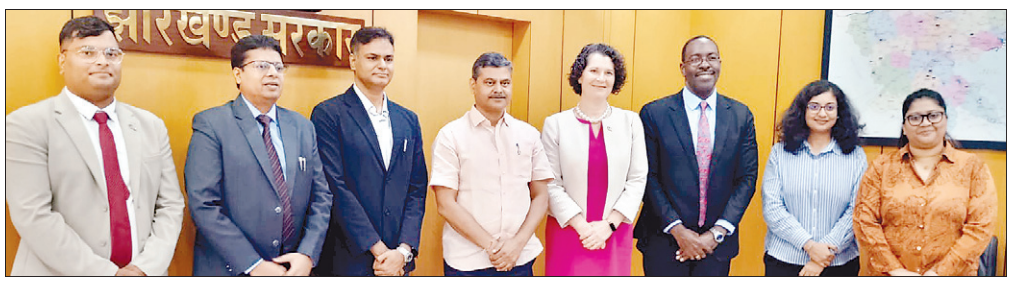

नवीन मेल संवाददाता

रांची। झारखंड में परंपरागत खनिजों के अलावा दुर्लभ खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) की खोज, खनन, प्रसंस्करण एवं तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों ने रुचि दिखाई है। इस संबंध में मंगलवार को राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अमेरिकी काउंसलेट जेनरल कैली जाइल डियाज के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई।

बैठक के दौरान झारखंड में खनिज क्षेत्र में उपलब्ध व्यापक संभावनाओं पर चर्चा की गई। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया गया कि राज्य में परंपरागत खनिजों के विशाल भंडार उपलब्ध हैं तथा इनके खनन एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। बैठक के दौरान अमेरिकी काउंसलेट जेनरल के माध्यम से अमेरिकी कंपनियों को झारखंड में खनन, खनिज अन्वेषण एवं उन्नत तकनीक आधारित गतिविधियों से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया गया। यह भी बताया गया कि इस क्षेत्र में उन्नत तकनीक के साथ कार्य कर रही विश्व की विभिन्न अग्रणी कंपनियों के साथ राज्य सरकार द्वारा निरंतर संपर्क स्थापित किया जा रहा है तथा इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति भी हुई है। बैठक में इच्छुक कंपनियों द्वारा खनिज ब्लॉक प्राप्त कर अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से कार्य किए जाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त, बैठक में खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव अरवा राजकमल, खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा, अमेरिकी काउंसलेट जेनरल कैली जाइल डियाज आदि अधिकारी मौजूद थे।

20 से अधिक दुर्लभ खनिज हैं झारखंड में

राज्य में दुर्लभ एवं महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित 20 से अधिक खनिज हैं, जिनमें लिथियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, सिल्वर, ग्रेफाइट सहित कई महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं। साथ ही, दुर्लभ खनिजों के नए क्षेत्रों की अन्वेषण की प्रक्रिया भी निरंतर संचालित की जा रही है। बैठक में यह जानकारी भी साझा की गई कि अमेरिका की माइनिंग कंपनियों के समूह यूएसआईएसपीए द्वारा झारखंड सरकार के साथ संपर्क स्थापित किया गया है। समूह द्वारा खनिज ब्लॉकों की खुली नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की गई है। विशेष रूप से दुर्लभ खनिजों की खोज, खनन एवं प्रसंस्करण गतिविधियों में रुचि प्रदर्शित की गई है।

चतरा में 13 लाख की अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार

नवीन मेल संवाददाता

चतरा। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पत्थलगड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना क्षेत्र के सिरकोल गांव में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने करीब 13 लाख रुपये मूल्य की 2.567 किलोग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त एक बाइक भी जब्त की है।गिरफ्तार आरोपी की पहचान पत्थलगड़ा थाना क्षेत्र के बड़कीटांड़ खैरा गांव निवासी मनीष मुंडा के रूप में हुई है। उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मंगलवार को प्रेस वार्ता में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) नागरगोजे शुभम भाऊसाहब ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अफीम की खेप लेकर पत्थलगड़ा के रास्ते गिद्धौर की ओर जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए सत्यापन कराया गया और एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया और गिरफ्तारी हुई।

मेदिनीनगर	गढ़वा
अधिक. 42.0°	अधिक. 39.0°
न्यून. 29.0°	न्यून. 26.0°

दृष्टिपात

चाईबासा में खेत में काम कर रही युवती पर बिजली गिरी, मौत

चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत शरीदिरी गांव में मंगलवार को वज्रपात की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई। मृत युवती की पहचान गांव निवासी गुंडई मुंडू की पुत्री सुरारी मुंडू (18 वर्ष) के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार, सुरारी मुंडू मंगलवार को खेत में कृषि कार्य कर रही थी। इसी दौरान मौसम अचानक बदल गया और तेज बारिश के साथ वज्रपात होने लगा। खेत में मौजूद युवती आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण उसे तुरंत बंदगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

आज / कल

कृषि उत्पाद एवं व्यापार मेला-2026 के उद्घाटन पर हेमंत सोरेन ने कहा-

कृषक व सरकार साथ हों, तो राज्य की तस्वीर बदल जाएगी

बोले सीएम

- राज्य के किसानों को मजबूत बनाने के लिए सरकार और किसानों को मिलकर काम करना होगा
- राज्य की लगभग 80 प्रतिशत आबादी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है
- जलवायु परिवर्तन और भू-जल संकट है खेती के लिए सबसे बड़ी चुनौती

- टाना भगत परिवारों को दुधारू पशु शेड निर्माण हेतु 100 प्रतिशत अनुदान पर चेक वितरित
- उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित किया गया तथा नियुक्ति पत्र और डिजिटल एआई किट प्रदान की गई
- मुख्यमंत्री ने बिरसा कृषि रथ-2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

नवीन मेल संवाददाता

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को 'झारखंड कृषि उत्पाद एवं व्यापार मेला 2026' के भव्य उद्घाटन समारोह में कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की आजादी के बाद सबसे पहली परिकल्पना हमारे अन्नदाता को लेकर ही की गई थी, इसीलिए 'जय जवान, जय किसान' का नारा बुलंद हुआ। उन्होंने कहा, खेती-बाड़ी और किसान का इतिहास इस धरती पर किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या संप्रदाय के वजूद में आने से कहीं पुराना है। कृषि ने ही घुमंतू इंसान को एक जगह ठहरकर समाज की नींव रखना सिखाया। यह मानव सभ्यता की एक अनवरत यात्रा है। मुख्यमंत्री सोरेन उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे।

मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि आधी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी और आधी जिम्मेदारी किसानों को उठानी होगी। जब दोनों मिलकर प्रयास करेंगे, तो झारखंड के किसानों को कोई हरा नहीं सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक तथा राज्य सरकार की साझा सहयोग से ही राज्य की तस्वीर बदलेगी।

शेष पेज 11 पर...

1.50 लाख एकड़ बंजर जमीन में पेड़ लगाए, लंदन जा रहे यहां के आम

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बंजर भूमि और खेतों पर लगाए गए फलदार पौधों का परिणाम दिखने लगा है। मुख्यमंत्री ने कहा, हाल दिनों में ही सिमडेगा की जेएसएलपीएस से जुड़ी दीदियां मुझसे मिलने आई थीं। उनके द्वारा बागवानी के माध्यम से उपजाया गया आम आज सीधे लंदन (इंग्लैंड) निर्यात हो रहा है। व्यक्तिगत प्रयासों और सरकारी योजनाओं के सही समन्वय से हमारे किसानों ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में किसानों की आय में वृद्धि हो, इसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत रही है। हमने पिछले कार्यकाल में बिरसा हरित ग्राम योजना शुरू किया, जहां बंजर भूमि में फलदार पेड़ लगाने की शुरुआत की गई। वर्तमान समय में लगभग 1.50 लाख एकड़ बंजर जमीन में पेड़ लगाने का काम हुआ है।

किसानों से जैविक खेती पर ध्यान देने की अपील

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों से आग्रह किया कि फसलों को उगाने में जहरीले पदार्थ का इस्तेमाल न करें। रासायनिक खाद का इस्तेमाल भी कम से कम हो, यह सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि चंद रुपयों की लालच में दूसरों की जान खतरे में न डालें, क्योंकि यह जहरीला अनाज घूमकर हमारे अपने परिवार के पेट में ही जाता है। उन्होंने किसानों से अधिक से अधिक जैविक खाद उपयोग करने की अपील की, मुख्यमंत्री ने बताया कि झारखंड सरकार इसके लिए एक सुलभ रास्ता तैयार कर रही है। जिन राज्यों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल हुआ, वहां की फसल अब कोई लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व के दौर में झारखंड में लोग भूख से मरते थे, लेकिन पिछले 7-8 सालों के कार्यकाल में सरकार ने हर गरीब के घर को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत किया है। किसी की मौत भूख से नहीं हुई। राज्य सरकार झारखंड के कृषकों के उत्थान के लिए कृतसंकल्पित होकर कार्य कर रही है।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसान किए जाएंगे सम्मानित

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि विभाग को निर्देश दिया है कि वे राज्य के सभी बेहतर व आधुनिक खेती करने वाले किसानों की मैपिंग करें। उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सीधे मुख्यमंत्री की तरफ से सम्मानित किया जाएगा और उन्हें तकनीकी उपकरणों से लैस करने के लिए आर्थिक सहायता दिए जाने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। मुख्यमंत्री ने कहा, कृषि व्यापार मेला का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया है कि कृषकों की आमदनी कैसे बढ़ाई जा सके। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। दोनों को समझना होगा कि सरकार कितना और किसान कितना भार उठा सकते हैं।

सैरात वसूली विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट

झामुमो प्रखंड अध्यक्ष समेत 4 घायल

नवीन मेल संवाददाता

दोनों पक्षों ने कराई प्राथमिकी दर्ज, पुलिस जांच में जुटी

हरिहरगंज (पलामू)। शहरी क्षेत्र के भगत तेंदुआ काली मंदिर के समीप वाहन पड़ाव सैरात वसूली को लेकर मंगलवार को दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना में चार लोग घायल हो गए। घायलों में एक पक्ष से झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अमित कुमार सिंह, राजू शर्मा एवं शंभू यादव, जबकि दूसरे पक्ष से प्रदीप कुमार शामिल हैं। इनमें अमित कुमार सिंह और प्रदीप कुमार की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से हरिहरगंज थाना में एक-दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने बताया कि नगर पंचायत के वाहन पड़ाव सैरातधारक मेघा इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर दिनेश मेहता ने भगत तेंदुआ निवासी प्रिंस कुमार, रंजय कुमार, सुधीर कुमार, राजू, सोहराई पासवान सहित अन्य लोगों पर सैरात वसूली कर रहे कर्मियों के साथ मारपीट करने तथा राशि छीनने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है।

वहीं दूसरे पक्ष से विजय पासवान ने शंभू यादव, अमित कुमार सिंह, राजू शर्मा सहित अन्य लोगों पर रंगदारी वसूलने, गाली-गलौज करने तथा विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है।

थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद विधिसम्मत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बुजुर्ग की डंडे से पीटकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

- गुमला के घाघरा में हुई वारदात, कारण अभी स्पष्ट नहीं

नवीन मेल संवाददाता

गुमला। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के चट्टी गांव में एक वृद्ध व्यक्ति की डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृत वृद्ध की पहचान चट्टी गांव निवासी धना उरांव के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, घटना मंगलवार सुबह की है।

परिजनों ने कहा कि धना उरांव रोज की तरह शौच के लिए घर से खेत की ओर निकले थे। इसी दौरान घर से कुछ दूरी पर गांव के ही छोटू उरांव ने उन पर डंडे से हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलने पर घाघरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, गुमला भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त डंडा भी बरामद कर लिया है। वारदात के बाद आरोपी गांव में ही मौजूद था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे आशंका थी कि यदि वह धना उरांव पर हमला नहीं करता, तो उसकी खुद की जान को खतरा हो सकता था। हालांकि, पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों के अनुसार, घटना के कारणों को लेकर कई बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है।

एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने कहा कि स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों ने आरोपी की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं होने की बात कही है। हालांकि, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। उन्होंने कहा कि जिले में पूर्व में जमीन विवाद, पारिवारिक रंजिश और अंधविश्वास से जुड़े मामलों में भी हत्या की घटनाएं सामने आती रही हैं। इसलिए पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर वृद्ध की हत्या

65 वर्षीय बिगन उरांव की मौत से क्षेत्र में सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

बालूमाथ। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत 65 वर्षीय वृद्ध की धारदार हथियार से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान चितरपुर गांव निवासी बिगन उरांव के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव की स्थिति को देखकर आशंका जताई जा रही है कि अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर वृद्ध की बेरहमी से हत्या की है। हालांकि हत्या के कारणों का अब तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। सूचना मिलने के बाद बालूमाथ थाना प्रभारी अमित कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं गांव में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा।

अपराध

बादम कोल परियोजना क्षेत्र में बढ़ा तनाव; पुलिस ने जांच तेज की

बीजीआर इंफ्रा माइनिंग के कार्यालय में तोड़फोड़

- हजारीबाग के अंबाजीत स्थित कंपनी साइट पर तड़के हुआ हमला
- पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और स्थानीय लोगों से कर रही है पूछताछ

नवीन मेल संवाददाता

हजारीबाग। हजारीबाग जिले में एनटीपीसी की बादम कोल खनन परियोजना के लिए काम करने वाली बीजीआर इंफ्रा माइनिंग के अंबाजीत स्थित साइट कार्यालय पर मंगलवार तड़के बड़ी संख्या में अज्ञात लोगों ने धावा बोलकर तोड़फोड़ की। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है।

पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी रहीं। घटना तड़के करीब पांच बजे की बताई जा रही है। हमले में कार्यालय की संपत्ति और संरचनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। किसी कर्मचारी के घायल होने की सूचना नहीं है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ दिन पहले परियोजना प्रभावित ग्रामीणों ने कंपनी के अधिकारियों को घेर लिया था। बाद में पुलिस हस्तक्षेप के बाद अधिकारियों को वहां से सुरक्षित निकाला गया। इस घटना के संबंध में कंपनी की शिकायत पर सैकड़ों ग्रामीणों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। बताया जा रहा है कि इसी कार्रवाई को लेकर इलाके में नाराजगी बढ़ रही थी। मंगलवार सुबह अचानक बड़ी संख्या में लोग कंपनी के साइट कार्यालय पहुंच गए। देखते ही देखते कार्यालय परिसर में तोड़फोड़ शुरू हो गई। दरवाजे, खिड़कियां, फर्नीचर और अन्य सामान क्षतिग्रस्त कर दिए गए। घटना के दौरान कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही बड़कागांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया।

थाना प्रभारी दीपक सिंह ने कहा कि अज्ञात लोगों की भीड़ ने कार्यालय में तोड़फोड़ की है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर हमलावरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। परियोजना विरोध, हालिया पुलिस कार्रवाई और अन्य संभावित कारणों को भी जांच के दायरे में रखा गया है।

रोजगार और मुआवजे को लेकर नाराजगी

बादाम कोल परियोजना एनटीपीसी की कोयला खनन परियोजना है, जबकि बीजीआर इंफ्रा माइनिंग इसमें माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर (एमडीओ) के रूप में काम कर रही है। परियोजना शुरू होने के बाद से ही भूमि अधिग्रहण, विस्थापन, पुनर्वास, मुआवजा और स्थानीय लोगों को रोजगार देने जैसे मुद्दों को लेकर ग्रामीणों और कंपनी प्रबंधन के बीच विवाद बना हुआ है।

रांची विवि में दूसरे और चौथे शनिवार को रहेगी छुट्टी

- अन्य दिनों में 10:00 बजे से 5:30 बजे तक होगा कार्य संचालन

नवीन मेल संवाददाता

रांची। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने विश्वविद्यालय मुख्यालय के कार्य संचालन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब विश्वविद्यालय में प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहेगा। इसके साथ ही मुख्यालय के कार्यालयों के लिए नया कार्य समय भी निर्धारित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय के सभी कार्यालय अब दिन में 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक संचालित होंगे। इस दौरान कुल साढ़े सात घंटे की कार्य अवधि सुनिश्चित की जाएगी।

मंगलवार को विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सभी विभागों, शाखाओं और संबंधित कार्यालयों को निर्धारित कार्यालय अवधि का अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कार्यालयीन कार्यों के सुचारु संचालन और कर्मचारियों की कार्य दक्षता को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है।

अब कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रत्येक माह के दूसरे एवं चौथे शनिवार को नियमित अवकाश का लाभ मिलेगा, जबकि शेष कार्यदिवसों में निर्धारित समय के अनुसार कार्यालय संचालित होंगे।

ऊंटारी रोड अंतर्गत बांकी नदी किनारे दफन अज्ञात शव कब्र से निकाला गया

मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई कार्रवाई , पोस्टमार्टम के लिए एमएमसीएच भेजा गया शव

नवीन मेल संवाददाता

ऊंटारी रोड। पलामू जिले के ऊंटारी रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत बांकी नदी के समीप दफनाए गए एक अज्ञात शव को मंगलवार को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र से बाहर निकाला गया। यह कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई। मौके पर मजिस्ट्रेट वासुदेव राय, ऊंटारी रोड थाना प्रभारी संतोष कुमार गिरी तथा आरपीएफ के दो जवान मौजूद रहे। ऊंटारी रोड थाना के सब इंस्पेक्टर संजय सिंह, उदय पासवान, मुन्ना लाल जामुदा एवं थाना के चौकीदारों की सहायता से शव को कब्र से बाहर निकाला गया। शव को कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर स्थित एमएमसीएच भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है तथा शव की पहचान के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

मृतक की पहचान को लेकर आसपास के क्षेत्रों में संपर्क जारी

समाचार लिखे जाने तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों से संपर्क कर शव की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। बताया जाता है कि कुछ दिन पूर्व बांकी नदी के समीप यह शव बरामद हुआ था, जिसे आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद दफना दिया गया था। अब मजिस्ट्रेट के आदेश पर शव को पुन: कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, ताकि मौत के कारणों का स्पष्ट पता लगाया जा सके।

कस्तूरबा गांधी विद्यालय में छात्राओं को खिलाई गई एल्बेंडाजोल की गोली

हरिहरगंज (पलामू)। प्रखंड क्षेत्र स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. गोपाल प्रसाद एवं वार्डेन अनिता कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान छात्राओं को कृमिनाशक एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर अभियान की शुरुआत की गई। मौके पर डॉ. गोपाल प्रसाद ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें कृमि मुक्त रखना बेहद आवश्यक है। कार्यक्रम में विद्यालय की वार्डेन, शिक्षिकाएं एवं स्वास्थ्यकर्मी दीपक कुमार, प्रदीप ठाकुर, अभिमन्यु कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

संगठन मजबूत कर जनसमस्याओं पर आंदोलन करें : रघुवर दास

नवीन मेल संवाददाता

सतबरवा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व राज्यपाल रघुवर दास का सतबरवा परिसदन भवन में सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं भाजपा नेताओं ने अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत बनाने और जनहित के मुद्दों पर सक्रिय रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रखंड स्तर से लेकर पूरे राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिससे आम जनता परेशान है। कार्यकर्ताओं से उन्होंने जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने की अपील की। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता आशीष कुमार सिन्हा, युवा नेता प्रवेश यादव, अशर्फी यादव, धावाडीह के उपमुखिया मुधिर साहू, उपेंद्र उरांव, राकेश कुमार भुईयां सहित कई कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे।

पूर्व मुखिया जमुना यादव पंचतत्व में विलीन, शोक की लहर

हैदरनगर। कुकही पंचायत के पूर्व मुखिया एवं समाजसेवी जमुना यादव का अंतिम संस्कार मंगलवार को देवरी ग्राम स्थित सोन नदी तट के मुक्ति धाम में किया गया। सोमवार को अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए जमुहार स्थित नारायण मेडिकल एंड रिसर्च हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन की खबर मिलते ही कुकही पंचायत समेत आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई। स्व. यादव लंबे समय तक पंचायत की जनसमस्याओं के समाधान और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे।

बिजली व्यवस्था नहीं सुधरी तो होगा आंदोलन : नगर अध्यक्ष

नवीन मेल संवाददाता

छतरपुर (पलामू)। छतरपुर नगर पंचायत अध्यक्ष अरविन्द कुमार गुप्ता ने नगर क्षेत्र में चरमराई बिजली व्यवस्था को लेकर बिजली विभाग पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र के लोग ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक बिजली बिल का भुगतान करते हैं, इसके बावजूद उन्हें नियमित और पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। नगर अध्यक्ष ने कहा कि लगातार बिजली कटौती के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है, पानी की टंकियां नहीं भर पा रही हैं और भीषण गर्मी में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नगरवासियों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब चुप बैठना संभव नहीं है। यदि शीघ्र बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो नगर पंचायत के नेतृत्व में बिजली विभाग कार्यालय का घेराव, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी। नगर अध्यक्ष ने पलामू उपायुक्त, बिजली विभाग के महाप्रबंधक (जीएम) और कार्यपालक अभियंता (ईई) से तत्काल हस्तक्षेप कर छतरपुर नगर क्षेत्र में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है।

दृष्टिपात

जपला आरपीएफ के नये निरीक्षक प्रभारी ने संभाला पदभार

हुसैनाबाद। जपला रेलवे आरपीएफ पोस्ट के नवपदस्थापित निरीक्षक प्रभारी संतोष कुमार झा ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में योगदान देकर पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने रेल यात्रियों की सुरक्षा और रेल संपत्ति की रक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रभारी निरीक्षक श्री झा ने कहा कि यात्रियों को सुरक्षित और भयमुक्त माहौल उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि रेलवे परिसर और ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। साथ ही यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर हेल्पलाइन 139 पर प्राप्त सूचनाओं का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यभार संभालने के बाद निरीक्षक झा ने पोस्ट के अधीनस्थ अधिकारियों और जवानों के साथ परिचय बैठक की। बैठक में वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई तथा महिला और वरिष्ठ नागरिक यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जवानों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया। उन्होंने आम जनता और रेल यात्रियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यात्रा के दौरान किसी भी संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत आरपीएफ अथवा रेलवे हेल्पलाइन पर दें। पदभार ग्रहण करने पर जपला आरपीएफ पोस्ट के जवानों, स्थानीय रेल कर्मियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों ने उन्हें बधाई दी।

अखौरी पतरा में बन रहा भव्य श्री शिव शक्ति धाम मंदिर

नीलांबर-पीतांबरपुर। प्रखंड क्षेत्र के अखौरी पतरा गांव में निर्माणाधीन श्री शिव शक्ति धाम मंदिर जल्द ही क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक एवं आध्यात्मिक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। श्रद्धा, उत्साह और जनसहयोग से मंदिर निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीणों और श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। मंदिर निर्माण समिति के सदस्यों ने बताया कि यह मंदिर केवल पूजा-अर्चना का स्थल नहीं होगा, बल्कि सनातन संस्कृति, धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता का प्रतीक भी बनेगा। समिति के अनुसार मंदिर को भव्य और दिव्य स्वरूप देने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निर्माण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए समिति ने क्षेत्र के श्रद्धालुओं, धर्मप्रेमी नागरिकों और समाज के लोगों से तन, मन और धन से सहयोग करने की अपील की है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष रवीन्द्र कुमार मिश्रा, सचिव लक्ष्मीकांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष रमेश कुमार मिश्रा तथा सहयोगी सदस्य राजकिशोर चंद्रवंशी, पंकज मिश्रा और बसंत नारायण सिंह सहित अन्य सदस्यों ने कहा कि सभी के सहयोग से यह पवित्र स्थल आने वाले समय में भक्ति और आध्यात्मिकता का प्रमुख केंद्र बनेगा। समिति ने आम लोगों से इस धार्मिक संकल्प में सहभागी बनने और श्री शिव शक्ति धाम को पलामू जिले में नई पहचान दिलाने में सहयोग करने का आह्वान किया है।

पांच साल बाद भी नहीं हुआ पेयजल योजना का पूरा भुगतान

मोहम्मदगंज। पंसा पंचायत मुख्यालय स्थित कैलाश सिंह उच्च विद्यालय में 15वें वित्त आयोग मद से स्थापित सोलर ऊर्जा संचालित पेयजलापूर्ति योजना की पूरी राशि का भुगतान पांच वर्ष बाद भी लाभुक समिति को नहीं किया गया है। इससे समिति के सदस्यों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। समिति के सदस्यों ने बताया कि विद्यालय की छत पर पानी की टंकी स्थापित कर पाइपलाइन के माध्यम से नल कनेक्शन दिया गया, जिससे विद्यालय की पेयजल समस्या का समाधान हो गया। लेकिन योजना की बकाया राशि का भुगतान अब तक नहीं होने से उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया कि पंसस सह प्रखंड उपप्रमुख नगीना सिंह को आवंटित राशि से इस योजना को धरातल पर उतारा गया था। 16 अगस्त 2022 से ही इस योजना के माध्यम से विद्यालय में पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से हो रही है। इसके बावजूद संबंधित मद की राशि का पूर्ण भुगतान अब तक लंबित है। लाभुक समिति का कहना है कि इसी मद से संचालित अन्य जलमीनार योजनाओं का भुगतान कर दिया गया, लेकिन इस योजना को नजरअंदाज किया गया। ग्रामीणों ने उपायुक्त से मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई तथा लंबित राशि का शीघ्र भुगतान कराने की मांग की है।

कोसीआरा स्टेशन पथ जर्जर, बरसात में बढ़ेगी परेशानी

मोहम्मदगंज। कादलकुर्मी-दंगवार वाया जपला मुख्य मार्ग से कोसीआरा स्टेशन जाने वाला संपर्क पथ लंबे समय से जर्जर स्थिति में पड़ा है। पटखौलिया स्कूल के समीप से स्टेशन तक जाने वाली सड़क पर जगह-जगह गड्ढे उभर आए हैं, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि हल्की बारिश में भी सड़क पर जलजमाव और कीचड़ फैल जाता है। ऐसे में बरसात के दिनों में इस मार्ग से गुजरना और भी मुश्किल हो जाएगा। सड़क की खराब स्थिति के कारण वाहन चालकों के साथ-साथ पैदल यात्रियों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। गोड़ाडीह पंचायत के पूर्व मुखिया पंचम खान ने बताया कि कोसीआरा स्टेशन तक पहुंचने के लिए गोड़ाडीह, बरडंडा, लटपौरी समेत कई गांवों के लोगों के लिए यही एकमात्र प्रमुख मार्ग है। इसके बावजूद सड़क की मरम्मत या पक्कीकरण की दिशा में अब तक कोई पहल नहीं की गई। उन्होंने बताया कि इस सड़क का निर्माण वर्ष 2002-03 में आरईओ विभाग द्वारा कराया गया था। इसके बाद से कभी इसकी मरम्मत तक नहीं हुई।

समय पर नहीं खुलता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ताला

नौडीहा। बाजार प्रखंड के सरईडीह पंचायत स्थित आती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था पर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य केंद्र का ताला कभी भी निर्धारित समय पर नहीं खुलता, जिससे क्षेत्र की जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र मुख्य रूप से एकमात्र कर्मी अनीता देवी के भरोसे संचालित हो रहा है। कभी दवा वितरण कार्य तो कभी छतरपुर में बैठक रहने के कारण केंद्र नियमित रूप से समय पर नहीं खुल पाता। लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र अक्सर सुबह 11 बजे या 12 बजे खुलता है, जबकि कई बार पूरा दिन भी बंद रहता है। बताया गया कि इस स्वास्थ्य केंद्र से शाहपुर, कोलकाता, मंगराड़ी, तुलसी, हरिया समेत आसपास के कई गांवों के ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करते हैं। लेकिन समय पर केंद्र नहीं खुलने के कारण भोले-भाले ग्रामीण झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज कराने को मजबूर हो जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या की शिकायत कई बार अनुमंडलीय चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. राजेश अग्रवाल तथा छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी को दी गई, लेकिन अब तक न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही चिकित्सक की नियुक्ति की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों के संरक्षण में मनमानी जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि 16 जून 2026 को भी सुबह 10:30 बजे तक स्वास्थ्य केंद्र में ताला लटका हुआ था। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से तत्काल व्यवस्था सुधारने और नियमित स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की मांग की है।

नन्हा सा दिल अभियान से बच्चों को नई जिंदगी की उम्मीद

छतरपुर। सिविल सर्जन एवं उपायुक्त के मार्गदर्शन में प्रखंड क्षेत्र में "नन्हा सा दिल" अभियान के तहत बच्चों के लिए विशेष हृदय जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान का उद्देश्य जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की समय पर पहचान कर उनका निःशुल्क उपचार सुनिश्चित करना है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी एवं शिक्षा विभाग तथा सीसीएल के CSR सहयोग से संचालित हो रहा है। अभियान के तहत 14 जून से 24 जून 2026 तक विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की हृदय जांच की जा रही है। 15 जून को बिशुनपुर, नमुदाग और गुलाबझाड़ी में आयोजित शिविरों में 385 बच्चों की जांच की गई, जिनमें दो बच्चे संदिग्ध पाए गए। वहीं 16 जून को डगरा, सरईडीह और शाहपुर में आयोजित शिविरों में 538 बच्चों की जांच हुई, जिनमें दो बच्चों में हृदय रोग की आशंका पाई गई। जांच के दौरान जिन बच्चों में हृदय रोग की आशंका मिलेगी, उनकी आगे जांच कराई जाएगी। यदि किसी बच्चे में जन्मजात हृदय रोग की पुष्टि होती है तो उसका निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा। इलाज के दौरान बच्चों और अभिभावकों के आने-जाने, रहने और भोजन की व्यवस्था भी निःशुल्क होगी। प्रभारी पदाधिकारी ने कहा कि यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को जांच शिविर में अवश्य लेकर आएं।

अनुमंडलीय अस्पताल में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ

हुसैनाबाद। अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में सोमवार को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अस्पताल के उपाधीक्षक द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं स्वयं अल्बेंडाजोल की दवा का सेवन कर की गई। अभियान का उद्देश्य बच्चों और किशोरों को कृमि संक्रमण से मुक्त कर उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है। इस अवसर पर अस्पताल के चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सहिया एवं अन्य कर्मी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉ. माहिरा इरम, डॉ. अमित कुमार, बीपीएम विभूति कुमार गुप्ता समेत कई स्वास्थ्यकर्मियों ने भाग लिया और अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। उपाधीक्षक डॉ. एसके रवि ने बताया कि अभियान के तहत एक वर्ष से अधिक आयु के सभी चिन्हित लाभुकों को अल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह दवा पूरी तरह सुरक्षित है और बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जो बच्चे या लोग किसी कारणवश मुख्य दिवस पर दवा नहीं ले पाएंगे, उन्हें 18 जून 2026 को आयोजित मॉप-अप दिवस पर अस्पताल या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में दवा खिलाई जाएगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दवा पहुंचाने की जिम्मेदारी सहिया एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है। अस्पताल प्रबंधन ने अभिभावकों से अपने बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा अवश्य खिलाने की अपील की है, ताकि स्वस्थ एवं कृमि मुक्त समाज के निर्माण में सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो सके।

आज से उपलब्ध होंगे भरे हुए रसोई गैस सिलेंडर

मोहम्मदगंज। स्थानीय चौहान इंडेन गैस एजेंसी की ओर से भरे हुए गैस सिलेंडरों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने से उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। एजेंसी प्रबंधक अक्षय सिंह ने बताया कि अब प्रत्येक सप्ताह भरे हुए सिलेंडरों की खेप पहुंच रही है। बुधवार को भी उपभोक्ताओं को सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंगलवार को प्लांट से 342 भरे हुए सिलेंडरों की खेप रवाना कर दी गई है, जो गोदाम पहुंचने के बाद एजेंसी कार्यालय से उपभोक्ताओं को वितरित की जाएगी। साथ ही होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। प्रबंधक ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं के सिलेंडर उठाव की नियमानुसार 45 दिन की अवधि पूरी हो चुकी है, वे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल कर बुकिंग करा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अब कार्यालय अवधि में नियमित रूप से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पहले यह सुविधा केवल रविवार को उपलब्ध थी।

भीषण गर्मी में बिजली संकट से उबल रहा तरहसी प्रखंड

नवीन मेल संवाददाता

तरहसी (पलामू)। भीषण गर्मी के बीच तरहसी प्रखंड में लगातार हो रही बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि जहां एक ओर सरकार हर घर तक बिजली पहुंचाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में नियमित विद्युत आपूर्ति नहीं होने से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। लोगों का कहना है कि 24 घंटे में मात्र 4 से 5 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, जिससे दिन में कामकाज और रात में आराम दोनों प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण चौक-चौराहों पर बिजली व्यवस्था को लेकर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा स्थिति ने उन्हें पुराने दिनों की याद दिला दी है, जब लोग ढिबरी और हाथ के पंखे के सहारे जीवन बिताते थे। आधुनिक सुविधाएं होने के बावजूद पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से लोगों में निराशा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, भीषण गर्मी के कारण छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। रातभर बिजली कटौती होने से लोगों की नींद प्रभावित हो रही है, जबकि दिन में बिजली नहीं रहने से घरेलू कार्य, व्यवसाय और कृषि गतिविधियां भी बाधित हो रही हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, तरहसी प्रखंड के अध्यक्ष गोपाल प्रसाद ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र होने के बावजूद लोगों को नियमित बिजली नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि लगातार बिजली कटौती से छात्रों की पढ़ाई, किसानों की सिंचाई और व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि मौजूदा फीडर पर अधिक लोड है तो विभाग को वैकल्पिक व्यवस्था या अलग फीडर की योजना बनानी चाहिए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द ही बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो जनता का आक्रोश आंदोलन का रूप ले सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में बिजली के पोल, तार और अन्य आधारभूत संरचनाएं तो स्थापित कर दी गई हैं, लेकिन नियमित आपूर्ति के अभाव में इन सुविधाओं का अपेक्षित लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों ने सरकार और विभागीय अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान करने की मांग की है।

नशा मुक्ति जागरूकता रैली से गूंजा मोहम्मदगंज

'नशे की राह अंधेरी है' जैसे नारों से छात्र-छात्राओं ने दिया जागरूकता का संदेश

नवीन मेल संवाददाता

मोहम्मदगंज। प्रखंड मुख्यालय स्थित पीएमश्री राजकीयकृत स्तरोन्नत प्लस टू उच्च विद्यालय की ओर से मंगलवार को नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। राज्य सरकार द्वारा 26 जून तक चलाए जा रहे अभियान के तहत छात्र-छात्राओं ने प्रभात फेरी निकालकर विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। रैली में शामिल छात्र-छात्राएं बैनर और तख्तियां लेकर "नशे की राह अंधेरी है, इससे दूर रहना समझदारी है" सहित कई जागरूकता संबंधी नारे लगा रहे थे, जिससे पूरा वातावरण गूंजायमान हो उठा। इससे पूर्व विद्यालय परिसर में छात्र-छात्राओं को नशा मुक्ति जागरूकता अभियान को सफल बनाने की शपथ दिलाई गई। प्रधानाध्यापक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि अभियान के तहत छात्र-छात्राओं और अभिभावकों को जागरूक करने के लिए निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन राइटिंग, पेंटिंग, नाटक एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान को सफल बनाने में शिक्षक इश्तियाक अहमद निहाल, प्रियहित कुमार सोनी, प्रदीप कुमार, सोनी कुमारी और रुपम कुमारी सहित अन्य सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

रोहिणी गई, आर्द्रा आने को है, पर बादल अब भी रुठे

हैदरनगर। क्षेत्र के किसानों की निगाहें लगातार आसमान पर टिकी हैं, लेकिन अब तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। रोहिणी नक्षत्र बिना बारिश के ही बीत गया और अब 22 जून से 6 जुलाई तक चलने वाला आर्द्रा नक्षत्र शुरू होने वाला है। किसानों का मानना है कि रोहिणी नक्षत्र खेती की बेहतर शुरुआत का आधार माना जाता है। भाजपा नेता सह किसान रविन्द्र कुमार सिंह सहित विनय कुमार सिंह, अनूप कुमार सिंह, अंकू सिंह और मनोज सिंह ने बताया कि इसी समय खेतों में बोआई का कार्य शुरू होता है, लेकिन इस बार न तो बादल गरजे और न ही बारिश हुई।

संघ के मिलन समारोह में सामाजिक समरसता और संगठन विस्तार पर मंथन

नीलांबर-पीतांबरपुर। प्रखंड मुख्यालय स्थित अटल स्मृति हॉल परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की ओर से साप्ताहिक मिलन समारोह एवं सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों, पदाधिकारियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर सामाजिक एकता और संगठनात्मक मजबूती का संकल्प दोहराया। समारोह का उद्देश्य संगठनात्मक गतिविधियों को गति देना, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना तथा आपसी समन्वय को मजबूत करना था।

हैदरनगर के लपेया में निकली मां भगवती की भव्य कलश शोभायात्रा

वैदिक मंत्रोच्चार, ढोल-नगाड़ों व जयकारों से भक्तिमय हुआ पूरा गांव

नवीन मेल संवाददाता

हैदरनगर। प्रखंड के ग्राम लपेया स्थित देवी मंदिर में नव कलश स्थापना एवं धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ किया गया। इस अवसर पर मंगलवार को भव्य कलश शोभायात्रा सह नगर भ्रमण का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिला-पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मां भगवती के जयकारों से पूरा गांव भक्तिमय माहौल में डूब गया। शोभायात्रा देवी मंदिर परिसर से प्रारंभ हुई, जहां वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि-विधान के साथ कलश पूजन किया गया। इसके बाद सजे-धजे कलशों के साथ गाजे-बाजे, ढोल-नगाड़ों और धार्मिक धुनों के बीच गांव के विभिन्न मार्गों से नगर भ्रमण कराया गया। श्रद्धालु पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ शोभायात्रा में शामिल हुए। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि नव कलश स्थापना के साथ धार्मिक अनुष्ठान एवं पूजा-पाठ का कार्यक्रम शुरू हो गया है। आगामी दिनों में गांव एवं आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इस अवसर पर महेंद्र सिंह, देवदत्त सिंह, ललन मेहता, राकेश मेहता, शिव कुमार, अमरेंद्र सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं ग्राम लपेया के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शोभायात्रा में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाया। भक्ति और आस्था से सराबोर इस आयोजन ने पूरे क्षेत्र को धार्मिक रंग में रंग दिया।

क्षेत्र में सुख, शांति की कामना

नगर भ्रमण के दौरान ग्रामीणों ने विभिन्न स्थानों पर कलश का स्वागत किया तथा मां भगवती से क्षेत्र में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में तथा युवाओं ने धार्मिक ध्वज लेकर यात्रा की शोभा बढ़ाई।

सड़क हादसों पर प्रशासन गंभीर नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

● पांच वर्षों में 1300 सड़क दुर्घटनाओं में 1025 लोगों की मौत

नवीन मेल संवाददाता

मेदिनीनगर। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और यातायात व्यवस्था की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि मई 2026 में जिले में 35 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 29 लोगों की मौत और 17 लोग घायल हुए। वहीं पिछले पांच वर्षों में लगभग 1300 सड़क दुर्घटनाओं में 1025 लोगों की जान गई है। उपायुक्त ने बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, गलत दिशा में वाहन चलाने, ओवरस्पीडिंग और मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग करने वालों के खिलाफ नियमित जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए पर्याप्त संख्या में ब्रेथ एनालाइजर उपलब्ध कराने को कहा। बैठक में बताया गया कि मई माह में यातायात नियम उल्लंघन के खिलाफ 1301 चालान काटे गए और 21.71 लाख रुपये से अधिक की वसूली की गई। हेलमेट नहीं पहनने के सबसे अधिक 476 मामले सामने आए।

पलामू में नशे के खिलाफ सख्त अभियान चलाने का निर्देश

● एनकोर्ड बैठक में डीसी बोले- मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर लगे पूरी रोक

नवीन मेल संवाददाता

मेदिनीनगर। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला स्तरीय नार्कोटिक्स समन्वय समिति (एनकोर्ड) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए।

उपायुक्त ने पांकी, मनातू, पीपराटांड़, छतरपुर और नौडीहा बाजार थाना क्षेत्रों में मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाने को कहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिले में नशे के अवैध कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी।
डीसी ने जिले से बाहर जाने वाले सड़कों और रेल मार्गों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया। साथ ही नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने को कहा।
बैठक में स्कूलों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री पर भी चिंता जताई गई। एक स्कूल के समीप संचालित लाइसेंसी शराब दुकान के बाहर जागरूकता पोस्टर लगाने का निर्देश दिया गया, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शराब नहीं बेचने की चेतावनी अंकित होगी।
उपायुक्त ने डी-अडीक्शन सेंटर को जल्द शुरू करने के लिए समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग को समन्वय बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया।
बैठक में एसपी कपिल चौधरी ने थाना प्रभारियों को अफीम और गांजा के खिलाफ व्यापक कार्रवाई चलाने तथा स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया।

पलामू में अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर प्रशासन सख्त

● 140 वाहनों की जब्ती, 33 लाख रुपये से अधिक की वसूली

नवीन मेल संवाददाता

मेदिनीनगर। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अवैध खनन, अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि खनन विभाग द्वारा अब तक 80 वाहनों को जब्त कर चार प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। साथ ही 24.19 लाख रुपये की वसूली की गई है। वहीं परिवहन विभाग ने 60 वाहनों को जब्त कर 8.91 लाख रुपये राजस्व वसूला है। उपायुक्त ने अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ नियमित संयुक्त छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने मानसून अवधि में एनजीटी के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए संवेदनशील बालू घाटों की निगरानी बढ़ाने को कहा। डीसी ने बंद खदानों में सुरक्षा मानकों का पालन करने और माइंस क्लोजर रिपोर्ट लागू करने पर भी जोर दिया। साथ ही अतिरिक्त ट्रेंच कटिंग, अस्थायी चेकनाका, सीसीटीवी और रात्रि गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया। बैठक में एसपी कपिल चौधरी सहित खनन, परिवहन, वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी मौजूद थे।

स्वच्छता और हरित पहल में लातेहार को राष्ट्रीय पहचान

लातेहार। भारत सरकार की स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 पहल के तहत लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, तुरीसोत का राष्ट्रीय स्तर पर चयन किया गया है। विद्यालय को स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह उपलब्धि हासिल हुई है। विद्यालय परिसर में स्वच्छता बनाए रखने, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था विकसित करने, जल संरक्षण के उपाय अपनाने तथा ऊर्जा के समुचित उपयोग को बढ़ावा देने के साथ विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता विकसित करने के सतत प्रयासों का यह परिणाम माना जा रहा है। विद्यालय की इस सफलता से पूरे चंदवा प्रखंड और लातेहार जिले में खुशी का माहौल है। विद्यालय प्रबंधन ने इसे सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल बताते हुए कहा कि भविष्य में भी विद्यालय स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के मानकों पर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वरिष्ठ शिक्षाविद प्रो. केके मिश्र से की मुलाकात

● शिक्षा व्यवस्था, आपातकाल और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हुई लंबी चर्चा

नवीन मेल संवाददाता

मेदिनीनगर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने मंगलवार को मेदिनीनगर प्रवास के दौरान वरिष्ठ शिक्षाविद प्रो. कमला कांत मिश्र (प्रो. के.के. मिश्र) से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान वे करीब एक घंटे तक उनके आवास पर रुके और विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

मुलाकात के दौरान आपातकाल के दौर की परिस्थितियों, लोकतंत्र पर पड़े प्रभाव तथा मीसा (मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट) के तहत जेल में बंद किए गए लोगों की कठिनाइयों को लेकर गंभीर बातचीत हुई। दोनों ने उस दौर के अनुभवों को साझा करते हुए वर्तमान राजनीतिक हालात और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी विचार-विमर्श किया। चर्चा के दौरान राज्य की शिक्षा व्यवस्था, विशेषकर स्कूलों और कॉलेजों की मौजूदा स्थिति पर भी चिंता जताई गई। प्रो. के.के. मिश्र ने कहा कि राज्य के स्थायी संबद्धता प्राप्त कॉलेजों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इन कॉलेजों के पास आधारभूत संसाधन उपलब्ध हैं और सरकार के थोड़े प्रयास से इन्हें और बेहतर बनाया जा सकता है। इससे उच्च शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और नए कॉलेज खोलने की आवश्यकता भी कम पड़ेगी। प्रो. के.के. मिश्र के पुत्र प्रो. डॉ. संजीव मिश्र ने बताया कि यह उनके परिवार के लिए अत्यंत सुखद और सम्मानपूर्ण क्षण रहा। उन्होंने कहा कि रघुवर दास ने आत्मीयता के साथ उनके पिता से मुलाकात की और लंबे समय तक विभिन्न विषयों पर चर्चा की। बातचीत के दौरान शिक्षा, समाज, लोकतंत्र और युवाओं की भूमिका जैसे विषयों पर भी गंभीर संवाद हुआ। डॉ. संजीव मिश्र ने बताया कि पूर्व राज्यपाल रघुवर दास का सहज और सादगीपूर्ण व्यवहार परिवार को काफी प्रभावित कर गया। उन्होंने बताया कि मुलाकात के दौरान पुराने राजनीतिक अनुभवों और सामाजिक बदलावों पर भी चर्चा हुई। मेदिनीनगर प्रवास के दौरान रघुवर दास आढ़त रोड स्थित वरिष्ठ समाजसेवी अखिलेश अग्रवाल के आवास पर भी पहुंचे। यहां उन्होंने स्वर्गीय गोपाल जी अग्रवाल को याद किया, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने स्वयंसेवकों में शामिल थे। इस दौरान सामाजिक और वैचारिक विषयों पर भी चर्चा हुई।

पलामू में डिजिटल सेवाओं की समीक्षा, लापरवाही पर शो कॉज

मेदिनीनगर। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने मंगलवार को जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी की मासिक समीक्षा बैठक कर विभिन्न डिजिटल सेवाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), आधार नामांकन एवं अपडेट, झारनेट कनेक्टिविटी, ई-ग्रंथालय, झारसेवा के तहत प्रमाण पत्र निर्गत करने तथा विवाह निबंधन कार्यों की जानकारी ली गई। उपायुक्त ने कहा कि आमजनों को समयबद्ध और पारदर्शी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने और तकनीकी समस्याओं का जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। मनातू बीआरसी में आधार ऑपरेटर के कार्यरत नहीं रहने के मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित एजेंसी को शो कॉज जारी करने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिला शिक्षा अधीक्षक को सभी बीआरसी में अनिवार्य रूप से दो-दो आधार ऑपरेटर तैनात करने को कहा गया। बैठक में मास्टर सोबरन मांझी जिला पुस्तकालय को मॉडल लाइब्रेरी के रूप में विकसित करने तथा वहां बेहतर बिजली और सोलर सिस्टम उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की गई। बैठक में सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी रणवीर सिंह, जिला शिक्षा अधीक्षक संदीप कुमार समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

प्रखंड कार्यालय में लाखों की उपस्कर खरीद पर सवाल

● प्रमुख आभा रानी ने जताई फर्जीवाड़े की आशंका जांच की मांग

नवीन मेल संवाददाता

खरौंधी (गढ़वा)। प्रखंड प्रमुख आभा रानी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में प्रखंड कार्यालय के लिए खरीदे गए उपस्करों की खरीद प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मामले में फर्जीवाड़े की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रमुख ने आरोप लगाया कि वर्ष 2023-24 में लगभग तीन लाख रुपये की लागत से स्टील आलमारी, प्लास्टिक चेयर, एक्जीक्यूटिव टेबल एवं अन्य सामग्री की खरीद दिखाई गई है, लेकिन अधिकांश उपस्कर कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने बताया कि खरीद से संबंधित दस्तावेजों की जांच के दौरान कई विसंगतियां सामने आई हैं। प्रमुख के अनुसार अलग-अलग वित्तीय वर्षों के दस्तावेजों में तत्कालीन बीडीओ के हस्ताक्षरों में अंतर पाया गया है, जिससे संदेह और गहरा गया है। आभा रानी ने कहा कि तत्कालीन बीडीओ गणेश महतो से बातचीत में भी कथित रूप से फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर खरीद की बात सामने आई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में भी करीब तीन लाख रुपये की लागत से लैपटॉप, कार्टेज, कुर्सियां एवं अन्य सामग्री खरीदे जाने का उल्लेख है, लेकिन इनकी उपलब्धता स्पष्ट नहीं है। प्रमुख ने कार्यालय कर्मियों से खरीदे गए सभी उपस्करों को प्रस्तुत करने की मांग करते हुए कहा कि यदि स्थिति स्पष्ट नहीं हुई तो उपायुक्त गढ़वा से शिकायत की जाएगी। मौके पर बीडीसी विकास कुमार सिंह, कृष्णा राम सहित अन्य लोग मौजूद थे।

चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल में पलामू की दमदार मौजूदगी

● आठ फिल्मों का हुआ चयन, युवा फिल्मकारों की प्रतिभा को मिलेगा बड़ा मंच

नवीन मेल संवाददाता

मेदिनीनगर। झारखंड में क्षेत्रीय सिनेमा को नई पहचान दिलाने वाले चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल में इस बार पलामू की रचनात्मक प्रतिभा दमदार उपस्थिति दर्ज कराएगी। रांची स्थित सरला बिरला विश्वविद्यालय में 26 से 28 जून तक आयोजित होने वाले इस फिल्म महोत्सव में पलामू के फिल्मकारों द्वारा निर्मित आठ फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। चयनित फिल्मों में छह शॉर्ट फिल्म और दो डॉक्यूमेंट्री फिल्में शामिल हैं।
फिल्म फेस्टिवल आयोजन समिति के सदस्य नंद कुमार सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से चयनित फिल्मों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि झारखंड में फिल्म निर्माण की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि इस फेस्टिवल का उद्देश्य राज्य के युवाओं और स्थानीय फिल्मकारों को बेहतर मंच उपलब्ध कराना है।
जानकारी के अनुसार इस वर्ष फेस्टिवल के लिए झारखंड भर से कुल 84 फिल्मों की प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 67 फिल्मों को स्क्रीनिंग के लिए चयनित किया गया है। इनमें पलामू की आठ फिल्मों का चयन जिले के लिए गौरव की बात मानी जा रही है। फेस्टिवल में पलामू के फिल्मकारों द्वारा निर्मित दो डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का भी प्रदर्शन किया जाएगा।
आयोजन समिति के अनुसार तीन दिवसीय इस समारोह में फिल्म प्रदर्शन के साथ पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी आयोजित होगा, जिसमें कई नामचीन फिल्मी हस्तियों के शामिल होने की संभावना है।
फिल्म महोत्सव के दौरान एक विशेष स्मारिका का भी विमोचन किया जाएगा। स्मारिका समिति के सदस्य ने बताया कि इस प्रकाशन में पलामू की साहित्यिक और सिनेमाई रचनात्मकता की झलक देखने को मिलेगी।
फेस्टिवल के प्रचार-प्रसार को लेकर आयोजित रील मेकिंग प्रतियोगिता में भी पलामू के युवाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। नवोदित कलाकार प्रकाश संगम की रील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई।
चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल को लेकर पलामू के कलाकारों, फिल्मकारों और सिने प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। स्थानीय कलाकारों का मानना है कि ऐसे आयोजन क्षेत्रीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और झारखंडी सिनेमा को नई दिशा देने का कार्य करते हैं।

भाषा विवाद से लेकर भ्रष्टाचार तक, रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना

● पूर्व मुख्यमंत्री बोले- मोदी सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन और निर्णायक नेतृत्व के प्रतीक

● पूर्व मुख्यमंत्री ने झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज और निवेश नीति विफल करने का लगाया आरोप

● भाषा विवाद पर रघुवर दास का हमला, बोले- विरोध है तो कांग्रेस के मंत्री दें इस्तीफा

● जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान, महिला आरक्षण और सर्जिकल स्ट्राइक को बड़ी उपलब्धि बताया।

● भाजपा ने 2029 चुनाव की तैयारी तेज करने का दावा किया।

मेदिनीनगर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने मंगलवार को पलामू दौरे के दौरान एक निजी होटल में मीडिया संवाद के दौरान राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भाषा विवाद, भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज, निवेश नीति की विफलता, प्रश्नपत्र लीक और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद गठबंधन सरकार को कठघरे में खड़ा किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख करते हुए इसे देश के विकास, सुशासन और निर्णायक नेतृत्व का स्वर्णिम काल बताया।

भाषा विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए रघुवर दास ने कहा कि भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को सूची से बाहर करने का निर्णय कांग्रेस के चारों मंत्रियों की मौजूदगी में लिया गया था। अब वही मंत्री मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विरोध का दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस मंत्री वास्तव में इस निर्णय के विरोध में हैं तो उन्हें नैतिकता के आधार पर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है, लेकिन यहां पत्थर, कोयला और बालू सिंडिकेट सक्रिय हैं। राज्य का राजस्व विकास कार्यों में खर्च होने के बजाय सत्ता पक्ष के नेताओं के हित में जा रहा है। उन्होंने कहा कि 'तीन तिगाड़ा, काम बिगाड़ा' वाली कहावत झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन पर पूरी तरह लागू होती है। रघुवर दास ने कहा कि वर्तमान सरकार ने राज्य की निवेश नीति को पूरी तरह विफल कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में आयोजित 'मोमेंटम झारखंड' कार्यक्रम ने राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई थी। उस समय निवेशकों का भरोसा झारखंड पर बढ़ा था, लेकिन वर्तमान माहौल में उद्योगपति निवेश करने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और अस्थिर नीतियों के कारण राज्य में निवेश का वातावरण खराब हो गया है। उन्होंने राज्य में लगातार हो रही प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने अपने कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय शिक्षक, दरोगा, सिपाही समेत लाखों नियुक्तियां निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की गई थीं। आज युवाओं में सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश भ्रष्टाचार और घोटालों से जूझ रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने जवाबदेही और विकास आधारित राजनीति को स्थापित किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए कई ऐतिहासिक योजनाएं लागू कीं। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जनधन योजना, किसान सम्मान निधि, हर घर जल, स्वच्छ भारत मिशन और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। रघुवर दास ने दावा किया कि मोदी सरकार के प्रयासों से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल आंकड़ा नहीं बल्कि देश में हुए वास्तविक परिवर्तन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है।
राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई ने दुनिया में भारत की मजबूत छवि बनाई है। उन्होंने कहा कि देश में नक्सलवाद समाप्ति की ओर है और यह केंद्र सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति का परिणाम है।
रघुवर दास ने कहा कि मोदी सरकार सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने का भी कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि देश अपनी सांस्कृतिक विरासत और गौरव को पुनर्स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तीन तलाक समाप्त करना, राम मंदिर निर्माण और राष्ट्रहित में लिए गए कई बड़े फैसले इसके उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाजपा इसी संकल्प के साथ जनता के बीच काम कर रही है और पार्टी ने 2029 विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। इस अवसर पर पलामू के सांसद वीडी राम, विधायक आलोक चौरसिया, विधायक शशिभूषण मेहता, महापौर अरूणा शंकर, प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह, जिला अध्यक्ष अमित तिवारी, पूर्व विधायक पुष्पा देवी, पूर्व सांसद मनोज कुमार, विजयानंद पाठक, नरेन्द्र पांडेय, पूर्व जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह समेत कई वरिष्ठ भाजपाई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : डीडीसी

बरवाडीह। उप विकास आयुक्त सैयद रियाज अहमद मंगलवार को बरवाडीह प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न विभागों के कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान आयोजित समीक्षा बैठक में बीडीओ, अंचलाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कल्याण पदाधिकारी, एई, जेई तथा पंचायत सचिव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। डीडीसी ने सभी विभागों के लंबित कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अगले 15 दिनों के भीतर कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान बरवाडीह पंचायत के पंचायत सेवक विजय शंकर पर ग्रामीणों द्वारा लगाए गए रुपये लेने के आरोपों पर भी चर्चा हुई। इस मामले में डीडीसी ने संबंधित पंचायत सेवक को शोकॉज जारी करते हुए कहा कि आरोपों की गंभीरता से जांच कराई जा रही है। जांच में दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला परिषद योजनाओं में कथित लापरवाही के संबंध में पूछे गए सवाल पर डीडीसी ने कहा कि अब तक कोई आधिकारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि भविष्य में शिकायत मिलती है तो स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाएगी तथा संवेदक की लापरवाही सामने आने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को जनहित से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर समय पर पूरा करने तथा कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। डीडीसी ने कहा कि विकास कार्यों का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचना चाहिए।

दृष्टिपात

सरस्वतीया नदी सफाई अभियान 17वें दिन भी जारी

मेराल। आपन सरस्वतीया नदी सफाई अभियान के तहत मंगलवार को सत्रहवें दिन भी सफाई कार्य जारी रहा। मेराल पश्चिमी वर नदी छठ घाट पर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संगठन के सहयोग से जेसीबी मशीन लगाकर सफाई की गई। अभियान में समाजसेवी, जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी स्वेच्छा से एक-एक दिन के लिए जेसीबी मशीन उपलब्ध कराकर सहयोग कर रहे हैं। अभियान गढ़वा एसडीएम संजय कुमार पांडेय के मार्गदर्शन एवं प्रभारी बीडीओ सह सीओ यशवंत नायक के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार चल रहे अभियान से अपना अस्तित्व खो चुकी सरस्वतीया नदी अब धीरे-धीरे पुराने स्वरूप में लौटती दिख रही है। मानसून से पहले सफाई कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके कारण अभियान तेज गति से चलाया जा रहा है। अभियान में विधायक प्रतिनिधि डॉ. लालमोहन, पूर्व जिप सदस्य संजय भगत, भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनोज जायसवाल, पत्रकार यासीन अंसारी एवं विवेकानंद चौबे लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। मंगलवार को अजय तिवारी, विष्णु यादव, डॉ. नईम अंसारी, लैब टेक्नीशियन राजू कुमार सहित कई लोगों ने अभियान में सहयोग किया।

राज्यस्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अर्पणा ने जीता सिल्वर

मेराल। एसजीएन मॉडर्न किंडर गार्टन विद्यालय की छात्रा अर्पणा कुमारी ने राज्यस्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया है। 13 से 15 जून तक सरायकेला-खरसावां में आयोजित बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अर्पणा ने 49 से 61 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया। उनका चयन गढ़वा जिला बॉक्सिंग टीम में किया गया था। विद्यालय के निदेशक धर्मेंद्र देव ने छात्रा की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि विद्यालय में मिशन ओलंपिक को ध्यान में रखकर बॉक्सिंग सहित विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगा है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी विद्यालय की छात्राओं ने वूमेन्स बॉक्सिंग लीग चैंपियनशिप में पदक जीतकर प्रखंड और जिले का सम्मान बढ़ाया था। धर्मेंद्र देव ने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। इसके लिए खेल और अन्य गतिविधियों को भी समान महत्व दिया जा रहा है। अर्पणा की इस सफलता पर विद्यालय परिवार एवं क्षेत्र के लोगों ने खुशी जताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

विद्यालय प्रबंधन समितियों के पुनर्गठन का कार्यक्रम जारी

खरौंधी (गढ़वा)। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी विजय पांडेय ने प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) के पुनर्गठन एवं गठन को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया है। जिन विद्यालयों की समिति का कार्यकाल पूरा हो चुका है, वहां निर्धारित तिथियों पर आमसभा आयोजित कर नई समिति का गठन किया जाएगा। निर्देश के अनुसार विद्यालयों को अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों को पूर्व सूचना देकर अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। कार्यक्रम के तहत उत्क्रमित मध्य विद्यालय चंदनी, कन्या मध्य विद्यालय तोरेलावा तथा नव प्राथमिक विद्यालय चिनियाही में 17 जून को समिति का पुनर्गठन होगा। वहीं उत्क्रमित मध्य विद्यालय चौरिया एवं उच्च विद्यालय तोरेलावा में 18 जून को आमसभा के माध्यम से नई समिति का गठन किया जाएगा। इसके अलावा पीएम श्री मध्य विद्यालय भलुही में 19 जून तथा पीएम श्री मध्य विद्यालय अरंगी में 22 जून को विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बीईईओ विजय पांडेय ने कहा कि विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय के सर्वांगीण विकास, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार तथा समुदाय और विद्यालय के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने सभी विद्यालयों को पारदर्शी एवं नियमसम्मत तरीके से समिति गठन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि समिति गठन के साथ-साथ सरस्वती वाहिनी माता समिति का भी पुनर्गठन किया जाएगा। साथ ही पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर बीआरसी कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। कार्यक्रम जारी होने के बाद संबंधित विद्यालयों में तैयारियां शुरू हो गई हैं तथा अभिभावकों को आमसभा में शामिल होने के लिए सूचना दी जा रही है।

मतदाता सूची पुनरीक्षण में तेजी, 83 प्रतिशत मैपिंग कार्य पूरा

केतार। निर्वाचन नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रखंड क्षेत्र में मतदाता सत्यापन एवं मैपिंग कार्य तेजी से चल रहा है। अब तक 83 प्रतिशत मतदाताओं का मैपिंग कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि शेष मतदाताओं का सत्यापन युद्धस्तर पर जारी है। जिन मतदाताओं का मैपिंग कार्य अब तक नहीं हो पाया है, उनके घर-घर जाकर बीएलओ द्वारा सत्यापन किया जा रहा है। निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए क्षेत्र से बाहर पलायन कर चुके, मृत एवं संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की भी जांच की जा रही है। जांच के बाद ऐसे मतदाताओं की एएसडी (एब्सेंट, शिफ्टेड एंड डेड) रिपोर्ट तैयार की जा रही है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 20 जून से 29 जून तक प्रशिक्षण एवं आवश्यक सामग्री का मुद्रण कार्य होगा। इसके बाद 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। 29 जुलाई को मतदान केंद्रों का रेशनलाइजेशन किया जाएगा। वहीं 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा एवं आपत्तियां ली जाएंगी। दावों और आपत्तियों का निपटारा 3 अक्टूबर तक किया जाएगा। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

आवास दिलाने के नाम पर गरीब से रुपये वसूलने का आरोप

भवनाथपुर। बुका गांव निवासी देवनंदन पासवान ने पंचायत एवं प्रखंड कर्मियों पर आवास योजना में अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रुपये लेने के बावजूद उन्हें अबुआ आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। देवनंदन पासवान ने बताया कि वर्ष 2023-24 में उनकी पत्नी उर्मिला देवी का नाम अबुआ आवास योजना की सूची में आया था, लेकिन अब तक आवास स्वीकृत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उनका परिवार जर्जर मिट्टी के मकान में रहने को मजबूर है। बरसात में छत से पानी टपकता है और गर्मी में तिरपाल लगाकर किसी तरह गुजारा करना पड़ता है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आवास दिलाने के नाम पर पंचायत सेवक नवनीत कुमार ने पांच हजार रुपये लिए। वहीं जियो टैगिंग के नाम पर रोजगार सेवक द्वारा चार किस्तों में दो हजार रुपये लिए गए। इसके बावजूद लाभ नहीं मिला। देवनंदन ने कहा कि कई बार कार्यालय का चक्कर लगाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले से आवास लाभ ले चुके लोगों का नाम दोबारा सूची में शामिल कर लिया गया है। ग्रामीणों ने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई तथा पीड़ित को शीघ्र आवास उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं पंचायत सेवक नवनीत कुमार ने रुपये लेने के आरोप को निराधार बताया है। इस संबंध में बीडीओ नंदजी राम ने कहा कि आवेदन मिलने पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

नेपाल खोह के पास सड़क हादसा, दो घायल

केतार। नेपाल खोह के समीप मंगलवार को हुए सड़क हादसे में केतार प्रमुख प्रतिनिधि सुरेंद्र प्रसाद एवं झामुमो नेता उदय प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में चिंता का माहौल बन गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों मोटरसाइकिल से बंशीधर नगर व्यवहार न्यायालय जा रहे थे। इसी दौरान नेपाल खोह के पास बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों की मदद से घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल बंशीधर नगर पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मेदिनीनगर रेफर कर दिया। बताया गया कि सुरेंद्र प्रसाद के सीने और माथे में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि उदय प्रसाद भी घायल हुए हैं।

झारजल पोर्टल की समीक्षा में सख्त दिखे उपायुक्त

लंबित शिकायतों के त्वरित निष्पादन व निर्बाध पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

नवीन मेल संवाददाता

गढ़वा। जिले में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और आमजनों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को लेकर उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारजल पोर्टल की समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारी तथा संबंधित कर्मी शामिल हुए। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने ग्रीष्म ऋतु में निर्बाध पेयजलापूर्ति को प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए सभी अधिकारियों को क्षेत्रवार लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि संभावित पेयजल संकट से निपटने के लिए प्रखंड स्तर पर मिस्त्री, मुखिया, पंचायत सचिव, कनीय अभियंता एवं अन्य कर्मियों के साथ नियमित समन्वय बनाए रखा जाए। बैठक में बताया गया कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा झारजल पोर्टल के माध्यम से पेयजल संबंधी शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। आमजन टोल फ्री नंबर 1800-3456-502, मोबाइल एप, व्हाट्सएप नंबर 9470176901 और ई-मेल के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कार्यपालक अभियंता अजय कुमार सिंह ने बताया कि 16 जून 2026 तक कुल 1826 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 1632 मामलों का निष्पादन कर दिया गया है। शिकायतें चापाकल मरम्मत, जलापूर्ति योजना, पाइपलाइन लीकेज, पेयजल संकट, जल गुणवत्ता और स्वच्छता से संबंधित हैं। उन्होंने बताया कि 25 शिकायतें वापस ले ली गई हैं, जबकि 108 मामलों में कार्रवाई जारी है। वहीं 50 शिकायतें विभागीय स्तर पर लंबित हैं। इसके अलावा विभिन्न बीडीओ लॉग-इन में 241 मामले दर्ज हैं, जिनमें 213 का निष्पादन किया जा चुका है। बैठक में जिला प्रशासन ने आमजनों से अपील की कि पेयजल संबंधी समस्या होने पर झारजल पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराएं, ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। प्रशासन ने कहा कि प्रत्येक नागरिक तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

खराब पड़े चापाकलों की शीघ्र मरम्मत कराकर उन्हें चालू कराने के निर्देश

लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए उपायुक्त ने सभी बीडीओ को व्यक्तिगत रूप से समीक्षा कर प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निष्पादित मामलों की अद्यतन रिपोर्ट कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराई जाए, ताकि मुख्यालय को समय पर समेकित प्रतिवेदन भेजा जा सके। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मुखिया एवं पंचायत सचिवों के साथ समन्वय बनाकर खराब पड़े चापाकलों की जानकारी लें और शीघ्र मरम्मत कराकर उन्हें चालू कराएं। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग की राशि से आवश्यकता के अनुसार नए चापाकल भी लगाए जाएंगे।

पुलिस चौपाल में ग्रामीणों को किया गया जागरूक

चिनिया। थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांव परशुखाड़ में मंगलवार को पुलिस द्वारा जन-जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी बीकू कुमार रजक ने किया। इस दौरान ग्रामीणों को सड़क सुरक्षा नियमों, नशामुक्ति, डायल-112 सेवा, डायन-भूत जैसी कुरीतियों से बचाव, महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम तथा बाल विवाह निषेध कानून की जानकारी दी गई। थाना प्रभारी बीकू कुमार रजक ने कहा कि समाज में फैली कुरीतियों और अपराधों के खिलाफ जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने लोगों से किसी भी आपात स्थिति में तत्काल डायल-112 पर सूचना देने की अपील की। उन्होंने ग्रामीणों से नशे से दूर रहने तथा बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने में प्रशासन का सहयोग करने का आह्वान किया। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला-पुरुष उपस्थित रहे। थाना के सशस्त्र बल के जवान भी कार्यक्रम में शामिल हुए। ग्रामीणों ने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए ऐसे कार्यक्रम गांव-गांव तक चलाने की मांग की।

मनरेगा कर्मियों को 24 घंटे में काम पर लौटने का निर्देश

नवीन मेल संवाददाता

गढ़वा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कार्यों में आ रही बाधा को लेकर उप विकास आयुक्त प्रेमलता मुर्मू ने जिले के हड़ताली मनरेगा कर्मियों को 24 घंटे के भीतर कार्यस्थल पर लौटने का निर्देश दिया है। डीडीसी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मार्च 2026 से मनरेगा कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन और ग्रामीणों को समय पर रोजगार उपलब्ध कराने में गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। लेकिन कर्मियों की हड़ताल के कारण योजनाओं के संचालन और मानव-दिवस सृजन का लक्ष्य प्रभावित हुआ है। उप विकास आयुक्त ने बताया कि विभागीय निर्देशों और पूर्व में जारी आदेशों के बावजूद कई कर्मी अब तक कार्य पर वापस नहीं लौटे हैं। इससे मार्च, अप्रैल और मई 2026 के निर्धारित लक्ष्य पर प्रतिकूल असर पड़ा है। डीडीसी प्रेमलता मुर्मू ने स्पष्ट किया कि सभी हड़ताली कर्मियों को 24 घंटे के भीतर सेवा में योगदान देना होगा। निर्धारित समय सीमा के बाद भी कार्य पर नहीं लौटने वाले कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी मनरेगा कर्मियों से ग्रामीण हित और विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए जल्द कार्य पर लौटने तथा योजनाओं के सफल संचालन में सहयोग करने की अपील की है।

कार्यालय- उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार
(जिला ग्रामीण विकास शाखा)

विज्ञापन संख्या– 01/2026

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत प्रखण्ड स्तर पर गठित PMU में नियुक्ति संबंधी सूचना।

सरकार के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रांची के अधिसूचना संख्या–1016(अनु0) ग्रा0 वि0–10–PMAY-G-54/2016 रांची दिनांक 01.03.2017 ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण सफल संचालन हेतु प्रखण्ड स्तर पर गठित PMU के रिक्त पदों पर पूर्णतया संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आमंत्रण किया जाता है। रिक्त पदों की विवरणी निम्नवत है :–

क्र0 सं0	पद का नाम	रिक्ति की संख्या	कोटि	शैक्षणिक योग्यता	मासिक मानदेय
01	प्रखण्ड समन्वयक	02	अ0ज0जा0–01 आ0क0वर्ग–01	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/ को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उर्त्तीण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उर्त्तीण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव।	18,000/–
02	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	02	अ0ज0जा0–01 आ0क0वर्ग–01	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उर्त्तीण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ छः माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।	10,000/–

नोट :–
(I). उपरोक्त कोटिवार रिक्तियों की संख्या भविष्य में घट–बढ़ सकती है।
(II). नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण नीति ही मान्य होगी।
1. आवेदक के द्वारा दिनांक 24.06.2026 से दिनांक 09.07.2026 के अपराह्न 5:00 बजे तक विभागीय वेबसाईट https://applyrdd.jharkhand.gov.in पर केवल Online आवेदन स्वीकार किया जायेगा।
2. आवेदन हेतु रिक्त पदों के वांछित योग्यता सहित अन्य विस्तृत जानकारी लातेहार जिला के वेबसाईट https://latehar.nic.in पर तथा उप विकास आयुक्त, लातेहार के कार्यालय के सूचना पट्ट में देखा जा सकता है।

PR 382470 Rural Development (26-27)_D — उपायुक्त, लातेहार

न्यायालय, उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी, लातेहार

अनुमति वाद संख्या–39/2026
आम इस्तेहार

आवेदक सरीफ मियां वो सतलू मियां दोनों के पिता–स्व0 खोदावक्स मियां वो जाहेदा बीबी पति–स्व0 करीमन मियां वो यशोदा बीबी पति–स्व0 मुदा मियां उर्फ स्व0 महमूद मियां, सभी निवासी ग्राम+पो0–चकला, थाना–चन्दवा, जिला–लातेहार द्वारा मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्री लि0, 21वीं मंजिल प्रथम अंतराष्ट्रीय केन्द्र टॉवर–4, प्रभादेवी, प्रभादेवी रेलवे स्टेशन के पास सेनापति बापत मार्ग, मुम्बई–400013 वर्तमान पता–ग्राम+पो0–चकला, थाना–चन्दवा, जिला–लातेहार के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति के लिए छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 के अंतर्गत आवेदन पत्र दाखिल किया है।

भूमि का विवरण

मौजा	खाता	प्लॉट	रकबा (एकड़)
चकला	34	1304	0.64

एतद् द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि इस भूमि अंतरण के विरूद्ध किसी को आपत्ति हो, तो स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय में आम–इस्तेहार निर्गत की तिथि से एक पक्ष (15 दिनों) के अंदर आपत्ति दायर कर सकते है। समय सीमा समाप्ति के बाद प्राप्त आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रभारी उप समाहर्त्ता, विधि शाखा, लातेहार

PR 382480 (District)26-27*D

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, लातेहार
Email- rdsd.latehar@rediffmail.com

पत्रांक –................../ग्रा0वि0वि0प्र0, लातेहार, दिनांक– ....

प्रेस विज्ञप्ति

एतद् द्वारा श्री आयुष कुमार, महुआडाड़ लातेहार जिला लातेहार झारखण्ड को सूचित किया जाता है कि जिला समाज कल्याण मद अन्तर्गत **प्रखण्ड महुआडाड़ पंचायत ओरसा ग्राम कुकुद पाट में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण कार्य** जिसका एकरारनामा संख्या F2 78/24-25 दिनांक–21.02.2025 है। आपको निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु बार बार स्मार पत्र दिया गया है, परन्तु आपके द्वारा एक वर्ष बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। एवं आपके द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कराने में रूचि नहीं ली जा रही है।

अतः आपको इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अंतिम बार निर्देश दिया जाता है कि निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा बाध्य होकर संवेदक नियमावली के 11.1.4 के तहत आपके एकरारनामा को रद्द करते हुए आपके फॉर्म को काली सूची में डालने की अनुशंसा कर दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगें।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल,लातेहार

PR 382475 Rural Development(26-27).D

न्यायालय, उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी, लातेहार

अनुमति वाद संख्या–41/2026
आम इस्तेहार

आवेदक भोला राम पिता–स्व0 भगवान राम, निवासी ग्राम–हरखा, पो0–मोंगर, थाना+जिला–लातेहार द्वारा संजीव कुमार पिता–राजकुमार प्रसाद, ग्राम+पो0–लातेहार, थाना+जिला–लातेहार के साथ भूमि बिक्री के लिए अनुमति हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा– 46(1–बी) के अंतर्गत आवेदन पत्र दाखिल किया है।

भूमि का विवरण

मौजा	खाता	प्लॉट	रकबा
हरखा	39	505	0.66 ए0

एतद् द्वारा हर आम व खाश को सूचित किया जाता है कि इस भूमि अंतरण के विरूद्ध किसी को आपत्ति हो, तो स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय में आम–इस्तेहार निर्गत की तिथि से एक पक्ष (15 दिनों) के अंदर आपत्ति दायर कर सकते है। समय सीमा समाप्ति के बाद प्राप्त आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

PR.NO.382481 District(26-27):D — प्रभारी उप समाहर्त्ता, विधि शाखा, लातेहार।

District AYUSH Society, Latehar
Advt.- 01/2026
Annexure – III
Recruitment Notice
Recruitment for DPMU cell on contract basis at District AYUSH Society, Latehar

National AYUSH Mission (NAM), Jharkhand, is committed to provide accessible, affordable and accountable quality health services to the last person of the last household at the last village. The thrust is on establishing a fully functional, community owned, decentralized health delivery system with Intersectoral convergence at all levels, to ensure simultaneous action on & wide range of health determinants such as water, sanitation, education, nutrition, social and gender equality.

NAM, Jharkhand, is seeking online applications from eligible candidates for the flowing position for District AYUSH Society, Latehar Govt. of Jharkhand: -

Sl. No.	Name of Post	Number of Post	Remuneration (Rs. /Month)	Qualification & Eligibility Criteria
01.	District Programme Manager	01 (UR)	50000/-	**Essential Minimum Qualification:** Graduation degree in any discipline including AYUSH and MBA in Healthcare Management/Masters in Health/ Hospital Administration/ Post Graduation diploma in Hospital & Healthcare Management (Two Years) from AICTE Recognized institute. **Essential Minimum Experience:** Minimum 01 Year working Experience in public health programme. Exposure in social sector Schemes/ Missions at National, State and District level. **Required Minimum Competencies:** Computer knowledge including MS Office, MS Word, MS Power point and MS Excel would be desirable. **Note:** Preference will be given to person having experience of working in health sector including AYUSH.

Term of Engagement:
1. Contractual employment will be made for 01 year from the date of appointment. However, contract May be extended or terminated on the basis of Satisfactory/unsatisfactory services without any notice.
2. **Age limit:** Minimum - 21 years Maximum 59 year as on 30th June 2026.
3. **Last Date for Receiving the Application** is 3rd July 2026, Application received after last Date/Time will be refused/rejected.
4. The successful Candidates will be required to execute contractual Agreement and their service Guided by the service rule of National Ayush mission.
5. **How to apply:** Go to website http:// latehar.nic.in & Download the form and apply and fill the form(offline Mode) along with the required documents and make the **payment through DD** (i.e. 1000/- for each application) on the behalf of **JILA AYUSH CHIKITSA PADADHIKARI, LATEHAR Payable at LATEHAR.** Bank Name- Canara Bank, Branch-Latehar.
   Form Submission by Registered Post/Speed Post Location:- DAMO, Office, AYUSH Bhawan, District Joint Dispensary (Office), Latehar, Sadar Hospital Campus, Latehar, Jharkhand. PIN Code- 829206. And Last date for Submission is : 3rd July 2026 till 05:00PM.
6. **Required Documents:**
   I. Aadhar Card
   II. PAN Card
   III. Photograph (Passport size)
   IV. 10th Marksheet
   V. 12th Marksheet
   VI. Semester wise Marksheet of BAMS/ BHMS/ BUMS/ BSMS/ BYNS/ M. Com/ C.A/ ICWA(Inter)/ CA(Inter)/ another Graduation Degree/ MBA.
   VII. Degree Certificate
   VIII. Experience Certificate
   IX. Residential Certificate (if applicable) which should not be older than 06 Month before than last date of Application.
7. For the posts of District Programme Manager Sort listed candidates would be called for document verification and personal interview on the date, time and place communicated to them through website. Personal interview will be conducted under the Chairmanship of Deputy Commissioner.
   Note: If number of applicants increases considerably then Written Exam may be conducted by authority.
8. List Of selected candidates Published on website.
9. The selected candidates will get an annual enhancement of 03% based on satisfactory performance to be decided by the performance assessment committee of AYUSH.
10. **Leave -** The selected candidates will get maximum 18 day leave during a calendar year.
11. The District AYUSH society reserves the right to cancel, postpone the recruitment wholly or partly If so Required.
12. Canvassing in any form either for selection or for place of posting will result in cancellation of the candidature of the applicants.
13. For more details, please visit Annexure – I & Annexure – II.

Responsibilities of DPM(AYUSH):
- To provide support for planning and implementation of National AYUSH Mission including AYUSH Health and Wellness Centres in the District.
- Preparation and finalization of District Annual Action Plan of National Ayush Mission in coordination with relevant programme divisions.
- Pursue with District Authorities and different implementing agencies to roll out the Approved activities of State Annual Action Plan.
- Furnishing relevant documents related to SAAP to the State/Ministry well within time.
- Maintenance of district wise profile of AYUSH.
- Maintenance and submission after cross-verification of the financial Sanctions, expenditure as well as utilization certificates submitted to State with the support Data Entry Operator Working under PMU.
- Data validation of all the information uploaded on the National AYUSH Mission Website with the support of Data Entry Operator.
- Time to time filled visits to monitor different activities approved under National AYUSH Mission.
- To provide relevant information time to time to State/Govt. of India as per the recruitment regarding Parliament Questions, Parliament assurances, Parliament Standing committee etc.
- To maintain and share with State/GOI a database of all the officers/officials dealing with National AYUSH Mission Scheme.
- To liaison with Officers and State Programme Management unit Manpower of National AYUSH Mission division as required.
- To facilitate 3rd party evaluation team/ central Monitoring team etc as and when required.
- Any other work assigned by officers of the State Govt. time to time.

PR 382459 Health Med Edu and Family Welfare(26-27)D — District Ayush Society,Latehar

दृष्टिपात

सड़कों पर सवारी उतारने या बैठाने पर कटेगा चालान

लातेहार। नगर पंचायत क्षेत्र में बस एवं ऑटो चालकों को अपने निर्धारित स्टैंड में ही वाहन खड़ा करने और यात्रियों को चढ़ाने-उतारने का निर्देश दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित वाहनों का चालान काटकर जुर्माना वसूला जाएगा। मंगलवार को डीटीओ उमेश कुमार मंडल और कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन की संयुक्त अध्यक्षता में नगर पंचायत कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में बस मालिक, एजेंट, टेंपो चालक तथा बस स्टैंड के संवेदक मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिया कि बसों को धर्मपुर स्थित बस स्टैंड में ही खड़ा किया जाए और वहीं से यात्रियों को बैठाया या उतारा जाए। थाना चौक, धर्मपुर चौक, सर्किट हाउस समेत अन्य सड़कों पर बसों के ठहराव पर कार्रवाई की जाएगी। ऑटो चालकों को भी सख्त हिदायत देते हुए कहा गया कि सड़क किनारे वाहन खड़ा करने से जाम की समस्या उत्पन्न होती है। उन्हें थाना चौक स्थित नगर पंचायत कार्यालय रोड के ऑटो स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन स्थित ऑटो स्टैंड में ही वाहन लगाने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नियमों का पालन अनिवार्य है। बैठक में नगर प्रबंधक जया लक्ष्मी भगत, राजकुमार वर्मा, कलंदर आजाद, संतोष कुमार सिंह, योगेंद्र प्रसाद, अयोध्या प्रसाद जायसवाल सहित कई लोग उपस्थित थे।

मोहर्रम को लेकर महुआडांड़ में जोरदार तैयारी

महुआडांड़ (लातेहार)। आगामी मोहर्रम पर्व को ऐतिहासिक भव्यता, आपसी भाईचारे और अनुशासन के साथ मनाने को लेकर महुआडांड़ में तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में सोमवार को छोटी मस्जिद परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सेक्रेटरी मजहर खान ने की। बैठक में सर्वसम्मति से मोहर्रम कमेटी का गठन किया गया। उपस्थित लोगों ने युवा समाजसेवी तनवीर अहमद उर्फ रिंकू को खलीफा (अध्यक्ष) तथा सद्दाम आलम उर्फ शेरू को नायब खलीफा (उपाध्यक्ष) चुना। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का फूल-मालाओं से स्वागत किया गया। बैठक में ताजिया, मातमी जुलूस, मजलिस, सबील और लंगर समेत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। जुलूस के रूट, समय-सारणी, साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन को लेकर रणनीति बनाई गई। खलीफा तनवीर अहमद ने कहा कि मोहर्रम इंसानियत, सब्र और हक की राह पर चलने का पैगाम देता है। सेक्रेटरी मजहर खान ने युवाओं से अफवाहों से दूर रहने और स्वयंसेवक बनकर जुलूस की व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की। बैठक में पूर्व सदर फहीम खान, इस्तियाक अहमद, रानू खान, नुरुल हसन अंसारी, शहाबुद्दीन खान, अलाउद्दीन अंसारी, फिरोज अंसारी, बशारत अली, रूहुल अमीन, मो. साजिद, अनीस अंसारी, जमील अख्तर, शमशाद आलम और नसीम अंसारी सहित बड़ी संख्या में उलेमा, बुद्धिजीवी एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कमेटी ने निर्णय लिया कि जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल अनुमंडल पदाधिकारी और थाना प्रभारी से मिलकर जुलूस मार्ग की साफ-सफाई, अतिक्रमण हटाने तथा पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती को लेकर ज्ञापन सौंपेगा।

विद्यालय से चोरी हुई सोलर प्लेट बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

प्रतापपुर (चतरा)। थाना क्षेत्र के ग्राम लिदीक स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में हुई सोलर प्लेट चोरी की घटना का प्रतापपुर पुलिस ने त्वरित उद्भेदन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई तीनों सोलर प्लेट भी बरामद कर ली हैं। जानकारी के अनुसार, 13 जून 2026 की रात अज्ञात चोरों ने विद्यालय भवन की छत पर लगे तीन सोलर प्लेट चोरी कर लिए थे। घटना के बाद विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने प्रतापपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर प्रतापपुर थाना कांड संख्या 57/2026 दिनांक 14 जून 2026 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(2) एवं 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी आलोक रंजन चौधरी के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन कर लगातार छापेमारी अभियान चलाया गया। जांच के दौरान पुलिस ने बभने तालाब के समीप छापेमारी कर विनय कुमार, पिता द्वारिका यादव, निवासी परहियाडीह, थाना प्रतापपुर, जिला चतरा को चोरी किए गए तीनों सोलर प्लेट के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं इस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। चोरी गई सरकारी संपत्ति की शीघ्र बरामदगी पर स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यशैली की सराहना की है। थाना प्रभारी आलोक रंजन चौधरी ने कहा कि मामले में संलिप्त किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा तथा शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा।

मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक आज

चंदवा। आगामी मुहर्रम पर्व को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर बुधवार 17 जून को चंदवा थाना परिसर में प्रखंड स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक अपराह्न 4 बजे अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, लातेहार की अध्यक्षता में आयोजित होगी। इसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, पंचायतीराज जनप्रतिनिधि, मीडिया कर्मी, समाजसेवी एवं प्रबुद्धजनों को आमंत्रित किया गया है। पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि बैठक में मुहर्रम पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, जुलूस मार्ग, यातायात नियंत्रण एवं आपसी सौहार्द बनाए रखने सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।

ओएएसपीएल गेट पर दूसरे दिन भी जारी रहा आंदोलन

- पांच घंटे चली वार्ता बेनतीजा, कर्मी एकमुश्त बहाली की मांग पर अड़े

नवीन मेल संवाददाता

चंदवा। अभिजीत ग्रुप पावर प्लांट का संचालन कर रही ओएएसपीएल (रश्मि मेटेलिक्स ग्रुप) के खिलाफ मेनपावर कर्मियों और विस्थापित रैयतों का अनिश्चितकालीन आंदोलन मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। बचे हुए कर्मियों की बहाली की मांग को लेकर आंदोलनरत कर्मी और ग्रामीण अपनी मांगों पर डटे रहे। मंगलवार को स्थानीय प्रशासन की पहल पर आंदोलनकारियों और कंपनी प्रबंधन के बीच वार्ता कराई गई। वार्ता में प्रबंधन के अधिकारी, पुनि सह थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह, प्रशासनिक प्रतिनिधि, मेनपावर कर्मी और प्रभावित ग्रामीण शामिल हुए। करीब पांच घंटे तक चली बातचीत के बावजूद कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल सका। आंदोलनकारियों का कहना है कि मार्च माह में हुए लिखित समझौते के तहत सभी मेनपावर कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से बहाल करने का आश्वासन दिया गया था। प्रथम चरण में लगभग 120 कर्मियों को नौकरी पर रखा गया, लेकिन शेष करीब 50 कर्मियों की बहाली अब तक नहीं हो सकी है। कर्मियों ने आरोप लगाया कि बार-बार मांग उठाने के बावजूद प्रबंधन केवल आश्वासन देता रहा और बहाली प्रक्रिया को टालता रहा। वार्ता के दौरान आंदोलनरत कर्मी सभी शेष कर्मियों की एकमुश्त बहाली की मांग पर अड़े रहे, जबकि प्रशासन और प्रबंधन की ओर से शेष कर्मियों की सेवा बहाली तीन चरणों में करने का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि आंदोलनकारियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण वार्ता बेनतीजा समाप्त हो गई। आंदोलन में संजीव कुमार, चंद्रदेव उरांव, दिनेश उरांव, साम्बीर उरांव समेत बड़ी संख्या में मेनपावर कर्मी और ग्रामीण मौजूद रहे। आंदोलन के दूसरे दिन भी प्लांट गेट पर प्रदर्शन जारी रहने से क्षेत्र में स्थिति चर्चा का विषय बनी रही।

कुएं से सोलर समर्सिबल मोटर की चोरी

हंटरगंज (चतरा)। जिले के हंटरगंज प्रखंड की पाण्डेयपुरा पंचायत अंतर्गत पचमो गांव में समर्सिबल मोटर चोरी होने की घटना से ग्रामीणों और किसानों में दहशत का माहौल है। चोरी की इस घटना के बाद क्षेत्र के किसान अपनी सिंचाई व्यवस्था को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। पचमो गांव निवासी सनोज यादव ने आवेदन देकर बताया कि उन्होंने अपने कुएं में कुसुम सोलर योजना के तहत तीन एचपी का समर्सिबल मोटर लगाया था, जिससे वे प्रतिदिन खेतों की सिंचाई करते थे। उन्होंने बताया कि 14 जून की शाम रोज की तरह मोटर बंद कर घर चले गए थे। अगले दिन सुबह जब वह मोटर चालू करने के लिए कुएं पर पहुंचे तो देखा कि मोटर से जुड़ा पाइप बाहर निकाला हुआ पड़ा है और कुएं में लगा समर्सिबल मोटर गायब है। पीड़ित किसान ने घटना की लिखित सूचना पाण्डेयपुरा पुलिस पिकेट एवं हंटरगंज थाना को दे दी है।

5 करोड़ की सड़क योजना में भारी अनियमितता का आरोप

- प्राक्कलन को दरकिनार कर सीधे जीएसबी कार्य शुरू करने से गुणवत्ता पर उठे सवाल

नवीन मेल संवाददाता

बरवाडीह। प्रखंड मुख्यालय अंतर्गत चमरडीहा रेलवे गेट से लंका होते हुए मंगरा रोड तक लगभग पांच करोड़ रुपये की लागत से चल रहे पीसीसी एवं कालीकरण सड़क निर्माण कार्य में भारी अनियमितता का मामला सामने आया है। निर्माण कार्य में स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं किए जाने से गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण से पहले की जाने वाली अनिवार्य प्रक्रियाओं की अनदेखी की जा रही है। बताया गया कि सड़क के ऊपरी हिस्से को कहीं-कहीं जेसीबी मशीन से उखाड़कर वहीं छोड़ दिया गया है, जबकि नियमानुसार सड़क भूमि की पूर्ण सफाई (क्लियरिंग एंड ग्रबिंग) तथा निकाली गई अनुपयोगी सामग्री का निर्धारित स्थल पर निस्तारण किया जाना चाहिए था। ग्रामीणों के अनुसार 150 मिमी मोटाई तक की ऊपरी जैविक मिट्टी हटाने एवं उसके उचित निस्तारण की प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई। सबसे गंभीर आरोप यह है कि सबग्रेड को मजबूत बनाने के लिए मूल भूमि का कॉम्पैक्शन किए बिना सीधे जीएसबी कार्य शुरू कर दिया गया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण एजेंसी द्वारा प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं कर केवल कागजी खानापूर्ति की जा रही है, जबकि प्रारंभिक कार्यों के लिए लाखों रुपये का प्रावधान है। इससे सड़क की गुणवत्ता और स्थायित्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों एवं संवेदक पर कार्रवाई की मांग की है।

पीएम आवास दिलाने के नाम पर वसूली का आरोप

नवीन मेल संवाददाता

लातेहार। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत मुरपा पंचायत के जिपूवा गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने योजना की लाभार्थी सूची में अनियमितता और अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए उपायुक्त को आवेदन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि योजना की जारी सूची में कई वास्तविक जरूरतमंद और आवासहीन परिवारों का नाम शामिल नहीं किया गया, जबकि पूर्व में लाभ प्राप्त कर चुके अथवा पहले से सूचीबद्ध लोगों के नाम दोबारा दर्ज कर दिए गए हैं। इससे पात्र लाभुक योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने आवेदन में आरोप लगाया है कि पंचायत सचिव महेश मुंडा द्वारा करीब 30 ग्रामीणों से 500-500 की राशि ली गई। वहीं बिचौलियों के रूप में नामित बबलू यादव, उमेश प्रजापति एवं सत्येंद्र यादव पर भी किसी से 3000 तो किसी से 5000 तक वसूली करने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई पात्र परिवार आज भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं और सभी मानदंडों को पूरा करने के बावजूद योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण संजू देवी ने बताया कि वर्ष 2025 में आवास योजना में नाम जोड़ने के नाम पर पैसे लिए गए थे, लेकिन आज तक आवास नहीं मिला। इस संबंध में पूछने पर पंचायत सेवक द्वारा फंड नहीं होने की बात कही जाती है। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची का पुनः सत्यापन कर वास्तविक पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को शामिल करने की मांग की है। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। आवेदन सौंपने वालों में वीरेंद्र यादव, विनोद यादव, गोपाल यादव, लालू यादव, प्रकाश गंझू, धनंजय गंझू, जगन्नाथ यादव, बंधन साव, महेंद्र यादव, संजू देवी, शांति देवी, ललिता देवी, गीता देवी, सुमन देवी, सुगिया देवी, जसोईया देवी, प्रतिमा देवी सहित सैकड़ों ग्रामीण शामिल थे।

महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

गिद्धौर (चतरा)। थाना क्षेत्र की द्वारी पंचायत अंतर्गत भुइंया टोला झरना गांव में मंगलवार को एक महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान राधा देवी (36 वर्ष), पति गंगवा भुइंया के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी पुरुषोत्तम अग्निहोत्री पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को फंदे से उतरवाकर अपने कब्जे में लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल भेज दिया गया।

AFFIDAVIT

Before

Sub-Divisional Magistrate
Lohardaga

Appendix-'F'
Refer to Para 3 (b)(iii)

AN AFFIDAVIT FOR CHANGE OF NAME OF DEPENDENTS (ADDITION/CHANGE/AMENDMENT IN MAIN (FIRST) AND MIDDLE NAME)
I, No. 4270388W, Rank NAIK, name- SUSHIL KUMAR BARA, residing at Village Saheda Patra Toli, P.O. Jori, P.S. Lohardaga, District Lohardaga (Jharkhand) do hereby solemnly affirm and declare as under:-
(a) That I want to change name of my Spouse/ dependents (name) from ARPNA BARA to ARPANA BARA.
CF No. 805, Dated 15.06.2026.

AFFIDAVIT

Before

Sub-Divisional Magistrate
Lohardaga

Appendix-'F'
Refer to Para 3 (b)(iii)

AN AFFIDAVIT FOR CHANGE OF NAME OF DEPENDENTS (ADDITION/CHANGE/AMENDMENT IN MAIN (FIRST) AND MIDDLE NAME)
I, No. 4270388W, Rank NAIK, name- SUSHIL KUMAR BARA, residing at Village Saheda Patra Toli, P.O. Jori, P.S. Lohardaga, District Lohardaga (Jharkhand) do hereby solemnly affirm and declare as under:-
(a) That I want to change name of my Spouse/ dependents (name) from ANJANI KUMARI BARA to ANJALI BARA.
CF No. 804, Dated 15.06.2026.

चंदवा पहुंचे रघुवर दास, राज्य सरकार पर बोला हमला

नवीन मेल संवाददाता

चंदवा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास सोमवार शाम चंदवा पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वे रांची से पलामू प्रमंडल के दौरे पर जा रहे थे। इस दौरान विधायक प्रकाश राम एवं जिलाध्यक्ष बंशी यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। स्थानीय गायत्री मंदिर मोहल्ला स्थित पूर्व मंडल अध्यक्ष अमित कुमार गुप्ता के आवास पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। कार्यक्रम में अमित कुमार गुप्ता ने पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंट कर रघुवर दास का स्वागत किया। वहीं विधायक प्रकाश राम, जिलाध्यक्ष बंशी यादव, पूर्व विधायक हरेकृष्णा सिंह और राजधानी यादव का भी स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश को नक्सलवाद से मुक्त करने की दिशा में लगातार कार्य हो रहा है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कई महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया है। रघुवर दास ने भाजपा कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान सीसीएल राजहरा की ओर से 30 महिलाओं के बीच सिलाई मशीनों का वितरण भी किया गया। मौके पर पवन कुमार गुप्ता, आशीष सिंह, विनय कुमार रिकी, लाल कौशल नाथ शाहदेव, अनील सिंह, राजु उरांव, मो. उमर, विजय दुबे, दीपक निषाद, सुरेश यादव, शिकेश्वर यादव, छोटू राजा, प्रेम शंकर भगत, महेंद्र प्रसाद साहू सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।

मुख्य प्रवक्ता बनने पर प्रतुल शाहदेव को बधाई

चंदवा। प्रखंड के जमीरा पंचायत अंतर्गत रोल गांव निवासी लाल प्रतुल नाथ शाहदेव को भाजपा झारखंड का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किए जाने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की सहमति से प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्र द्वारा जारी नई सूची में उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रतुल शाहदेव को दोबारा यह दायित्व मिलने पर चंदवा सहित पूरे क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। पूर्वी मंडल अध्यक्ष आशीष सिंह ने इसे क्षेत्र के लिए गौरव की बात बताते हुए कहा कि उनकी संगठनात्मक क्षमता, राजनीतिक अनुभव और प्रभावी वक्तृत्व कला के कारण पार्टी ने उन पर पुनः भरोसा जताया है।

उपायुक्त–सह–जिलादण्डाधिकारी का कार्यालय, लोहरदगा (जिला योजना)

Request for Proposal (RFP)

Request for Proposal (RFP): District Planning Office, Lohardaga invites proposals from eligible agencies for providing professional consultation services for deployment of an **Aspirational Block Fellow (ABF)** to support district administration in planning, implementation, monitoring, and evaluation of developmental initiatives under the **Aspirational Block Programme (ABP)**.

	Information	Details
1	Name of the Work	Providing professional consultation services for deployment of an Aspirational Block Fellow (ABF)
2	Date of Publication of Bid	16.06.2026
4	Rate Valid For	One year from the date of work order
5	Last Date & Time of Submission of Bid	04.07.2026 (02:00 P.M)
6	Technical Bid Opening	06.07.2026 (12:00 P.M)
7	Financial Bid Opening	After Technical Evalution
8	Bid Submission Place	https://jharkhandtenders.gov.in/
9	Bid Opening Place	Zila Parishad, Lohardaga Building Meeting Hall
10	Contact Details	dpoloh20@gmail.com,
11	Method of Selection	1. The qualified bidder who submits the highest financial offer will typically declared the "Selected Bidder" or "Successful Bidder," provided they meet all other technical and commercial requirements of the tender. 2. In case of Same H1 [Highest Financial Offer] by two or more parties, selection will be done through presentation of the program covering topics - • About the bidder and work profile • Understanding of the scope of work • Detailed Plan for ABF • Micro plan for the improvement of all indicators • Planning for the Training and hand-holding support to Frontline Worker

नोट :– उक्त निविदा समर्पित करने संबंधी विस्तृत शर्त एवं दिशा निर्देश वेबसाईट www.lohardaga.nic.in तथा https://jharkhandtenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

ह0/–

PR 382506 (Lohardaga)26-27*D जिला योजना पदाधिकारी,लोहरदगा

न्यायालय, उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी, लातेहार

अनुमति वाद संख्या–42/2026

आम इस्तेहार

आवेदिका प्रमिला देवी पति–स्व0 पनु राम, निवास स्थान–हुम्बू, टोला–हाटाटोंगरी, पो0–चीरू, थाना–हेरहंज, जिला–लातेहार द्वारा बसंती देवी पति –उपेन्द्र मोची, निवास स्थान–हुम्बू, टोला–हाटाटोंगरी, पो0–चीरू, थाना–हेरहंज, जिला–लातेहार के साथ भूमि बिक्री के लिए अनुमति हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा– 46(1–बी) के अंतर्गत आवेदन पत्र दाखिल किया है।

भूमि का विवरण

मौजा	खाता	प्लॉट	रकबा (एकड़ में)
हुम्बू	189	2285	0.06
		2300	$0.02\frac{1}{2}$
		2301	0.02
		2633	$0.13\frac{1}{2}$
		2638	$0.04\frac{1}{2}$
		2725	$0.19\frac{1}{2}$
		2726	$0.11\frac{1}{2}$
		2728	$0.12\frac{1}{2}$
		2730	$0.01\frac{1}{2}$
	58	1073	$0.07\frac{1}{2}$
		1075	0.02
		1077	$0.03\frac{1}{2}$
		1078	0.03
		1080	$0.01\frac{1}{2}$
		1083	$0.02\frac{1}{2}$
		2538	$0.69\frac{1}{2}$
		2566	0.19
		2636	0.25
		2637	$0.17\frac{1}{2}$
		2727	$0.17\frac{1}{2}$
कुल रकबा–			2.42 ए0

एतद् द्वारा हर आम व खाश को सूचित किया जाता है कि इस भूमि अंतरण के विरूद्ध किसी को आपत्ति हो, तो स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपायुक्त– सह–जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय में आम–इस्तेहार निर्गत की तिथि से एक पक्ष (15 दिनों) के अंदर आपत्ति दायर कर सकते है। समय सीमा समाप्ति के बाद प्राप्त आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

PR 382482 Rural Development(26-27).D

प्रभारी उप समाहर्त्ता, विधि शाखा, लातेहार

एसएसबी ने शुरू किया 25 दिवसीय बेसिक कंप्यूटर कोर्स

- ग्रामीण युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने की पहल

लातेहार। मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के तहत 32वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), लातेहार द्वारा मंगलवार को बी-समवाय, लातेहार में 25 दिवसीय "बेसिक कंप्यूटर कोर्स" का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नक्सल एवं वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के गरीब, जरूरतमंद एवं पिछड़े वर्ग के युवाओं को तकनीकी एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करना है। कार्यक्रम का उद्घाटन 32वीं वाहिनी एसएसबी के कार्यवाहक कमांडेंट विनय कुमार ओझा के नेतृत्व में किया गया। समारोह में ग्राम पंचायत धनकारा की मुखिया ललिता देवी, एसएसबी के अधिकारी एवं जवान उपस्थित थे। सभी अतिथियों ने इस पहल को युवाओं के लिए रोजगार और डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 जून से 11 जुलाई 2026 तक चलेगा। इसमें जिले के विभिन्न गांवों एवं आसपास के क्षेत्रों से कुल 25 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को कंप्यूटर संचालन, फाइल प्रबंधन, मल्टीटास्किंग, डिवाइस कंट्रोल, सुरक्षा एवं यूजर कंट्रोल, एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क एवं इंटरनेट संबंधी जानकारी दी जाएगी। साथ ही एमएस वर्ड, पावर प्वाइंट और एमएस एक्सेल जैसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। कार्यवाहक कमांडेंट विनय कुमार ओझा ने कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर ज्ञान रोजगार की बुनियादी आवश्यकता बन चुका है। यह प्रशिक्षण युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देगा।

प्रशासन ने लगाया चेतावनी बोर्ड, यातायात व्यवस्था सुधारने की पहल

चंदवा। सड़क पर अनियमित रूप से बसों के ठहराव और उससे उत्पन्न हो रही यातायात समस्या को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। जिला परिषद बस स्टैंड क्षेत्र में प्रशासन की ओर से चेतावनी बोर्ड लगाया गया है, जिसमें बस मालिकों और चालकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि बसों का ठहराव केवल निर्धारित बस पड़ाव में ही किया जाए। बोर्ड पर अंकित सूचना के अनुसार बस पड़ाव के अलावा सड़क किनारे अथवा अन्य स्थानों पर बस खड़ी करने या सवारी चढ़ाने-उतारने पर मोटर वाहन अधिनियम एवं यातायात नियमों के तहत जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुख्य सड़क पर बसों के रुकने से अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न होती है और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। प्रशासन की इस पहल से यातायात व्यवस्था में सुधार और आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, पलामू
Email:- palamunrep@gmail.com

तिथि विस्तारण संबंधी सूचना

इस कार्यालय के आम सूचना ज्ञापांक 193/एन0आर0ई0पी0, दिनांक 10.06.2026 (PR No-382175) द्वारा निर्गत अतिअल्पकालिन ई–निविदा आमंत्रण सूचना ई–संख्या– RDD/NREP/Palamu 02/2026-27 में पूर्व से निर्धारित तिथि में संशोधन करते हुए निम्न प्रकार निविदा की तिथि विस्तारित की जाती है–

विवरणी	पूर्व से निर्धारित तिथि	संशोधित तिथि
ई–निविदा प्राप्त करने की तिथि	15-06-2026 Time 10:00 AM to 24-06-2026 Time 05:00 PM	18-06-2026 Time 10:00 AM to 27-06-2026 Time 05:00 PM
निविदा खोलने की तिथि एवं समय	25-06-2026 Time 10:00 AM	29-06-2026 Time 10:00 AM

नोट :– निविदा की शेष सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

ह0/–कार्यपालक अभियंता,
राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम,
मेदिनीनगर पलामू

PR 382531 (NREP)26-27*D

दृष्टिपात

उपायुक्त ने लगाया जनता दरबार, सुनी आमजनों की समस्याएं

लोहरदगा। उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने समाहरणालय परिसर में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम (जनता दरबार) में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए आमजनों की समस्याएं एवं शिकायतें सुनीं। कार्यक्रम में लोगों ने रास्ता विवाद, बैंक खाते से राशि निकासी, विद्यालय में नामांकन, अवैध निर्माण, राशन कार्ड से नाम हट जाने, घर क्षतिग्रस्त होने, वृद्धावस्था पेंशन, आवास योजना, सिंचाई हेतु विद्युत व्यवस्था, भूमि अधिग्रहण मुआवजा, भूमि म्यूटेशन, दाखिल-खारिज, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, पेयजल एवं तालाब जीर्णोद्धार सहित विभिन्न विषयों से संबंधित आवेदन उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए। उपायुक्त ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई कर निर्धारित समयावधि में मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आमजनों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा प्राप्त शिकायतों के निष्पादन की नियमित समीक्षा की जाएगी।

एसआईआर के तहत मतदाता सूची पुनरीक्षण की समीक्षा बैठक

भंडरा। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची के पुनरीक्षण, मैपिंग और शुद्धिकरण कार्य में तेजी लाने को लेकर मंगलवार को अंचल कार्यालय सभागार में सीओ दुर्गा कुमार की अध्यक्षता में बीएलओ और सुपरवाइजरों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान सीओ ने प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों पर चल रहे कार्य की प्रगति रिपोर्ट ली। इस दौरान कई बूथों पर धीमी गति से काम होने और डोर-टू-डोर सर्वे में लापरवाही बरतने पर सीओ ने संबंधित बीएलओ को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार का कार्य पूरी पारदर्शिता और गंभीरता से करें। किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीओ दुर्गा कुमार ने सभी बीएलओ को निर्देश दिया कि 18 वर्ष पूरे कर चुके सभी युवाओं का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाए जाएं। उन्होंने प्रखंड में मतदाता सूची में 5% की बढ़ोतरी का लक्ष्य निर्धारित कर 15 जुलाई तक शत-प्रतिशत कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए सीओ दुर्गा कुमार ने बताया कि एसआईआर कार्यक्रम के तहत लोहरदगा जिले में अब तक 93 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। भंडरा प्रखंड में भी कार्य अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि घर-घर जाकर फॉर्म-6, 7 और 8 भरे जा रहे हैं। बीएलओ को गरुड़ ऐप और बीएलओ ऐप के माध्यम से रियल टाइम डाटा अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। सीओ ने सभी सुपरवाइजरों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र के बीएलओ के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें और प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट अंचल कार्यालय को उपलब्ध कराएं।

मुहर्रम को लेकर भंडरा थाना में 18 जून को शांति समिति की बैठक

भंडरा। आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं भाईचारे के वातावरण में संपन्न कराने को लेकर भंडरा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक दिनांक 18 जून 2026, दिन गुरुवार को अपराह्न 3:00 बजे आयोजित की जाएगी थाना प्रभारी मनोज गुप्ता ने बताया कि बैठक में शांति समिति के सदस्य, पत्रकार बंधु, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी वर्ग, सभी समुदायों के गणमान्य व्यक्ति एवं आम नागरिकों की उपस्थिति अपेक्षित है। बैठक का मुख्य उद्देश्य मुहर्रम पर्व के दौरान क्षेत्र में शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखना है। बैठक में त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था, जुलूस के रूट, समय-सारणी, डीजे-साउंड पर रोक, अफवाहों से बचाव, साफ-सफाई, पेयजल, बिजली व्यवस्था सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। थाना प्रभारी मनोज गुप्ता ने क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिकों से सादर अपील की है कि निर्धारित तिथि एवं समय पर भंडरा थाना परिसर में उपस्थित होकर बैठक को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करें, ताकि हमारे क्षेत्र में मुहर्रम पर्व आपसी सद्भाव, शांति और भाईचारे के साथ संपन्न हो सके।

धोबी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 10 अगस्त को नासिक महाराष्ट्र में

कुडू। अखिल भारतीय धोबी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए साल 2026-2029 तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए चुनाव दस अगस्त को होना निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की तारीखों की घोषणा किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में झारखंड के आठ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।अखिल भारतीय धोबी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अवधेश बैठा व प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बालाजी लान्स एंड रिजार्ट गंगापुर रोड सोमेश्वर मंदिर के समीप नासिक रोड महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। दस अगस्त की सुबह 11 बजे से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए कार्यक्रम शुरू होगा। एक से अधिक दावेदार होने की स्थिति में वोटिंग का सहारा लिया जायेगा। देश के विभिन्न राज्यों के मतदाता तथा प्रदेश अध्यक्ष मतदान प्रक्रिया में शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के प्रवेक्षक राकेश कुमार आर्य को बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया में झारखंड से विभिन्न जिलों के जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदधारी सहित 20 लोग शामिल होंगें।

विशेष नामांकन अभियान के तहत शिक्षक शिक्षिकाओं की बैठक आयोजित

सेन्हा। प्रखंड मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी सभागार में बीपीओ प्रकाश रंजन की अध्यक्षता में प्रखंड क्षेत्र सरकारी व सरकारी मान्यता प्रापर्टी विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ विशेष नामांकन अभियान के तहत बैठक आयोजित किया गया। आयोजित बथिक में दिव्यांग बच्चे बच्चियों का विद्यालय में नामांकन करने के सम्बंध में चर्चा किया गया।वही प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी प्रकाश रंजन ने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को निर्देश देते हुए कहा कि कोई भो विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका दिव्यांगता होने के कारण से नामांकन लेने से मना नही करेंगे क्यों की दिव्यांगता को लेकर समाज मे फैले भ्रांतियां को शिक्षा के माध्यम से खत्म करना है। दिव्यांग बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जिसके लिये दिव्यांग बच्चे बच्चियों के माता पिता को बच्चों का पढ़ाई के लिये प्रेरित करना है। दिव्यांग बच्चों की नामांकन संख्या राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। इस लिए अंतर को कम करते हुए हर एक दिव्यांग बच्चों तक शिक्षा पँहुचे सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को ऐसा माध्यम सुनिश्चित करना है।

नीट-2026 परीक्षा को लेकर डीसी संदीप कुमार मीना ने की बैठक, परीक्षा 21 जून को

कदाचारमुक्त परीक्षा आयोजित कराने का निर्देश

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध, कड़ी निगरानी के निर्देश

नवीन मेल संवाददाता

लोहरदगा। उपायुक्त संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में आज जिला में नीट (यूजी)-2026 परीक्षा के कदाचारमुक्त आयोजन की तैयारी को लेकर आवश्यक बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित हुई। परीक्षा 21 जून 2026 को जिला के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय जोगना, सेन्हा में होगी। उच्चतर शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तहत गठित स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के माध्यम से यह परीक्षा आयोजित होगी। इस परीक्षा में 255 अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा केंद्र पर सुबह 11 बजे से रिपोर्ट करना है। उपायुक्त ने सभी कार्यपालक दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को परीक्षा को कदाचारमुक्त बनाये रखने के लिए विभिन्न निर्देश दिए। बैठक में परीक्षा केंद्र में कमरों की उपलब्धता, अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था, सीसीटीवी से निगरानी, पेयजल की व्यवस्था, कमरों में उचित प्रकाश की व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था, परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग आदि बिंदुओं पर गहन चर्चा की और केंद्राधीक्षक को परीक्षा की अवधि में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया। बैठक में पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी, एसडीएम अमित कुमार, एसडीपीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी संग्राम मुर्मू, जिला शिक्षा अधीक्षक अभिजीत कुमार, केंद्राधीक्षक एसी झा समेत अन्य उपस्थित थे।

उपायुक्त ने कहा कि परीक्षा केंद्र में कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में मोबाईल, डिजिटल घड़ी,पेनड्राइव, ईयरफोन, कैलकुलेटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर प्रवेश ना करे, इसकी सख्ती से जांच कर ली जाए। पूरी परीक्षा प्रक्रिया की सीसीटीवी से निगरानी होगी। किसी कदाचार की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन बेहद संवेदनशील है। परीक्षा को कदाचारमुक्त, भयमुक्त सम्पन्न कराने हेतु परीक्षा केंद्र के निश्चित दायरे में निषेधाज्ञा लागू कराने का भी निर्देश अनुमण्डल दंडाधिकारी,लोहरदगा को दिया गया। साथ ही बस स्टैंड व होटल/लॉज में सुरक्षा संबंधी आवश्यक जांच का भी निदेश दिया गया। पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने परीक्षा केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था संबंधित पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों को सतर्क एवं सक्रिय रहने का निर्देश दिया।

जेएसएलपीएस की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर डीसी ने दिए आवश्यक निर्देश

निर्धारित लक्ष्यों को तय समयसीमा में पूरा करना जरूरी : संदीप मीना

नवीन मेल संवाददाता

लोहरदगा। उपायुक्त संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभाकक्ष में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक में डीपीएम जेएसएलपीएस द्वारा स्वयं सहायता समूह से संबंधित गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की गई। वित्तीय वर्ष 2026-27 में एनआरएलएम अंतर्गत एसएचजी, ग्राम संगठन एवं सीएलएफ गठन की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि छूटे हुए परिवारों का सर्वेक्षण कर उन्हें समूहों से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर से कम-से-कम एक सदस्य एसएचजी, ग्राम संगठन अथवा सीएलएफ से जुड़ा होना चाहिए।

बैठक में स्वयं सहायता समूहों के बैंक खातों के खुलवाने की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने भंडरा प्रखंड में सभी एसएचजी के बैंक खाते शीघ्र खुलवाने, डुप्लीकेट समूहों को निष्क्रिय करने तथा सेन्हा एवं किस्को प्रखंडों में लंबित गैप को दूर करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी समूहों की प्रविष्टि एमआईएस में अद्यतन करने को कहा गया। किस्को एवं कुडू प्रखंड के बीपीएम को लक्ष्य समूह गठन एवं उनकी ऑनलाइन प्रविष्टि में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि अगली समीक्षा बैठक से पूर्व सभी निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएं। बैठक में सीएलएफ बैठकों में उठाए गए मुद्दों, उनके निष्पादन तथा एसएचजी के अंतर्गत सक्रिय महिलाओं, इंटरनल प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन, इंटरनल ब्लॉक एंकर पर्सन एवं नवजीवन सखी के कार्यों की भी समीक्षा की गई।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत फुलो-झानो आशीर्वाद अभियान की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी बीपीएम को उपलब्धियों की ऑनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि चिन्हित महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराते हुए आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जाए तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से आच्छादित किया जाए। उपायुक्त ने जिले में संचालित सभी दीदी कैफे को सक्रिय रखने तथा नियमित रूप से संचालित करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी प्रखंडों में संचालित जेंडर रिसोर्स सेंटरों की कार्यशीलता की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन एवं प्रदर्शन में सुधार लाने को कहा। बैठक में जेंडर सीआरपी, सेतु दीदी एवं चेंज मेकर की भूमिका एवं दायित्वों की भी समीक्षा की गई।

अन्नामृत फाउन्डेशन ने संचालित सेंट्रालाइज किचन का औचक निरीक्षण

लोहरदगा। उपायुक्त संदीप कुमार मीणा के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, डा मोईन अख्तर के द्वारा अन्नामृत फाउन्डेशन द्वारा संचालित सेन्ट्रालाइज किचन का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान किचन एरिया, खाद्यान गोदाम, स्टोर रूम, खाद्य पदार्थों के परिवहन में उपयोग होने वाले गाड़ियों तथा विभिन्न दस्तावेजों का गहन निरीक्षण किया गया। जांच के क्रम में मसूर एवं चना दालों की गुणवता अच्छी नही पायी गयी। अत्यधिक नमी के कारण दालों में गांठे बन गयी थी और आगे चलकर इसमें जाले तथा कीड़ा लग जाते। इस प्रकार के दालों को तुरंत आपूर्तिकर्ता को वापस करते हुए अच्छी गुणवता वालें खाद्य सामग्रियों का उपयोग करने हेतु निदेशित किया गया। किचन में उपयोग हो रहे सभी प्रकार के खाद्य सामग्रियों यथा चावल, सभी प्रकार के दालें, मसाले, सरसो तेल तथा भोजन बनाने में प्रयुक्त होने वाले पानी का भी नमूना लिया गया। इसे जांच हेतु राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। उक्त खाद्य सामग्रियां एफएसएसएआइ द्वारा तय मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित आपूर्तिकर्ता पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् कार्रवाई की जायेगी। निरीक्षण के दौरान गोदाम में उपयोग नही हो रहे चावलों पर काफी मात्रा में चूहे के मल-मूत्र पाये गये। इससे पता चलता है कि गोदाम चूहों का आवागमन होते रहता है। संचालक को पेस्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित किसी भी एजेंसी से अपने किचन एरिया, स्टोर रूम, चावल गोदाम तथा गाड़ियों में पेस्ट कंट्रोल हेतु निदेशित किया गया।

लोहरदगा को मिली रेल की ऐतिहासिक सौगात, भाजपा ने जताया केंद्र सरकार का आभार

नवीन मेल संवाददाता

लोहरदगा। लोहरदगा रेलवे स्टेशन को जंक्शन का दर्जा प्रदान किए जाने तथा लोहरदगा-गुमला-जशपुर होते हुए छत्तीसगढ़ के धर्मजयगढ़ तक 292 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन के विस्तार को स्वीकृति मिलने पर भाजपा ने केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्र के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है। भाजपा जिला अध्यक्ष अजय कुमार पंकज ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने वर्षों पुरानी मांग को पूरा कर लोहरदगा सहित पूरे क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल आवागमन को सुगम बनाएगी, बल्कि व्यापार, उद्योग, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी। उन्होंने बताया कि दशकों से लोहरदगा से गुमला होते हुए छत्तीसगढ़ तक बड़ी रेल लाइन की मांग उठती रही थी। इस दिशा में पूर्व सांसद सुदर्शन भगत, राज्यसभा सांसद समीर उरांव, भाजपा कार्यकर्ताओं, प्रबुद्ध नागरिकों तथा पत्रकारों ने समय-समय पर केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। श्री पंकज ने कहा कि रेलवे किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास का आधार होता है।

नई रेल लाइन परियोजना से लोहरदगा के विकास को मिलेगी नई गति : चेंबर

लोहरदगा। लोहरदगा को गुमला होते हुए छत्तीसगढ़ के कोरबा/धरमजयगढ़ क्षेत्र से जोड़ने वाली नई रेल लाइन परियोजना को क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। इस परियोजना को लंबे समय से चली आ रही जन मांग और विभिन्न जनप्रतिनिधियों व व्यापारिक संगठनों के प्रयासों का परिणाम माना जा रहा है। लोहरदगा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रस्तावित रेल लाइन से झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी एवं पिछड़े इलाकों में औद्योगिक, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उनका मानना है कि बेहतर रेल संपर्क से निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। चेंबर की ओर से इस परियोजना के लिए पीएम मोदी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रायगढ़ सांसद राधेश्याम राठिया, लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत, पूर्व सांसद सुदर्शन भगत, पूर्व रास सांसद महेश पोद्दार, धीरज प्रसाद साहू, समीर उरांव सहित इस दिशा में प्रयासरत सभी जनप्रतिनिधियों एवं फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। चेंबर अध्यक्ष रीतेश कुमार, पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर अग्रवाल, कमल प्रसाद केसरी, अभय अग्रवाल, उपाध्यक्ष पंकज जायसवाल, सचिव राकेश सिन्हा, सह सचिव अनीस मित्तल, कोषाध्यक्ष दीपक पोद्दार तथा अन्य पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि रेल परियोजना के साकार होने से लोहरदगा जिले के विकास को नया आयाम मिलेगा और क्षेत्र की कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा।

कार्यक्रम | लोहरदगा जिला का डेढ़ मीट्रिक टन आम्रपाली आम कोलकाता से दुबई के लिए किया निर्यात

आम निर्यात का वर्चुअल माध्यम से किया गया फ्लैग-ऑफ

- उपायुक्त ने कहा कि यह लोहरदगा जिले से आम का पहला औपचारिक निर्यात है

नवीन मेल संवाददाता

लोहरदगा। लोहरदगा जिला का 1.5 मीट्रिक टन आम्रपाली आम आज कोलकाता से दुबई के लिए निर्यात किया गया। वर्चुअल माध्यम से इसका फ्लैग ऑफ कार्यक्रम कोलकाता स्थित एपीडा के मुख्यालय से हुआ। कार्यक्रम से एपीडा मुख्यालय से चेयरमैन अभिषेक देव, क्षेत्रीय प्रबंधक श्रीकांत मंडल, उद्यान विभाग झारखंड मणिमाला खलखो, लोहरदगा जिला से उप विकास आयुक्त राज महेश्वरम, डीडीएम नाबार्ड लोहरदगा, नाबार्ड के जिला समन्वयक और कुडू प्रखंड से आम की उत्पादक समूह सेनेम नेरेम किसान उत्पादक समूह की अध्यक्ष एमलेन कंडुलना जुड़ीं। सभी ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए।

अध्यक्ष, एपीडा ने भविष्य में लोहरदगा के साथ भावी निर्यात पर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की और किसानों को इसी तरह भविष्य में भी सहयोग देने की बात कही। लोहरदगा जिला की इस उपलब्धि पर उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने कहा कि यह लोहरदगा जिले से आम का पहला औपचारिक निर्यात है। इसका महत्व अत्यंत व्यापक है क्योंकि यह हमारी स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था के वैश्विक बाजारों से जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह जिला लंबे समय से अपने वन एवं खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता रहा है। किंतु वर्ष 2017 से जिले ने सुनियोजित प्रयासों के माध्यम से अपनी एक नई पहचान बनानी शुरू की है। बिरसा हरित ग्राम योजना तथा विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से जिले में उद्यानिकी क्षेत्र का उल्लेखनीय विकास हुआ है। वर्ष 2017-18 से 2025-26 के बीच आम के बागानों का विस्तार बढ़कर 6,306 एकड़ तक पहुंच गया है, जिससे 7,288 किसान लाभान्वित हुए हैं। वर्तमान में जिले में लगभग 7.06 लाख फलदार पौधे विकसित हो चुके हैं। सेन्हा, भंडरा और कुडू सहित विभिन्न प्रखंडों में किसानों द्वारा स्थापित बागान इसकी सफलता के प्रमाण हैं। आज लगभग 1,780 एकड़ क्षेत्र में आम के पौधे फल देने की अवस्था में पहुंच चुके हैं और करीब 1,860 किसान इस मौसम में उत्पादन कर रहे हैं। वर्ष 2026-27 में इन बागानों से लगभग 2,588 मीट्रिक टन आम उत्पादन का अनुमान है, जिसमें आम्रपाली प्रमुख किस्म है। इसके अतिरिक्त मल्लिका, हिमसागर एवं लंगड़ा जैसी किस्मों का भी उत्पादन हो रहा है। पूर्व में लोहरदगा के आम मुख्य रूप से स्थानीय मंडियों तथा रांची, ओडिशा एवं आसपास के बाजारों में बेचे जाते थे। किसानों को सीमित मूल्य प्राप्त होता था तथा संगठित मूल्य श्रृंखला तक उनकी पहुंच नहीं थी। आज हम उन सीमाओं से आगे बढ़ते हुए एक नई शुरुआत कर रहे हैं। यह उपलब्धि एपीडा के सतत मार्गदर्शन, तकनीकी सहयोग एवं सहयोगात्मक प्रयासों से संभव हो पाई है।

कार्यालय–कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, लातेहार
(E-mail ID- nrep-lat@jharkhandmail.gov.in)

अल्पकालीन ई– निविदा आमंत्रण सूचना

ई–निविदा संख्या :– 06/2026-27/EE/NREP/LATEHAR (DMFT)

क्र0	आईडेंटी फिकेशन सं0 / पैकेज सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	कार्य समाप्ति की तिथि	टेन्डर कॉल
1.	NREP/LATEHAR/23/ 2026-27	प्रखंड मनिका अंतर्गत पंचायत सिंजो के ग्राम बांडी में स्थित बालिका मध्य विद्यालय मनिका के प्रांगण में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन, बांडी का निर्माण	20,89,400.00	42,000.00	03 माह	प्रथम

1. निविदा प्रकाशन की तिथि : 16.06.2026
2. ई–निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय : 24.06.2026 से दिनांक–06.07.2026 को अपराहन 5:00 बजे तक।
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : 08.07.2026 अपराहन 12:00 बजे।
4. परिमाण विपत्र की राशि घट–बढ़ सकती है तदनुसार परिमाण विपत्र का 02 प्रतिशत राशि अग्रधन की राशि के रूप में जमा करना होगा।
5. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि केवल Online Mode द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
6. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि का ई–भुगतान जिस खाता से किया जाएगा, उसी खाते में अग्रधन की राशि वापस होगी। अगर खाता को बंद कर दिया जाता है तो उसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।
7. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता:– **कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, लातेहार**
8. ई–निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0 – **06565796434 ई मेल**– nrep-lat@jharkhandmail.gov.in
9. प्राक्कलित राशि बढ़ या घट सकती है।
10. निविदा में भाग लेने वाले संवेदक इस आशय का शपथ पत्र समर्पित करेंगें की निर्धारित अवधि में कार्य अनिवार्य रुप से पूर्ण कर लेंगें।
11. उक्त निविदा में BCD में निबंधित समुचित श्रेणी के संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते है।
12. बिना कारण बताये कार्य की निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
13. विस्तृत जानकारी के लिए बेवसाईट www.jharkhandtendres.gov.in पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियन्ता,
एन0आर0ई0पी0, लातेहार

PR 382489 Rural Development(26-27)#D

Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited
(CIN No. U40108JH2013SGC001702)
Electric Supply Circle, Garhwa

Very short e-TENDER NOTICE

e-tender in two parts (Part-I Technical and Commercial and Part-II Price Part) is invited from the reputed tenderers having good experience of following same type of Civil Works and having sound financial status.

Sl. No.	NIT No.	Name of work	Estimated cost (In Rs.)	Earnest money to be deposited (In Rs.)	Cost of BOQ (non-refundable) (In Rs.)	Time for completion
1	155/PR/JBVNL /26-27	Sinking of one no 125/115 mm dia tube well and allied woks at Central Store, Garhwa under Electric Supply Circle, Garhwa.	297100/–	6000/–	750.00+136.00 (GST 18%) = 886.00	45 days
2	156/PR/JBVNL /26-27	Sinking of one no 125/115 mm dia tube well and allied woks at 33/11 KV P/S/S, Ramkanda under Electric Supply Circle, Garhwa.	297000/–	6000/–	750.00+136.00 (GST 18%) = 886.00	45 days
3	157/PR/JBVNL /26-27	Sinking of one no 125/115 mm dia tube well and allied woks at 33/11 KV P/S/S, Sarkoni under Electric Supply Circle, Garhwa.	296200/–	6000/–	750.00+136.00 (GST 18%) = 886.00	45 days

Availability of tender document on website	18.06.2026 3:00 PM to 01.07.2026 at 2:00 PM
Last date and time for bid submission/uploading	01.07.2026 at 2:00 PM
Date and time for opening of Tender Part-I (Technical and Commercial)	02.07.2026 at 2:30 PM
Date and time for opening of Tender Part-II (Price Part)	Will be communicated later on
Tendering Officer and address for communication	ESE, Electric Supply Circle, Garhwa

Any query towards this tender can also be had from the office of the undersigned during office hours or may contact on Mob No. 8809507127

1. e-Tender documents and BOQ including terms & conditions, specification etc. can be downloaded and submitted online on website https://jharkhandtenders.gov.in. Any details required in this regard can also be had from the office of the undersigned during office hours. NIC helpline no. 0651-2400178.
2. Bidder shall deposit online tender fee as mentioned above for Cost of BOQ and EMD as per rules of e-tendering portal (jharkhandtenders.gov.in).
3. The tenders will be received through electronic tendering mode only.

स्वहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचावें। कृपया अपनी शिकायतों को टॉल फ्री नं० 1800 345 6570 पर दर्ज करायें।

Sd/-
Electrical Superintending Engineer
Electric Supply Circle, Garhwa

PR.NO.382545 Jharkhand Bijlee Vitran Nigam Ltd(26-27):D

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चतरा।
अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–06 वर्ष 2026–27

1	तकनीकी बिड खोलने का स्थान	कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चतरा।
2	विज्ञापनदाता का नाम	ई0 मनोज कुमार मुण्डारी, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चतरा।
3	परिमाण विपत्र बिक्री की अंतिम तिथि	दिनांक–24.06.2026 समय 05:00 बजे अपराहन तक
4	निविदा प्राप्ति की तिथि	दिनांक–25.06.2026 समय 03:00 बजे अपराहन तक
5	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक–25.06.2026 समय 04:00 बजे अपराहन तक
6	परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान	कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चतरा।
7	निविदा प्राप्ति का स्थान	कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चतरा।
8	निविदा खोलने का स्थान	कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चतरा।
9	कार्य की विस्तृत विवरणी –	

Name of Work: Construction of Modular Rain Water Harvesting, Storm Water Collection, Desilting Chamber in Various School of Chatra District under D.W. & S. Division , Chatra for the Year 2026-27. (DMFT Fund)

क्रं.	ग्रुप संख्या	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	योजना की संख्या	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रधन की राशि (लाख में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रूपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	RWH/CTR/GR-01	237/Vikas, Dated 10.04.2026	01 No.	17.17617	0.35	5,000/-	06 Months
2	RWH/CTR/GR-02		01 No.	17.17617	0.35	5,000/-	06 Months
3	RWH/CTR/GR-03		01 No.	17.17617	0.35	5,000/-	06 Months
4	RWH/CTR/GR-04		01 No.	17.17617	0.35	5,000/-	06 Months
5	RWH/CTR/GR-05		01 No.	17.17617	0.35	5,000/-	06 Months
6	RWH/CTR/GR-06		01 No.	17.17617	0.35	5,000/-	06 Months
7	RWH/CTR/GR-07		01 No.	17.17617	0.35	5,000/-	06 Months
8	RWH/CTR/GR-08		01 No.	17.17617	0.35	5,000/-	06 Months
9	RWH/CTR/GR-09		01 No.	17.17617	0.35	5,000/-	06 Months
10	RWH/CTR/GR-10		01 No.	17.17617	0.35	5,000/-	06 Months
11	RWH/CTR/GR-11		01 No.	17.17617	0.35	5,000/-	06 Months
12	RWH/CTR/GR-12		01 No.	17.17617	0.35	5,000/-	06 Months
13	RWH/CTR/GR-13		01 No.	17.17617	0.35	5,000/-	06 Months
14	RWH/CTR/GR-14		01 No.	17.17617	0.35	5,000/-	06 Months
15	RWH/CTR/GR-15		01 No.	17.17617	0.35	5,000/-	06 Months
16	RWH/CTR/GR-16		01 No.	17.17617	0.35	5,000/-	06 Months
17	RWH/CTR/GR-17		01 No.	17.17617	0.35	5,000/-	06 Months
18	RWH/CTR/GR-18		01 No.	17.17617	0.35	5,000/-	06 Months
19	RWH/CTR/GR-19		01 No.	17.17617	0.35	5,000/-	06 Months
20	RWH/CTR/GR-20		01 No.	17.17617	0.35	5,000/-	06 Months
21	RWH/CTR/GR-21		01 No.	17.17617	0.35	5,000/-	06 Months
22	RWH/CTR/GR-22		01 No.	17.17617	0.35	5,000/-	06 Months
23	RWH/CTR/GR-23		01 No.	17.17617	0.35	5,000/-	06 Months
24	RWH/CTR/GR-24		01 No.	17.17617	0.35	5,000/-	06 Months
25	RWH/CTR/GR-25		01 No.	17.17617	0.35	5,000/-	06 Months

निविदा की शर्त्ते विभागीय वेबसाईट www.daa.jharkhand.gov.in एवं इस कार्यालय के सूचना पटट पर देखा जा सकता है। इच्छुक एजेंसी परिमाण विपत्र वेबसाईट से डाउनलोड कर निविदा में भाग ले सकते हैं, परन्तु निविदा जमा करते समय परिमाण विपत्र का निर्धारित मूल्य का बैंक ड्राफ्ट तकनीकी बीड के साथ अनुलग्नित करेंगे, जो कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चतरा के पदनाम से भुगतेय होगा।

(ई0 मनोज कुमार मुण्डारी)
कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चतरा।

PR 382547 Drinking Water and Sanitation(26-27)D

दृष्टिपात

आंगनबाड़ी कर्मियों का धरना अब 24 जून को

चैनपुर। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ, चैनपुर प्रखंड की बैठक मंगलवार को लुथरन बगीचा में प्रखंड अध्यक्ष सुशांति देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की विभिन्न समस्याओं एवं आगामी आंदोलन की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार धरना-प्रदर्शन 23 जून 2026 को आयोजित होना था, लेकिन निर्वाचन विभाग द्वारा 22 एवं 23 जून को एसआईआर प्रशिक्षण निर्धारित किए जाने के कारण कार्यक्रम की तिथि बदल दी गई है। प्रखंड अध्यक्ष सुशांति देवी ने कहा कि चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, इसे ध्यान में रखते हुए संघ ने देशहित और कर्तव्य को प्राथमिकता दी है। इसी कारण सर्वसम्मति से धरना-प्रदर्शन की नई तिथि 24 जून तय की गई। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मियों की लंबित मांगों को लेकर संघ उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन करेगा। बैठक में मौजूद सभी कर्मियों ने आंदोलन को सफल बनाने और शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। बैठक में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं उपस्थित थीं।

जन शिकायत निवारण दिवस में 50 से अधिक मामलों पर सुनवाई

गुमला। उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय सभागार में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे 50 से अधिक लोगों ने अपनी समस्याओं और मांगों से संबंधित आवेदन उपायुक्त को सौंपे। जन शिकायत दिवस में भूमि विवाद, पेंशन, आवास, प्रमाण-पत्र, पेयजल, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े मामलों पर सुनवाई की गई। इस दौरान गुमला नगर क्षेत्र के जार वाटर संचालकों ने नगर परिषद द्वारा लगाए गए वार्षिक शुल्क एवं एनओसी संबंधी व्यावहारिक कठिनाइयों को लेकर राहत की मांग की। पालकोट प्रखंड के बिलिंगबीरा पंचायत में एक ही परिवार के दो लोगों को जन वितरण प्रणाली दुकान का लाइसेंस दिए जाने की शिकायत भी सामने आई। वहीं कामडरा प्रखंड के पारही गांव के एक आवेदक ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में अपने परिवार को प्राथमिकता देने की मांग की। सिसई रोड स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-43 से जुड़े आम रास्ते को बंद किए जाने तथा नागपेनी रापूटोली गांव में भूमि विवाद से जुड़े मामलों पर भी आवेदन प्राप्त हुए। उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो ने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को जांच कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जन शिकायत निवारण दिवस प्रशासन और आम लोगों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है तथा प्रत्येक आवेदन पर पारदर्शी कार्रवाई की जाएगी।

बांस कारीगरों को मिला आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण

गुमला। पारंपरिक बांस शिल्प को आधुनिक बाजार से जोड़ने और कारीगरों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कामडारा प्रखंड के पकरा गांव में 14 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड और नीड्स संस्थान के संयुक्त प्रयास से चल रहे इस प्रशिक्षण में स्थानीय कारीगरों को आधुनिक तकनीक और उन्नत उपकरणों के उपयोग की जानकारी दी जा रही है। पकरा गांव के कारीगर वर्षों से बांस से उपयोगी और आकर्षक उत्पाद तैयार करते आ रहे हैं। अब आधुनिक प्रशिक्षण के माध्यम से उनके उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने की पहल की जा रही है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होने की उम्मीद है। प्रशिक्षण के दौरान कारीगरों को बांस प्रसंस्करण की नई तकनीक, मशीनों के सुरक्षित उपयोग, कम समय में अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करने की जानकारी दी जा रही है। मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के माध्यम से कारीगरों को मात्र 10 प्रतिशत अंशदान पर मशीन और टूल किट भी उपलब्ध कराए गए हैं। कारीगरों के लिए बेहतर कार्य वातावरण सुनिश्चित करने हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना मद से सामुदायिक सुविधा केंद्र का निर्माण कराया गया है। इस केंद्र में कारीगर मौसम की परवाह किए बिना नियमित रूप से कार्य कर सकेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों के हुनर को आधुनिक बाजार की मांग के अनुरूप विकसित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस अवसर पर प्रखंड उद्यमी समन्वयक गंदुर उरांव, नीड्स संस्थान के मास्टर ट्रेनर पांचू तुरी सहित बड़ी संख्या में बांस कारीगर उपस्थित थे।

गुमला में पहली बार सीआर धान 807 का वैज्ञानिक प्रदर्शन शुरू

गुमला। कृषि विज्ञान केंद्र गुमला एवं विकास भारती बिशुनपुर के संयुक्त प्रयास से जिले में पहली बार खरपतवारनाशी-सहिष्णु धान किस्म "सीआर धान 807" का वैज्ञानिक प्रदर्शन शुरू किया गया है। यह पहल वर्षा आधारित खेती और बढ़ती श्रम लागत की चुनौती से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित इस उन्नत किस्म का प्रदर्शन बिशुनपुर प्रखंड के शिवराजपुर, लुट्टोबारटोली, सरनाटोली, सालगी और नगर गांवों में 50 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है। इसके लिए 50 चयनित किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज और कृषि सामग्री उपलब्ध कराई गई है। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. बृजेश पांडेय ने बताया कि सीआर धान 807 देश की पहली गैर-जीएमओ खरपतवारनाशी-सहिष्णु गैर-बासमती धान किस्म है। इसमें इमाजेथापायर आधारित खरपतवारनाशी के प्रति सहनशीलता विकसित की गई है, जिससे प्रत्यक्ष बुवाई में खरपतवार नियंत्रण आसान होगा और श्रम लागत में कमी आएगी। उन्होंने बताया कि यह तकनीक कम पानी में भी बेहतर उत्पादन देती है और खेतों में लगातार जलभराव की जरूरत नहीं होती। इससे ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आती है। विकास भारती के संयुक्त सचिव महेंद्र भगत ने कहा कि अनिश्चित मानसून और श्रमिक संकट के दौर में यह तकनीक किसानों के लिए लाभकारी साबित होगी। वहीं विशेषज्ञ ई. इनो राय ने कहा कि सफल परिणाम मिलने पर इसे जिले के अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार दिया जाएगा।

योग सत्र के तीसरे दिन उजई, भ्रामरी व शीतली प्राणायाम का कराया गया अभ्यास

सिसई (गुमला)। प्रखंड क्षेत्र के पोटरो बुढ़ा महादेव मंदिर परिसर में आयोजित योग सत्र के तीसरे दिन विभिन्न योगासनों एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। योग गुरु ने प्रतिभागियों को उजई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम का अभ्यास कराते हुए इनके स्वास्थ्य लाभों की विस्तृत जानकारी दी। योगाभ्यास के दौरान पूर्ण वज्रासन, पद्मासन और मंडूकासन भी कराया गया। साथ ही प्रतिभागियों को हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित कर श्वासों की गति की गणना करने की विधि सिखाई गई। योग गुरु ने बताया कि नियमित योगाभ्यास से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और तनाव से मुक्ति मिलती है। विशेष आकर्षण के रूप में वृंदावन से आए राधा-कृष्ण भक्तों की मंडली ने सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। इसके बाद योग भजन और शांति पाठ के साथ सत्र का समापन किया गया। इसके उपरांत राजकीयकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय, सिसई प्रखंड मुख्यालय परिसर में छात्र-छात्राओं को आयुष विभाग के प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास कराया गया। विद्यालय के शिक्षक एवं विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजकों ने बताया कि आगामी 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को भव्य और यादगार बनाने के लिए पूरे प्रखंड में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। विभिन्न विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर लगातार योग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

सात वर्षीय मासूम की हत्या से दहला कासीर जामटोली

- जंगल में मिला नवीन कुमार का शव, पुलिस ने शुरू की गहन जांच

नवीन मेल संवाददाता

गुमला। रायडीह थाना क्षेत्र के कासीर जामटोली गांव में सात वर्षीय मासूम नवीन कुमार सिंह की निर्मम हत्या से पूरा इलाका दहल उठा है। अज्ञात अपराधियों ने बच्चे की हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया, जिससे गांव में भय, आक्रोश और शोक का माहौल व्याप्त है।

जानकारी के अनुसार, नवीन कुमार सिंह गांव निवासी हेमंत कुमार सिंह का इकलौता पुत्र था। सोमवार को उसके माता-पिता खेत में काम करने गए थे, जबकि नवीन गांव के अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। देर रात तक ग्रामीणों के साथ आसपास के क्षेत्रों में तलाश की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला।

इसी दौरान जंगल की ओर गए कुछ ग्रामीणों ने एक बच्चे का शव देखा। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और शव की पहचान नवीन कुमार सिंह के रूप में की गई। बेटे का शव देखते ही परिवार में कोहराम मच गया।

परिजनों के अनुसार बच्चे के सिर, गर्दन, कमर और हाथ पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि हत्या कहीं और कर शव को जंगल में फेंका गया।

घटना की सूचना पर रायडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने बीएनएस की धारा 103(1) एवं 238 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है।

तड़के शौच के लिए निकले वृद्ध की पीट-पीटकर हत्या

नवीन मेल संवाददाता

गुमला। घाघरा थाना क्षेत्र के कुगांव चट्टी गांव में मंगलवार तड़के एक वृद्ध की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दिए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 65 वर्षीय धाना उरांव के रूप में हुई है।

घटना के बाद गांव में भय और शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार, धाना उरांव सुबह करीब तीन बजे शौच के लिए घर से बाहर निकले थे।

इसी दौरान गांव के ही छोटू उरांव ने उन पर लाठी-डंडे से हमला कर दिया।

हमले में वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही घाघरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी छोटू उरांव को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि हत्या के कारणों का अब तक स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ कर सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों की जानकारी सामने आएगी। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

'नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो' अभियान के तहत भरनो में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

- गीत, नुक्कड़ नाटक और शपथ के जरिए लोगों को नशामुक्त समाज का दिया संदेश

नवीन मेल संवाददाता

गुमला। भरनो प्रखंड कार्यालय परिसर में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के तत्वावधान में सोमवार को नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और समाज को नशामुक्त बनाने के लिए प्रेरित करना था।

"नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो" अभियान के तहत ज्योति संगम संस्था के कलाकारों ने गीत, संगीत, नृत्य और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। कलाकारों ने बीड़ी, सिगरेट, शराब, ड्रग्स और अन्य मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान की जानकारी दी।

नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया कि नशा केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। कलाकारों ने अफीम की खेती नहीं करने और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से दूर रहने की अपील भी की।

कार्यक्रम में मौजूद लोगों को सामूहिक रूप से शपथ दिलाई गई कि वे स्वयं किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे और दूसरों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करेंगे। कलाकारों ने युवाओं से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और समाज में नशा मुक्ति का संदेश फैलाने की अपील की। ज्योति संगम संस्था की सचिव माधुरी मिंज ने कहा कि समाज को नशामुक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। कार्यक्रम में कलाकार कृष्णा लोहरा, कलेश्वर नगेशिया, सोनी देवी, सुमित्रा कुजूर, बिनु उरांव, जगन्नाथ उरांव और महादेव उरांव सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का अधिकार कायम रहेगा : समीर उरांव

घाघरा। पांचवीं अनुसूची एवं पेसा अधिकार संरक्षण आंदोलन के तहत मंगलवार को घाघरा प्रखंड परिसर में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न गांवों के पहान-पुजारों के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला-पुरुष शामिल हुए। धरना को संबोधित करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने कहा कि पेसा कानून को उसकी मूल भावना के अनुरूप लागू नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम सभाओं और पारंपरिक ग्राम प्रधानों को मिलने वाले अधिकार व्यवहारिक रूप से नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं को सशक्त करने के बजाय अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों में केंद्रित कर दिए गए हैं, जो पेसा कानून की भावना के विपरीत है। यदि समय रहते पांचवीं अनुसूची और पेसा कानून को पूरी मजबूती से लागू नहीं किया गया तो आदिवासी समाज व्यापक आंदोलन करेगा। समीर उरांव ने कहा कि जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का पारंपरिक अधिकार था, है और आगे भी रहेगा। वहीं पवन कुमार भगत ने कहा कि सरकार को पेसा कानून को वास्तविक स्वरूप में लागू करना चाहिए, अन्यथा चरणबद्ध आंदोलन तेज किया जाएगा। धरना कार्यक्रम में सुनील उरांव, विष्णु उरांव, लोकनाथ पहान, संजय पहान, सुरेश उरांव, शोमी उरांव, जयप्रकाश भगत, जागे पहान, सोबरन उरांव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास का स्वर्णिम काल : चंपई सोरेन

- गुमला में प्रेसवार्ता कर केंद्र की उपलब्धियां गिनाईं, राज्य सरकार पर साधा निशाना

फोटो :

गुमला। भारतीय जनता पार्टी के "सेवा, सुशासन और विकास" अभियान के तहत मंगलवार को सदर प्रखंड स्थित बिंदेश होटल में आयोजित प्रेसवार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्षों को विकास और सुशासन का स्वर्णिम काल बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष सागर उरांव ने की।

प्रेसवार्ता में चंपई सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, डिजिटल इंडिया, सड़क, रेलवे, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के साथ वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। भाजपा शासित राज्यों में डबल इंजन सरकार के कारण विकास कार्यों में तेजी आई है और योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक पहुंच रहा है। इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का माहौल है तथा सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही। उन्होंने झामुमो और कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य के विकास की गति प्रभावित हुई है। प्रेसवार्ता में विनय लाल, मुनेश्वर साहू, सविंदर कुमार सहित भाजपा के कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

गुमला रोजगार मेला बना युवाओं के सपनों की उड़ान

गुमला। जिला नियोजनालय-सह-मॉडल करियर सेंटर द्वारा मंगलवार को नगर भवन परिसर में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में जिले सहित विभिन्न क्षेत्रों के 423 युवक-युवतियों ने भाग लिया, जिनमें से 103 अभ्यर्थियों का विभिन्न कंपनियों में चयन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो एवं जिला नियोजन पदाधिकारी अनामिका तिर्की ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। रोजगार मेले में 17 प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लेकर विभिन्न पदों के लिए चयन प्रक्रिया संचालित की। कुल 212 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया, जबकि अंतिम रूप से 103 युवाओं को रोजगार मिला। उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो ने चयनित युवाओं को ऑफर लेटर वितरित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले युवाओं और नियोजकों के बीच एक प्रभावी सेतु का कार्य कर रहे हैं। युवाओं को ऐसे आयोजनों का अधिकाधिक लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने झारखंड नियोजन पोर्टल पर पंजीकरण कराने की भी अपील की, ताकि निजी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें। उपायुक्त ने कहा कि युवाओं को उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। रोजगार मेले के सफल आयोजन में यंग प्रोफेशनल रवि कुमार गहलोत, प्रवीण सुरीन, विजय लकड़ा, संदीप राम, कृष्णा राम, मंजुला लकड़ा, सीता कुमारी एवं शैलेन्द्र साहू की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

कार्यालय, जिला अभियंता, लातेहार

अल्पकालीन ई–निविदा आंमत्रण सूचना

ई0–संख्या– ZP/LATEHAR- 08/2026-27

कार्य का नामः–

क्र	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र की राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ग्रुप संख्या
1	प्रखण्ड लातेहार पंचायत हेठपोचरा ग्राम हेठपोचरा में आंगनबाडी केन्द्र भवन हेठपोचरा मध्य का जीर्णोद्धार।	10,26,800	21,000	2500	02 माह	Group_15
2	प्रखण्ड लातेहार पंचायत आरागुण्डी ग्राम बमनहेरूआ में आंगनबाडी केन्द्र भवन बमनहेरूआ का निर्माण।	20,89,400	42,000	5,000	03 माह	Group_16

1. बेवसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि :– 17.06.2026
2. ई–निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय :–30.06.2026, 5.00 बजे अपराहन् तक।
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :–02.07.2026 अपराहन 11:00 बजे।
4. परिमाण विपत्र की राशि घट–बढ़ सकती है तदनुसार परिमाण विपत्र का 02 प्रतिशत राशि अग्रधन की राशि के रूप में जमा करना होगा।
5. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि केवल Online Mode द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
6. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि का ई–भुगतान जिस खाता से किया जाएगा उसी खाते में अग्रधन की राशि वापस होगी।
7. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पताः– जिला अभियंता, लातेहार।
8. ई–निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष संख्या– 93347–02381
9. प्राक्कलित राशि बढ़ या घट सकती है।
10. उक्त निविदा में जिला परिशद, लातेहार में निबंधित समुचित श्रेणी के संवेदक निविदा में भाग ले सकते है।
11. विस्तृत जानकारी के लिए बेवसाईट www.jharkhandtendres.gov.in पर देखा जा सकता है।

PR.NO.382535 Rural Development(26-27):D

जिला अभियंता, लातेहार।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, लातेहार।
Email- rdsd.latehar@rediffmail.com

पत्रांक -....................../ग्रा०वि०वि०प्र०, लातेहार, दिनांक- ....

प्रेस विज्ञप्ति

एतद् द्वारा श्री आलोक कुमार तिवारी बेलवाटीका डालटंगज पलामू जिला पलामू झारखण्ड को सूचित किया जाता है कि जिला समाज कल्याण मद अन्तर्गत **प्रखण्ड गारू पंचायत बारेसाढ़ ग्राम बारेसाढ़ में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण कार्य** जिसका एकरारनामा संख्या F2 27/24-25 दिनांक–30.09.2024 है। आपको निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु बार बार स्मार पत्र दिया गया है, परन्तु आपके द्वारा दो वर्ष बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। एवं आपके द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कराने में रूचि नहीं ली जा रही है।

अतः आपको इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अंतिम बार निर्देश दिया जाता है कि निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा बाध्य होकर संवेदक नियमावली के 11.1.4 के तहत आपके एकरारनामा को रद्द करते हुए आपके फॉर्म को काली सूची में डालने की अनुशंसा कर दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगें।

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, लातेहार।

PR.NO.382474 Rural Development(26-27):D

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, लातेहार
Email- rdsd. latehar@rediffmail.com

पत्रांक –....................../ग्रा0वि0वि0प्र0, लातेहार, दिनांक– ....

प्रेस विज्ञप्ति

एतद् द्वारा यादव इंटरप्राईजेज इनातु हेरहंज लातेहार जिला लातेहार झारखण्ड को सूचित किया जाता है कि जिला समाज कल्याण मद अन्तर्गत **प्रखण्ड बालूमाथ पंचायत गणेशपुर ग्राम गणेशपुर–1 में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण कार्य** जिसका एकरारनामा संख्या F2 42/24-25 दिनांक–04.10.2024 है। आपको निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु बार बार स्मार पत्र दिया गया है, परन्तु आपके द्वारा दो वर्ष बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। एवं आपके द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कराने में रूचि नहीं ली जा रही है।

अतः आपको इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अंतिम बार निर्देश दिया जाता है कि निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा बाध्य होकर संवेदक नियमावली के 11.1.4 के तहत आपके एकरारनामा को रद्द करते हुए आपके फॉर्म को काली सूची में डालने की अनुशंसा कर दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगें।

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल,
लातेहार

PR 382473 (Rural Development)26-27*D

कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, पलामू
योधसिंह नामधारी महिला कॉलेज के सामने
मेदिनीनगर, पलामू – 822101

माल ढुलाई हेतु वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा आमंत्रण

पलामू जिला में GST पंजीकृत इच्छुक फर्म/ट्रांसपोर्टर से कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में कृषकों को अनुदान पर विभिन्न फसलों का बीज वितरण हेतु प्राप्त बीज एवं अन्य कृषि उपादान (INM/IPM) जिला मुख्यालय से प्रखण्ड मुख्यालय तक पहुँचाने हेतु माल ढुलाई वाहन भाड़े पर उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित शर्तो के अधीन तकनीकी बिड –A एवं वित्तीय बिड–B दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : 25.06.2026 संध्या 5 बजे तक।
तकनीकी निविदि खुलने की तिथि एवं समय : 26.06.2026 अपरह्न 3 बजे।

नियम एवं शर्तें
1. वाहन की उपलब्धता निविदादाता को कार्यालय से मांग पत्र (Demand Letter/Phone call) मिलने के अधिकतम 24 घंटे के भीतर वांछित वाहन (पिकअप या बड़ा ट्रक) कार्यालय में बताए गए स्थान पर उपलब्ध कराना होगा।
2. अनुबंध की अवधि– यह अनुबंध कार्य आदेश (Work Order) जारी होने की तिथि से 01 वर्ष के लिए वैध होगा। कार्य संतोषजनक होने पर इसे आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है।

तकनीकी पात्रता (Technical Eligibility Criteria–लिफाफा 'A') –
1. निविदादाता को तकनीकी बोली के लिफाफे में निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित (Self & Attested) प्रतियां।
2. फर्म/ट्रांसपोर्टर का **PAN** कार्ड और **GST** रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
3. कम से कम 2 वाहनों की कमर्शियल **RC,** वैध फिटनेस और प्रदूषण प्रमाण पत्र (**PUC**)।
4. वाहनों का वैध कमर्शियल इंश्योरेंस (**First Party Insurance**) और परमिट।
5. चालक (**Driver**) का वैध कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस (**TR/Commercial DL**)।
6. राशि (**EMD**) 40,000/– (चालीस हजार) का डिमांड ड्राफ्ट (**DD**) जो कि **"जिला कृषि पदाधिकारी, पलामू"** के नाम पर देय हो।

वित्तीय शर्तें एवं भुगतान प्रक्रिया (Financial Terms – लिफाफा 'B')
1. दूरी/किलोमीटर (**KM**) की गणना कार्यालयध्सामग्री लोडिंग प्वाइंट से लेकर अनलोडिंग प्वाइंट तक के वास्तविक दुरी के आधार पर की जाएगी।
2. वाहन का लॉगबुक का सत्यापन कार्यालय के कर्मचारी द्वारा किया जाएगा।
3. ट्रांसपोर्टर को प्रत्येक माह की समाप्ति पर लॉगबुक की प्रमाणित प्रति के साथ अपना कमर्शियल बिल जमा करना होगा।
4. भुगतान चेक/बैंक ट्रांसफर (**NEFT/RTGS**) के माध्यम से किया जाएगा।
5. नियमानुसार भुगतान राशि से **TDS** और अन्य वैधानिक करों (**Taxes**) की कटौती की जाएगी।
6. सामग्री की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की होगी। रास्ते में चोरी या प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर ट्रांसपोर्टर को हर्जाना देना होगा।
7. किसी भी दुर्घटना (**Accident**) या यातायात नियमों के उल्लंघन (**Challan**) की स्थिति में सभी कानूनी और वित्तीय जिम्मेदारियां वाहन मालिक/ट्रांसपोर्टर की होंगी। कार्यालय का इससे कोई सरोकार नहीं होगा।
8. यदि वेंडर समय पर वाहन उपलब्ध कराने में असफल रहता है, तो कार्यालय को बाजार से दूसरे वाहन से माल मंगाने का अधिकार होगा। इसमें होने वाला अतिरिक्त खर्च वेंडर के बिल या धरोहर राशि (**EMD**) से काटा जाएगा।
9. बिना कोई कारण बताए निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार जिला कृषि पदाधिकारी, पलामू के पास सुरक्षित रहेगा।

जिला कृषि पदाधिकारी
पलामू

PR 382526 Agriculture(26-27).D

विचार प्रवाह प्रसन्नता कुछ सीमा तक बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर करती है, परंतु मुख्यत: मानसिक दृष्टिकोण पर। सुखी होने के लिए व्यक्ति के पास अच्छा स्वास्थ्य, संतुलित मन, समृद्ध जीवन, उचित कार्य, कृतज्ञ हृदय और सर्वोपरि, प्रज्ञा या ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए। - **श्री श्री परमहंस योगानंद, 'सफलता का नियम'**

राष्ट्रीय नवीन मेल

खाट पर सिस्टम व डाटा का बूम

देश के अन्य प्रांतों की तरह झारखंड में भी अक्सर खाट या कंधे पर मरीज या लाश लादे आम आदमी की तस्वीरें छपती हैं और कुछ दिनों बाद हम सभी भूल जाते हैं कि कहां ऐसा हुआ था। नेता बनने, सरकारी नौकरी या किसी भी कीमत पर पैसा कमाने के लिए मारामारी के पीछे एक बड़ा कारण यह भी होता है कि हम उससे अपना और परिजन का बढ़िया इलाज किसी प्राइवेट अस्पताल में करा सकें । दूसरी ओर करोड़ों की लागत वाले सरकारी अस्पतालों में आम आदमी इलाज के लिए मारामारी करता है। नए इंडिया में स्कूलों के बाद अस्पताल उद्योग का रूप ले चुके हैं और किसी भी शहर में बड़ी बिल्डिंग इसमें लगे लोगों की है जबकि सरकारी अस्पतालों में एंबुलेंस से लेकर उपकरण खरीदने का बजट बढ़ता ही जा रहा है। अनेक सरकारी शिक्षक और डॉक्टर ही इन प्राइवेट स्कूलों या अस्पतालों में मुख्य भूमिका निभाते हैं।अनेक नेताओं के स्कूल या प्राइवेट अस्पताल हैं। कुछ दिनों पूर्व हेल्थ सर्वे का डाटा जारी होने के साथ एक अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। सर्वे के नतीजे असल में उस चीज के ठीक उलट काम करते हैं, जो उन्हें करना चाहिए। सर्वे रिपोर्ट उन बातों को ही सामने लाती हैं, जिन्हें हम पहले से जानते हैं। शायद ही कभी इनके आधार पर तुरंत कोई कार्यक्रम शुरू किया जाता है। हाल ही में जारी स्वास्थ्य से जुड़े दो सर्वे-नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-6 और नेशनल हेल्थ अकाउंट्स 2022-23 के मामले में भी ऐसा ही लगता है। इन दोनों सर्वे से नीति बनाने वालों और नागरिकों को बेहतर समझ मिलनी चाहिए थी, पर वही पुरानी कहानी दोहराई जाती दिखती है। सर्वे का महत्व इसमें नहीं है कि क्या काम किया गया, बल्कि यह दिखाने में है कि कार्यक्रम कहां कमजोर है और पुरानी रणनीतियां कहां नाकाफी हैं। व्यावसायिक समूहों ने भी सेहत से जुड़ी बढ़ती चुनौतियों की ओर इशारा किया है और उन्हीं के आधार पर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया है। जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े संदेश कमजोर हैं और निजी स्वास्थ्य बाजार आक्रामक हैं, वहां हर सर्वे के नतीजे को व्यवसाय के मौके में बदला जा सकता है।अच्छी बात है कि प्रिंट मीडिया ने उन मुद्दों को व्यापक कवरेज दी है, जो नागरिकों के लिए मायने रखते हैं: जैसे मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और अन्य गैर-संचारी (एनसीडी) रोग। हालांकि, इनमें से ज्यादातर बातें पहले से ही पता थीं। मोटापा और अन्य एनसीडी अब सभी सामाजिक व आर्थिक वर्गों में फैल गए हैं। फिर भी, इन सर्वे के नतीजों और नीतियों पर गंभीरता से चर्चा नहीं हो रही है, जो चिंतनीय है। हेल्थ सर्वे का मकसद पुरानी समस्याओं को याद दिलाना भर नहीं होता है। इसका मकसद तो सुधार के लिए जरूरी कदम उठाना होता है। इन सर्वे का विश्लेषण धीमा होता है, क्योंकि कच्चा डाटा आसानी से नहीं मिलता और अक्सर इसे काफी समय बाद साझा किया जाता है। ऐसे में, नीति निर्माता अक्सर यह कहकर विश्लेषण करने से बचते हैं कि डाटा पुराना है। इस तरह डाटा अपनी अहमियत खो देता है। जब इसे जारी किया जाता है, तो यह ऐसी हालत में होता है कि इसका गहराई से मतलब नहीं निकाला जा सकता। नतीजतन, कुछ करने का मौका हाथ से निकल जाता है। डाटा से सेहत तभी बेहतर होती है, जब उसे सही नीतिगत फैसलों से जोड़ा जाए। जो देश स्वास्थ्य सबंधी डाटा का सही इस्तेमाल करते हैं, उनके पास ऐसे सिस्टम व मजबूत संस्थान होते हैं, जो तेजी से नीतियां तैयार करने, पिछड़े जिलों की पहचान व समीक्षा करने, प्रदर्शन की तुलना करने, संसाधन बांटने और कार्यक्रम में बदलाव लाने का काम करते हैं। इसलिए, 'डाटा-टू-एक्शन' कोई नारा नहीं, एक अनुशासन है, जिसकी भारत को जरूरत है। सबसे पहले, हर बड़े राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 30 दिनों के भीतर सरकार और स्वतंत्र संगठनों द्वारा मिलकर एक राष्ट्रीय व राज्य-स्तरीय एक्शन नोट तैयार किया जाना चाहिए। इसमें ईमानदारी से बताया जाना चाहिए कि क्या सुधार हुआ है, क्या नहीं हुआ है और स्थिति कहां बिगड़ी है। हर बिंदु को एक कार्यक्रम और एक जिम्मेदार अथॉरिटी से जोड़ा जाना चाहिए। दूसरी बात, राज्य स्तर पर स्वास्थ्य डाटा की समीक्षा बैठकें होनी चाहिए। सभी हितधारकों और स्वतंत्र विषय विशेषज्ञों को मिलकर नतीजों की जांच करनी चाहिए। सवाल यह होना चाहिए कि 'हमें क्या बदलना होगा?' तीसरी बात, डाटा का सही और समय पर इस्तेमाल करने के लिए सिस्टम की जरूरत है। भारत ने 'इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म' बनाना शुरू कर दिया है, पर यह मुख्य रूप से रियल-टाइम डाटा के लिए है। चौथा, सर्वे डाटा की प्राइमरी जानकारी और सोर्स फाइलें जल्द उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि स्वतंत्र शोधकर्ता और सरकारी संस्थान तेजी से उसका विश्लेषण कर सकें। पांचवीं बात, नतीजों का असर बजट आवंटन पर पड़ना चाहिए। अगर किसी सर्वे में गैर-संचारी रोगों के मामले बढ़ते दिखते हैं, तो बजट में इसकी रोकथाम और इलाज के लिए प्रावधान होने चाहिए। सरकारी सुविधाओं में जरूरी दवाओं की उपलब्धता बढ़ाई जानी चाहिए। अगर बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, तो स्कूल में स्वास्थ्य, खाने-पीने से जुड़े नियमों और शहरी योजना में इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अक्सर यह कहा जाता है कि स्वास्थ्य संबंधी डाटा जरूरी चीजों को तो छिपाता है, पर गैर-जरूरी चीजों को सामने ले आता है। जबकि इसे एक्स-रे जैसा होना चाहिए। यह तभी काम का होता है, जब इसे सही ढंग से समझा जाए, इस पर ईमानदारी से चर्चा की जाए और फिर काम किया जाए। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह लगातार स्थिति में सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं पर डायन हत्याओं के मामले जहां पर हैं वहां स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या है उसका अध्ययन किया जाना चाहिए सच्चाई सामने आ जाएगी।

इंडिया

सुनील बादल
कार्यकारी संपादक

स्वस्थ भारत, सशक्त भारत- स्वास्थ्य देखभाल विकास के 12 वर्ष

आज की बात

अनुप्रिया पटेल
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री

> आयुष्मान आरोग्य मंदिर का सफ़र व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के विस्तार और प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही से समस्या होने से पहले ही ध्यान रखने वाली देखभाल की ओर ज़रूरी बदलाव को दिखाता है। व्यापक स्वास्थ्य पैकेजों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 करना, भारत की बदलती आबादी और बीमारियों के बदलते पैटर्न के हिसाब से उठाया गया एक ज़रूरी कदम है

बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली से आर्थिक उत्पादकता बढ़ती है, कार्यबल की संख्या में बढ़ोतरी होती है और विकास दीर्घावधि तक होता है। इसलिए, अच्छी सेहत न केवल समाज के लिए अच्छा संकेत है, बल्कि यह देश की एक संपत्ति भी है। यह वह आधार है, जिस पर मानवीय क्षमता का निर्माण होता है और देश की ताकत मापी जाती है। इसलिए, बेहतर सेहत न केवल समाज के लिए अच्छा है, बल्कि यह देश की एक संपत्ति है और इसमें लगाया गया हर रुपया देश के लोगों में किया गया निवेश है। इस तरह, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी), यानी यह सुनिश्चित करना कि सभी लोग, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, बिना किसी आर्थिक परेशानी के, जब और जहां जरूरत हो, अच्छी गुणवत्ता की सभी ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाएं हासिल कर सकें। यह न केवल 2030 तक हासिल किया जाने वाला सतत विकास का लक्ष्य है, बल्कि सेहत से जुड़ी एक प्राथमिकता भी है। भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 (एनएचपी 2017), सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) और एसडीजी 3 को हासिल करने के लक्ष्य के अनुरूप है और यह एक सरल लेकिन मज़बूत सोच पर आधारित है – स्वास्थ्य सेवाओं तक हर व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए। इसके चार स्तंभ, किफायती होना, पहुंच, गुणवत्ता और उपलब्धता , उस सोच को वास्तिवकता में बदलते हैं और जीवन के सभी चरणों में देखभाल की एक व्यापक व्यवस्था को मज़बूत करते हैं। लक्ष्यों के अनुरूप, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्यों को स्वास्थ्य प्रणाली का एक एकीकृत तीन-स्तरीय मॉडल प्रदान करने में मदद करता है, जिसमें ग्रामीण और शहरी इलाकों (कमजोर वर्गों सहित) के बीच दोतरफा रेफरल लिंक शामिल हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) प्राथमिक स्तर पर बीमारी से बचाव, सेहत को बढ़ावा देने, इलाज, पुर्नवास और प्रशामक देखभाल जैसी व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं। ईसंजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफ़ॉर्म इन एएएम के जरिए समुदाय को विशेषज्ञों से जोड़कर विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। साथ ही, एक खास टेली-मानस प्लेटफ़ॉर्म भी है, जिसने अब तक कुल 38.93 लाख लोगों तक पहुंच बनाई है।

एएएम से जुड़े द्वितीय स्तर के केंद्र जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)/प्रथम रेफरल इकाई (एफआरयू) और ज़िला अस्पताल (डीएच) होते हैं, जो विशेषज्ञ के समक्ष इलाज और अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा के लिए रेफरल का पहला ज़रिया होते हैं। वहीं, मेडिकल कॉलेज जैसे तृतीयक संस्थान सबसे ऊपर होते हैं और ज़्यादा जटिल व सुपर-स्पेशलिस्ट सेवाओं की ज़रूरतें पूरी करते हैं।

इस तीन-स्तरीय प्रणाली को सरकारी स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी का समर्थन प्राप्त है। पिछले दशक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर होने वाला खर्च 168% बढ़ गया है, जो स्वास्थ्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता मानने के सरकार के संकल्प को दर्शाता है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर का सफ़र व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के विस्तार और प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही से समस्या होने से पहले ही ध्यान रखने वाली देखभाल की ओर ज़रूरी बदलाव को दिखाता है। व्यापक स्वास्थ्य पैकेजों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 करना, भारत की बदलती आबादी और बीमारियों के बदलते पैटर्न के हिसाब से उठाया गया एक ज़रूरी कदम है। बढ़ती उम्र की आबादी और गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के बढ़ते मामलों की दोहरी चुनौतियों का सामना करते हुए, इसके दायरे में गैर-संचारी रोग, मानसिक स्वास्थ्य, बुजुर्गों की देखभाल, आपातकालीन सेवाएं, आंख, कान-नाक-गला (ईएनटी) और मुंह की सेहत के साथ-साथ योग और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां शामिल हैं। यह सब उस आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो भारत अब बन रहा है। मई 2026 तक, देश भर में 1.8 लाख से ज़्यादा एएएम काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को उनके घर के पास स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। इस विस्तार का असर एएएम में 120 करोड़ से ज्यादा ओपीडी परामर्श, 70 करोड़ से ज्यादा ईसंजीवनी टेली-परामर्श और अच्छी सेहत व कल्याण को बढ़ावा देने वाले 46.1 करोड़ से ज्यादा वेलनेस सत्रों में साफ़ दिखता है।

प्राथमिक देखभाल स्तर पर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और आम कैंसर (जैसे ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर) के लिए आबादी-आधारित स्क्रीनिंग 30 साल से ज्यादा उम्र के सभी वयस्कों के लिए की जाती है, जिससे बीमारी का जल्दी पता लगाना एक सामान्य प्रक्रिया बन जाती है। यह जांच 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' के तहत सेवा वितरण का एक अहम हिस्सा है, जो एनसीडी की रोकथाम को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में शामिल करती है। एनसीडी सेवाओं का विस्तार बीमारी का जल्दी पता लगाने, रोकथाम, प्रबंधन और इलाज के लिए एक बहु स्तरीय प्रयास है। समर्पित एनसीडी क्लीनिक, डे-केयर कैंसर केंद्र, तृतीयक देखभाल कैंसर केंद्र और राज्य कैंसर संस्थान, उन्नत ऑन्कोलॉजी सेवाओं को विकेंद्रीकृत करते हैं और विशेषज्ञ देखभाल को मरीज़ के करीब लाते हैं। साथ ही, बचाव से जुड़ी गतिविधियों के लिए 'होल-ऑफ-गवर्नमेंट' दृष्टिकोण अपनाया जाता है। एफएसएसएआई स्वस्थ खान-पान की आदतों को बढ़ावा देता है, 'फिट इंडिया मूवमेंट' शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है और आयुष मंत्रालय योग और कल्याण को आगे बढ़ाता है। लगातार चलने वाले जन-जागरूकता अभियान और स्वास्थ्य दिवस मनाने जैसे कार्यक्रम इन प्रयासों को और मज़बूत करते हैं। खाने के तेल की खपत को 10% कम करने की प्रधानमंत्री मोदी की निजी अपील एक सरल लेकिन दमदार सोच को ज़ाहिर करती है कि एनसीडी के ख़िलाफ़ लड़ाई अस्पतालों के साथ-साथ घरों में भी जीती जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के विस्तार के लिए, एएएम स्तर पर 'सामुदायिक स्वास्थ्य ऑफिसर्स' का एक नया कैडर शुरू किया गया, जिससे क्लिनिकल और जन स्वास्थ्य से जुड़ी विशेषज्ञता समुदायों के और करीब आ गई। यह विस्तार लोगों के घर-द्वार तक भी पहुँचा, जहाँ फ्रंटलाइन नेटवर्क बढ़कर 10 लाख से ज़्यादा आशा (आशा) कार्यकर्ताओं तक पहुंच गया, जिन्होंने समुदाय को स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ा। विस्तार के साथ-साथ, भारत ने देखभाल के मापदंडों को बदलने की ज्यादा मुश्किल चुनौती भी स्वीकार की। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक, जो देश में ही विकसित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणीकृत हैं, ने गुणवत्ता को सिर्फ़ एक इच्छा से बदलकर एक जवाबदेही बना दिया। 65,000 से ज़्यादा जन स्वास्थ्य केंद्र, जिनमें 54,926 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शामिल हैं, अब एनक्यूएएस द्वारा प्रमाणीकृत हैं। इसके अलावा, आईपीएचएल के लिए लैब मानकों ने व्यवस्था में और मज़बूती और सटीकता लाई है।

क्वाड की नई खनिज रणनीति : क्या टूट पाएगा चीन का वैश्विक वर्चस्व?

अलग बात

जयदेव राठी

विश्व राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है, जहाँ संसाधनों पर नियंत्रण ही भविष्य की शक्ति का आधार बनता जा रहा है। तेल और गैस के बाद अब दुनिया की नजर "क्रिटिकल मिनरल्स" यानी दुर्लभ खनिजों पर टिक गई है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा उपकरण, मोबाइल फोन, सौर ऊर्जा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी आधुनिक तकनीकों का पूरा ढांचा इन खनिजों पर निर्भर है। ऐसे समय में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समूह क्वाड द्वारा 20 अरब डॉलर के निवेश से "क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क" की घोषणा केवल आर्थिक समझौता नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने की एक बड़ी रणनीतिक पहल मानी जा रही है। दरअसल, दुनिया में दुर्लभ खनिजों के उत्पादन और प्रसंस्करण पर चीन का लगभग एकाधिकार बना हुआ है। लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन में चीन की पकड़ इतनी मजबूत है कि पश्चिमी देश भी उसके विकल्प तलाशने को मजबूर हैं। कोरोना महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद यह बात और स्पष्ट हो गई कि यदि किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता बनी रही तो वैश्विक उद्योग कभी भी संकट में फंस सकते हैं। यही कारण है कि अब अमेरिका और उसके सहयोगी देश चीन पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर रहे हैं। नई दिल्ली में हुई क्वाड देशों की बैठक में जिस "क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव" की घोषणा की गई, उसका मूल उद्देश्य केवल खनिजों का व्यापार बढ़ाना नहीं, बल्कि एक ऐसी सुरक्षित और पारदर्शी सप्लाई चेन तैयार करना है, जो किसी एक देश के नियंत्रण में न हो। यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में खनिजों की मांग कई गुना बढ़ने वाली है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वर्ष 2040 तक लिथियम की मांग लगभग 40 गुना तक बढ़ सकती है। ऐसे में यदि दुनिया चीन पर ही निर्भर रही तो आर्थिक और रणनीतिक जोखिम और अधिक बढ़ेंगे। क्वाड देशों की यह पहल वैश्विक राजनीति में एक नए "खनिज शीत युद्ध" की शुरुआत भी मानी जा सकती है। अमेरिका लंबे समय से चीन के बढ़ते आर्थिक और तकनीकी प्रभाव को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। पहले व्यापार युद्ध, फिर चिप तकनीक पर प्रतिबंध और अब खनिज क्षेत्र में नया गठबंधन इसी रणनीति का हिस्सा दिखाई देता है। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया है कि क्वाड किसी विशेष देश को घेरने वाला संगठन नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह भी है कि इस पहल का सबसे बड़ा असर चीन पर ही पड़ने वाला है। भारत के लिए यह समझौता कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हो सकता है। भारत अभी इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी निर्माण और सेमीकंडक्टर उद्योग में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन इन उद्योगों की सबसे बड़ी चुनौती आवश्यक खनिजों की उपलब्धता है। भारत के पास कुछ खनिज संसाधन अवश्य हैं, परंतु उनकी मात्रा सीमित है और तकनीकी प्रसंस्करण क्षमता भी पर्याप्त नहीं है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया जैसे संसाधन सम्पन्न देशों और अमेरिका-जापान जैसी तकनीकी शक्तियों के साथ साझेदारी भारत को भविष्य के उद्योगों में मजबूत स्थिति दे सकती है। यह पहल "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" अभियान को भी नई दिशा दे सकती है। यदि भारत दुर्लभ खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित कर लेता है तो वह बैटरी निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन और चिप निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक निवेश आकर्षित कर सकता है। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकेगा। हालांकि इस पूरी रणनीति के सामने कई चुनौतियाँ भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि चीन केवल खनिज उत्पादन में ही नहीं, बल्कि उनके प्रसंस्करण और तकनीकी उपयोग में भी काफी आगे है। दुनिया के लगभग 85 प्रतिशत रेयर अर्थ प्रोसेसिंग पर चीन का नियंत्रण है। केवल खदानें खोज लेने से समस्या हल नहीं होगी। खनिजों को उपयोगी उत्पादों में बदलने के लिए भारी तकनीकी निवेश, पर्यावरणीय संतुलन और लंबी अवधि की नीति की आवश्यकता होगी।

(ये लेखक के निजी विचार हैं।)

आपकी बात

रानी लक्ष्मी बाई का जीवन और बलिदान भारतीय नारी शक्ति की महान पहचान

संजय सर्राफ

भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का नाम अदम्य साहस, देशभक्ति और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस प्रतिवर्ष 18 जून को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1858 में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था।उनका बलिदान भारतीय इतिहास की सबसे प्रेरणादायक घटनाओं में से एक माना जाता है।महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें प्यार से 'मनु' कहा जाता था। विवाह के पश्चात वे झांसी की महारानी बनीं। जब अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत झांसी को अपने अधीन करने का प्रयास किया, तब रानी लक्ष्मीबाई ने इसका डटकर विरोध किया। वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया और वीरता की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की, जो आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणास्त्रोत है।18 जून 1858 को ग्वालियर के निकट कोटा-की-सराय में अंग्रेजी सेना से युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुईं। अंतिम समय तक उन्होंने अपने साहस और रणकौशल का परिचय दिया। उनका प्रसिद्ध कथन-मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी,आज भी देशभक्ति की भावना को प्रज्ज्वलित करता है। रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस का उद्देश्य नई पीढ़ी को राष्ट्रप्रेम, आत्मसम्मान, साहस और कर्तव्यनिष्ठा के मूल्यों से परिचित कराना है। यह दिवस हमें यह संदेश देता है कि देश की स्वतंत्रता, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हर नागरिक को सदैव तत्पर रहना चाहिए। विद्यालयों, महाविद्यालयों, सामाजिक संस्थाओं तथा विभिन्न संगठनों द्वारा इस अवसर पर संगोष्ठियों, निबंध प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन और बलिदान भारतीय नारी शक्ति की महान पहचान है।

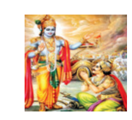

राष्ट्रीय नवीन मेल

धर्म-अध्यात्म

स्वयं को स्वयं उठाओ

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्।
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥

भगवद्-गीता-6.5

स्वामी चिन्मयानंद

श्लोक का अर्थ *–मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं को स्वयं के द्वारा ऊपर उठाए, स्वयं को नीचे गिरने न दे। मन ही स्वयं का मित्र है, मन ही स्वयं का शत्रु है।*

'उद्धरेत्' यानि ऊपर उठाने की यह प्रेरणा जीवन के प्रत्येक स्तर पर लागू होती है। जब हम 'उठाने' या 'उत्थान' शब्द पर विचार करते हैं, तो वह सदैव एक निम्न अवस्था से उच्च संभावना की ओर गति का प्रतीक होता है। यह उत्थान कभी सरल रूप में जल का पात्र होंठों तक उठाने जैसा, कभी किसी यंत्र द्वारा सड़क निर्माण हेतु मिट्टी उठाने जैसा, तो कभी एक स्नेहमयी माता द्वारा शिशु को गोद में उठाने जैसा है। हमारे दैनिक जीवन में भी यह 'उत्थान' की भावना विभिन्न रूपों में प्रकट होती है - सेवा या व्यवसाय में उन्नति की आकांक्षा, अपनी छवि को सुधारने की इच्छा, अथवा किसी नूतन प्रयास में श्रेष्ठता प्राप्त करने की प्रेरणा। इन सब उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि कहीं-न-कहीं हमारे भीतर ऊंचा उठने की चाह अवश्य है। हमें भले यह न पता हो कि कहां पहुंचना है, पर भीतर से हम जानते हैं कि जीवन में कुछ तो उच्चतर है। अपने कर्मों और प्रतिक्रियाओं के परिणाम को लेकर बेचैनी तथा प्रतिदिन की झुंझलाहटें हमारी दृष्टि को धूमिल तथा जीवन के लक्ष्य को सीमित कर देती हैं। यह श्लोक हमें प्रेरित करता है कि अब समय आ गया है कि हम असुरक्षा, आत्म-संदेह, चिंता और भय जैसी सभी धारणाओं से स्वयं को ऊपर उठाएं। एक भी क्षण प्रतीक्षा न करें; जो कुछ भी हमें उच्चतर उपलब्धि से रोक रहा है उसे दृढ़ता से त्याग दें। पर प्रश्न यह है कि हमे स्वयं को किस दिशा में, किस प्रकार उठाना चाहिए?

–पुस्तक गीता पंचामृत से साभार

आज का दोहा

चले अकेला तो लगे, देश चल रहा साथ।
कितनों को नाथा अभी, स्वयं हो गया नाथ।।

सोमदत्त शर्मा, गाजियाबाद (उ.प्र.)

रचना भेजिए

समाचारों के संबंध में शिकायत, सुझाव या इस पेज के लिए आर्टिकल कृप्या भेजें article.rnmail@gmail.com कॉल/व्हाट्सएप - 82925 53444 -संपादक

फेसबुक वॉल से

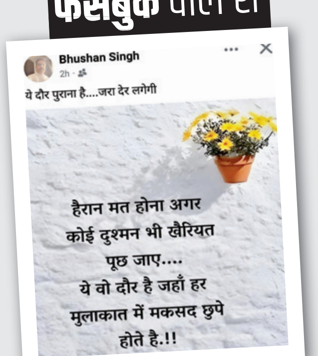

एक्स से

इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक दौर : भारत के लिए अवसर या चुनौती?

देश की बात

कुमार सिद्धार्थ

दुनिया के ऑटोमोबाइल बाजार में बड़ा बदलाव धीमे-धीमे आकार ले रहा है। पेट्रोल और डीज़ल से चलने वाली पारंपरिक गाड़ियां, जो पिछले सौ वर्षों से आधुनिक परिवहन व्यवस्था की पहचान रही हैं, अब धीरे-धीरे अपनी पकड़ खो रही हैं। उनकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन ले रहे हैं। हाल में प्रकाशित एक अध्ययन ने यह दावा किया है कि यूरोप और चीन में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, बाजार स्वयं इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में आगे बढ़ रहा है और पारंपरिक ईंधन आधारित वाहनों की वापसी मुश्किल होती जा रही है। यह केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं, बल्कि ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और वैश्विक राजनीति तक असर डालने वाला बदलाव है। सवाल यह है कि इस वैश्विक परिवर्तन के बीच भारत कहाँ खड़ा है? यूरोप और चीन के संदर्भ में किए गए अध्ययन का सार है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तेजी से कई गुना बढ़ रही है, यानी हर कुछ वर्षों में इनकी संख्या लगभग दोगुनी हो रही है और इन देशों में यह बाजार अब अपने बल पर आगे बढ़ने लगा है। शोधकर्ताओं के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती बिक्री, पेट्रोल-डीज़ल कारों की घटती मांग, बाजार में इलेक्ट्रिक वाहन के बढ़ते विकल्प और कीमतों में कम होता अंतर इस बात के संकेत हैं कि अब बाजार तेजी से बदलाव की दिशा में बढ़ चुका है, जहाँ से पुराने ढर्रे पर लौटना आसान नहीं होगा। चीन और यूरोप में यह परिवर्तन केवल बाजार की ताकत से नहीं आया, बल्कि वर्षों की नीति, सब्सिडी, सरकारी निवेश और उद्योग की तैयारी ने मिलकर इसे संभव बनाया है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है और तेजी से शहरीकरण, बढ़ती आय, ऊर्जा आयात और प्रदूषण जैसी चुनौतियों के बीच परिवहन का भविष्य तय करने की स्थिति में है। भारत की सड़कों पर आज भी पेट्रोल और डीज़ल वाहन हावी हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों की उपस्थिति अब केवल प्रयोगात्मक नहीं रही। दोपहिया और तिपहिया वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहन की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। शहरी परिवहन में इलेक्ट्रिक बसें भी धीरे-धीरे जगह बना रही हैं। लेकिन चारपहिया निजी वाहनों के मामले में भारत अभी शुरुआती चरण में है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या भारत भी उसी "निर्णायक मोड़" की ओर बढ़ रहा है, जिसकी चर्चा यूरोप और चीन के संदर्भ में हो रही है? भारत के सामने इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में बढ़ने का सबसे बड़ा तर्क आर्थिक है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के रूप में आयात करता है। तेल की कीमतों में वैश्विक उतार-चढ़ाव सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर डालते हैं। पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने पर महंगाई बढ़ती है, परिवहन लागत बढ़ती है और विदेशी मुद्रा पर दबाव पड़ता है। ऐसे में अगर परिवहन का बड़ा हिस्सा बिजली आधारित हो जाए, तो तेल आयात पर निर्भरता कम की जा सकती है। अध्ययन भी बताता है कि तेल आयात करने वाले देशों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर संक्रमण से आर्थिक लाभ हो सकता है, क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और व्यापार संतुलन बेहतर हो सकता है। पर्यावरणीय नजरिये से भी भारत के लिए इलेक्ट्रिक वाहन बदलाव केवल विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता बनता जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में वायु प्रदूषण एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है। परिवहन क्षेत्र इसका बड़ा कारण है। पेट्रोल और डीज़ल वाहनों से निकलने वाला धुआं कार्बन उत्सर्जन के साथ-साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड और सूक्ष्म कणों के रूप में स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है। भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्धताएं जताई हैं। ऐसे में अगर परिवहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों का विस्तार होता है, तो कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि यह भी सच है कि इलेक्ट्रिक वाहन तभी वास्तव में हरित विकल्प होंगे, जब बिजली उत्पादन में भी स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़े। लेकिन भारत की चुनौतियां यूरोप और चीन से अलग हैं। चीन ने इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बड़े पैमाने पर सरकारी सब्सिडी, बैटरी उत्पादन, सार्वजनिक खरीद और विनिर्माण क्षमता के सहारे विकसित किया। यूरोप ने भी कठोर उत्सर्जन नियमों और प्रोत्साहनों के जरिए बाजार को दिशा दी। भारत में नीति-स्तर पर फेम जैसी योजनाएं और राज्य सरकारों की इलेक्ट्रिक वाहन नीतियाँ आई हैं, लेकिन अभी भी बुनियादी ढाँचे की कमी बड़ी बाधा है। चार्जिंग स्टेशन सीमित हैं, बैटरियों की लागत अधिक है और उपभोक्ताओं के मन में अब भी यह आशंका बनी हुई है कि लंबी दूरी की यात्रा के दौरान बैटरी खत्म होने पर चार्जिंग सुविधा समय पर मिलेगी या नहीं। ग्रामीण और छोटे शहरों में यह चुनौती और अधिक जटिल है। इसलिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहन परिवर्तन केवल बाजार के भरोसे नहीं हो सकता, इसके लिए नीति और निवेश दोनों की निरंतर जरूरत होगी।

(ये लेखक के निजी विचार हैं।)

स्वामी, परिजात माइनिंग इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) प्रा. लि. के लिए प्रकाशक एंव मुद्रक हर्षवर्द्धन बजाज द्वारा इसके पब्लिकेशन डिवीजन, रेड़मा मेदिनीनगर (डालटनगंज), से प्रकाशित एवं एस एच प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में शिवासाई पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड), नियर टेंडर बागीचा पेट्रोल पम्प, रातू, रांची-835222, झारखंड द्वारा मुद्रित. रजिस्ट्रेशन नं. 61316/94 पोस्टल रजिस्ट्रेशन नं.-13 । प्रधान संपादक : सुरेश बजाज, संपादक : हर्षवर्द्धन बजाज, कार्यकारी संपादक : सुनील सिंह 'बादल', सह कार्यकारी संपादक : प्रवीण कुमार दूबे, स्थानीय संपादक : डॉ राणा अरुण सिंह*, प्रेस कार्यालय : रांची रोड, रेड़मा, मेदिनीनगर, (डालटनगंज) पलामू-822102, फोन नम्बर : 06562-796018, रांची कार्यालय : 502बी, पांचवी मंजिल मंगलमूर्ति हाईट्स, रानी बगान, हरमू रोड, रांची-834001, फोन नं.- 0651-3553943, लोहरदगा कार्यालय : सरस्वती निवास, तेली धर्मशाला के सामने, कृषि मार्केट, लोहरदगा। - फोन : 7903891779, ई-मेल : समाचार - news.rnmail@gmail.com, लेख - article.rnmail@gmail.com (*पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेवार।)

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला

डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगा कफ सिरप

- **छोटे गांवों में भी अब इन दवाओं को बिना लाइसेंस नहीं बेचा जा सकेगा**

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए औषधि नियम, 1945 में संशोधन कर दिया है। अब छोटे गांवों (1000 से कम आबादी वाले) में बिना लाइसेंस के खांसी की सिरप बेचना अवैध हो गया है। साथ ही अब डॉक्टर की पर्ची के बिना कफ सिरप नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी खांसी की दवाइयों के निर्माताओं, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वे नए नियमों का कड़ाई से पालन करें। किसी भी प्रकार की अनदेखी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह संशोधन दिसंबर 2025 में अधिसूचित किया गया था और अब पूरे देश में लागू माना जाएगा। इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में भी दवाइयों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी, खासकर बच्चों को दी जाने वाली खांसी की सिरप को लेकर। अब उपभोक्ताओं को ऐसी दवा खरीदने के लिए रजिस्टर्ड डॉक्टर के वैध प्रिस्क्रिप्शन (पर्ची) की जरूरत होगी।

अब लाइसेंस प्राप्त फार्मेसी से ही मिलेगी सिरप

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना जीएसआर 927 (ई) के माध्यम से यह संशोधन अधिसूचित किया है। इस अधिसूचना के तहत औषधि नियम, 1945 की अनुसूची 'क' की प्रविष्टि संख्या 13 से 'सिरप' शब्द को हटा दिया गया है। इससे पहले 1000 से कम जनसंख्या वाले गांवों में खांसी की दवा (सिरप) की बिक्री पर कुछ छूट दी गई थी। इन क्षेत्रों में खुदरा बिक्री लाइसेंस की जरूरत नहीं थी, जिसके कारण आसानी से इन दवाइयों की बिक्री हो जाती थी। अब यह छूट पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है।संशोधन के बाद खांसी की सिरप की बिक्री और वितरण अब केवल औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 तथा औषधि नियम, 1945 के तहत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही वैध होगा। छोटे गांवों में भी अब इन दवाइयों को बिना लाइसेंस नहीं बेचा जा सकेगा। मंत्रालय के अनुसार, यह कदम खांसी की सिरप बनाने और बेचने की प्रक्रिया पर नियामक निगरानी को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। इससे दवाइयों के जिम्मेदार वितरण को बढ़ावा मिलेगा और पूरे देश में नियामक मानकों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित होगा।

वोटर कार्ड और अन्य दस्तावेजों में आधार के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान

आधार का इस्तेमाल पहचान का प्रमाण, नागरिकता का नहीं : याचिका

- **सुप्रीम कोर्ट ने आधार के उपयोग संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी**
- **याचिका में आधार को केवल पहचान प्रमाण के रूप में सीमित रखने की मांग की गई है**

एजेंसी। नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई। इस याचिका में केंद्र सरकार, सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों और भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश देने की मांग की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आधार का इस्तेमाल केवल पहचान के सबूत के तौर पर हो न कि नागरिकता, निवास, पते या जन्मतिथि के सबूत के तौर पर।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों व केंद्रशासित प्रदेशों, ईसीआई और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) को नोटिस जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी।याचिका में कहा गया है कि आधार अधिनियम, 2016 की धारा 9 साफ तौर पर कहती है कि आधार नागरिकता या निवास का सबूत नहीं है जबकि यूआईडीएआई की सूचनाएं स्पष्ट करती हैं कि आधार केवल पहचान का सबूत है न कि नागरिकता, पते या जन्मतिथि का सबूत।याचिका में दावा किया गया है कि कथित घुसपैठिए और अवैध प्रवासी कमजोर वेरिफिकेशन सिस्टम के जरिए आधार कार्ड हासिल कर लेते हैं और बाद में आधार का इस्तेमाल राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर पहचान पत्र जैसे अन्य पहचान और हकदारी वाले दस्तावेज पाने के लिए करते हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, यह प्रक्रिया आधार अधिनियम के तहत बनाए गए पहचान फ्रेमवर्क की विश्वसनीयता को कमजोर करती है और अयोग्य लोगों को सब्सिडी, कल्याणकारी योजनाओं और कानूनी लाभार्थियों के लिए बने अन्य लाभों का फायदा उठाने में मदद करती है। याचिका में कहा गया है कि ऐसी प्रक्रियाओं से सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल होता है।

वोटर पंजीकरण में आधार उपयोग को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

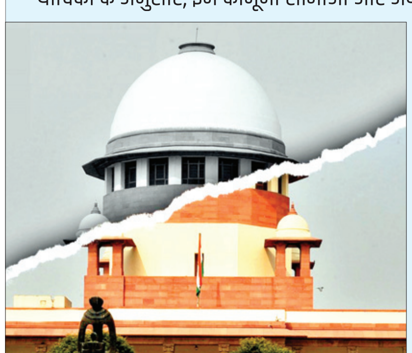

याचिका के अनुसार, इन कानूनी सीमाओं और अदालती फैसलों के बावजूद कि आधार उम्र का सबूत नहीं है, इस दस्तावेज को स्कूल में दाखिले, प्रॉपर्टी के लेनदेन, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने जैसे कई कामों के लिए उम्र, निवास, नागरिकता और निवास स्थान के सबूत के तौर पर बड़े पैमाने पर स्वीकार किया जाता रहा है। पीआईएल में खास तौर पर नए वोटर रजिस्ट्रेशन (फॉर्म-6) के लिए आवेदन फॉर्म में जन्मतिथि और निवास के सबूत के तौर पर आधार के इस्तेमाल को चुनौती दी गई है। इसमें तर्क दिया गया है कि ऐसा इस्तेमाल आधार अधिनियम, यूआईडीएआई की सूचनाओं और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है। याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने केंद्र सरकार, राज्यों और ईसीआई से निर्देश जारी करने की मांग की है कि वे यह पक्का करने के लिए उचित कदम उठाएं कि आधार का इस्तेमाल सख्ती से पहचान के सबूत के तौर पर ही हो, न कि उन कामों के लिए जो आधार अधिनियम और यूआईडीएआई दिशानिर्देशों के तहत मना हैं। आधार एनरोलमेंट फ्रेमवर्क का हवाला देते हुए, याचिका में तर्क दिया गया है कि सभी निवासी, जिनमें भारत में कम से कम 182 दिनों से रह रहे विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, आधार पाने के हकदार हैं। इसमें आगे कहा गया है कि आधार एनरोलमेंट कॉमन सर्विस सेंटर्स और रेंट एग्रीमेंट या स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों जैसे सहायक दस्तावेजों के माध्यम से किया जा सकता है।

पूर्वोत्तर एसटी आयकर छूट चुनौती पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आयकर अधिनियम, 2025 के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय को दी गई आयकर छूट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने कहा कि यह मामला मूल रूप से कानून बनाने और नीतिगत फैसलों से जुड़ा है। अदालत ने याचिकाकर्ता को अपनी चिंताओं को संबंधित सरकारी अधिकारियों और संसद की समितियों के सामने रखने की सलाह दी।

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, "यह शिकायत मुख्य रूप से विधायी (कानून से जुड़ा) मुद्दा है। संसद में ऐसी समितियां हैं, जहां कोई भी नागरिक कानूनों में सुधार या नए सुझाव दे सकता है। हमें विश्वास है कि जनप्रतिनिधि इन मुद्दों से अवगत हैं और इस पर विचार करेंगे।"यह याचिका अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दाखिल की थी। उन्होंने या तो इस कर छूट प्रावधान को रद्द करने या फिर 'क्रीमी लेयर' व्यवस्था लागू करने की मांग की थी, ताकि केवल आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जनजाति के लोगों को ही इसका लाभ मिल सके।याचिका में आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 11 और अनुसूची-3 की क्रम संख्या 19 को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के अधिसूचित इलाकों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों को बिना किसी आय सीमा, संपत्ति संबंधी शर्त, क्रीमी लेयर नियम या समय-समय पर समीक्षा के आयकर से पूरी छूट दी जा रही है। याचिका के अनुसार, यह छूट पहले आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(26) के तहत उन जनजातीय समुदायों की सुरक्षा के लिए दी गई थी, जो भौगोलिक रूप से दूरदराज और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में रहते थे। लेकिन पिछले दो दशकों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है, जिससे परिस्थितियां बदल चुकी हैं।

केंद्र सरकार की रोक से गूगल प्ले स्टोर से हटाया गया टेलीग्राम एप्पल ऐप स्टोर पर अब भी उपलब्ध

- **फर्जी टेलीग्राम चैनलों, समूहों और बॉट्स पर कई सप्ताह से निगरानी और कार्रवाई जारी थी**

एजेंसी। नई दिल्ली

नीट (यूजी) 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार द्वारा टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने के फैसले के बाद यह ऐप भारत में गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। इस वजह से नए यूजर्स फिलहाल गूगल के आधिकारिक एंड्रॉएड ऐप स्टोर के जरिए टेलीग्राम डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। यह कदम परीक्षा से जुड़े कथित फर्जीवाड़े, गलत जानकारी फैलाने और नकल के नेटवर्क को रोकने के लिए उठाया गया है, जो कथित रूप से टेलीग्राम के माध्यम से संचालित हो रहे थे। हालांकि, टेलीग्राम अभी भी एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। यह घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी प्रतिबंध लगाया था। सरकार का कहना है कि यह कदम 21 जून को होने वाली नीट (यूजी) पुनर्परीक्षा से पहले परीक्षा से जुड़े फर्जीवाड़े, गलत सूचना अभियानों और नकल के नेटवर्क को रोकने के लिए जरूरी था। एनटीए के अनुसार, यह प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत लगाया गया है और यह परीक्षा अवधि तथा उसके तुरंत बाद के समय तक लागू रहेगा।एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम के कई चैनल और समूह कथित रूप से परीक्षा पेपर लीक से जुड़े भ्रामक दावे फैलाने और छात्रों को प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने के नाम पर ठगने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। अस्थायी प्रतिबंध के अलावा टेलीग्राम को भारत में अपने संदेश संपादन (मैसेज एडिटिंग) फीचर को भी 30 जून तक बंद करने का निर्देश दिया गया है।

गोशालाएं बनेंगी ग्रामीण उद्योगों का नया केंद्र, जिले को मिलेगी अपनी पहचान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में गो संरक्षण को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन से जोड़ने की दिशा में योगी सरकार ने नई पहल शुरू की है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में स्थानीय संसाधनों और जरूरतों के अनुरूप एक प्रमुख गो-आधारित उद्योग विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग ने इसके लिए प्रदेशभर की गोशालाओं का व्यापक मूल्यांकन पूरा कर लिया है और अब "एक जनपद-एक नवाचार" मॉडल के तहत जिला विशेष योजनाओं को अमल में लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप शुरू की जा रही इस पहल का उद्देश्य गोशालाओं को केवल निराश्रित गोवंश के संरक्षण केंद्र तक सीमित न रखकर उन्हें उत्पादन, रोजगार, प्राकृतिक खेती और ग्रामीण उद्यमिता के सशक्त केंद्रों के रूप में विकसित करना है। इसके लिए प्रदेश की गोशालाओं में उपलब्ध भूमि, गोवंश, जल संसाधन, पंचगव्य इकाइयों तथा स्थानीय बाजार की संभावनाओं का विस्तृत अध्ययन किया गया है।

वायु सेना स्वदेशी कामिकेज ड्रोन करेगी विकसित

16,000 फीट की ऊंचाई पर भर सकेंगे उड़ान

एजेंसी। नई दिल्ली

भारतीय वायु सेना ने स्वदेशी लंबी दूरी के स्वदेशी कामिकेज (वन-वे अटैक) ड्रोन विकसित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। यह ड्रोन भारतीय उद्योग के सहयोग से तैयार किए जाएंगे। वायु सेना ने वन-वे अटैक अनमैन्ड एरियल सिस्टम के लिए भारतीय कंपनियों के चयन हेतु सीमित टेंडर जारी किया है। यह कामिकेज ड्रोन परियोजना तमिलनाडु के कोयंबटूर के पास सुलूर स्थित 5 बेस रिपेयर डिपो द्वारा संभाली जाएगी, जिसे इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।कामिकेज ड्रोन को 'लोइटरिंग म्यूनिशन' या 'आत्मघाती ड्रोन' भी कहा जाता है। ये एक तरफा (वन-वे) मानव रहित हवाई वाहन होते हैं, जो लक्ष्य क्षेत्र तक पहुंचकर दुश्मन की पहचान करते हैं और टकराकर विस्फोट कर देते हैं।

रक्षा मंत्रालय के फैसले के अनुसार, इस ड्रोन प्लेटफॉर्म के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारतीय वायु सेना के पास रहेंगे। इसे पूरी तरह भारत में ही घरेलू कंपनियों और स्टार्टअप्स की मदद से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जाएगा। इस परियोजना से जरूरत के अनुसार तेज अपग्रेड, बदलाव और अनुकूलन संभव होगा। आईएएफ के अनुसार, यह लंबी दूरी के कामिकाजे ड्रोन 16,000 फीट तक की ऊंचाई पर काम कर सकेंगे और दिन-रात दोनों समय में संचालित होंगे। पहले नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत को ड्रोन निर्माण में वैश्विक केंद्र बनने के लिए मिशन मोड में काम करना चाहिए।उन्होंने कहा था कि यह रणनीतिक स्वतंत्रता और रक्षा तैयारी को मजबूत करने के लिए जरूरी है और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध से लेकर ईरान-इजराइल तनाव तक हाल के संघर्ष दिखाते हैं कि भविष्य के युद्धों में ड्रोन और एंटी-ड्रोन तकनीक की भूमिका बहुत अहम होगी।उन्होंने यह भी कहा कि भारत में ड्रोन निर्माण केवल अंतिम उत्पाद तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके हर हिस्से (कंपोनेंट) का निर्माण भी देश में होना चाहिए।उन्होंने कहा, "ड्रोन के मोल्ड्स से लेकर सॉफ्टवेयर, इंजन और बैटरी तक सब कुछ भारत में ही बनना चाहिए। यह आसान काम नहीं है, क्योंकि कई देशों में ड्रोन के महत्वपूर्ण हिस्से अभी भी चीन से आयात किए जाते हैं।" उन्होंने बताया कि भारत के रक्षा नवाचार इकोसिस्टम में स्टार्टअप्स और एमएसएमई की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।

योजना | अल नीनो से निपटने के लिए कृषि मंत्रालय ने तैयार की रणनीति, हर हफ्ते होगी बैठक

कम वर्षा वाले जिलों के लिए विशेष रणनीति बनेगी

- **जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, इंटरक्रॉपिंग और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर ध्यान देने का निर्देश**

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कृषि भवन में उच्चस्तरीय बैठक कर संभावित अल नीनो परिस्थितियों से निपटने की रणनीति की समीक्षा की। उन्होंने कपास का उत्पादन बढ़ाने, दलहन में आत्मनिर्भरता और कम बारिश वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजना पर विशेष जोर दिया। अल नीनो की संभावित स्थिति पर चर्चा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने साफ निर्देश दिया कि जिन जिलों में कम बारिश या वर्षा में असमानता की आशंका है। ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान कर राज्य सरकारों के साथ मिलकर फसलवार कंटिंजेंसी प्लान तैयार किए जाएं, ताकि किसी भी मौसमीय चुनौती की स्थिति में किसानों को तुरंत विकल्प, सलाह और सहायता उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि पानी के संरक्षण, नमी प्रबंधन, इंटरक्रॉपिंग और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान देते हुए हर जोखिम वाले जिले के लिए अलग और व्यावहारिक रणनीति बनाई जाए। चौहान ने यह भी निर्देश दिए कि जिन 9–10 राज्यों में अल नीनो का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक पड़ सकता है, वहां के चिह्नित जिलों के जिला अधिकारियों, कृषि विभाग, केवीके और अन्य विस्तार तंत्र के साथ समन्वित बैठकें आयोजित की जाएं। जिला स्तर पर पूरी स्थिति स्पष्ट कर किसानों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि हर किसान को यह पता रहे कि उसके क्षेत्र के लिए कौन-सी सावधानियां और कौन-से फसल विकल्प अधिक सुरक्षित हैं। चौहान ने पत्रकारों से कहा कि खतरे को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने के बजाय, वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर शांत, भरोसेमंद और समाधान-उन्मुख संदेश किसानों तक पहुंचे, यही सरकार की प्राथमिकता है।

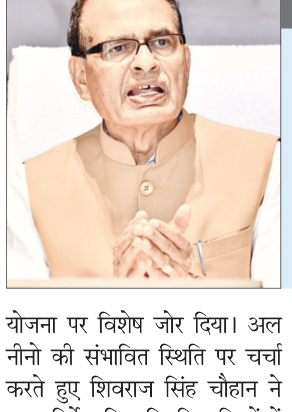

मानसून की रफ्तार के साथ आपूर्ति चुस्त-दुरुस्त रखी जाएगी

चौहान ने सरकार का प्रयास है कि अरहर, उड़द, मूंग जैसी दालों में देश अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बने और आयात पर निर्भरता कम हो। इसके लिए राज्यों के साथ मिलकर फसल चक्र, क्षेत्र विस्तार, बेहतर बीज उपलब्धता और तकनीकी मार्गदर्शन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसान सुरक्षित आय के साथ दलहन उत्पादन बढ़ा सकें। समीक्षा के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता, बाजार में मंडी भाव, जलाशयों एवं जल भंडारण की स्थिति और राज्यवार स्टॉक की जानकारी भी प्रस्तुत की गई। चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर उर्वरक उपलब्धता है और जैसे-जैसे मानसून की रफ्तार बढ़ेगी, राज्यों और जिलों तक आपूर्ति को और चुस्त-दुरुस्त रखा जाएगा। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देने के साथ ही इस पर भी जोर दिया कि जहां कहीं भी सूक्ष्म स्तर पर कमी की आशंका दिखे, वहां अग्रिम रुप से आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

दृष्टिपात

जमात-ए-इस्लामी हिंद ने देशभर में चल रहे विध्वंस अभियान को रोकने की मांग की

नई दिल्ली। जमात-ए-इस्लामी हिंद (जेआईआईएच) के नेताओं ने मंगलवार को देश भर में चल रहे विध्वंस अभियानों, अमेरिका-ईरान शांति समझौते, राज्यसभा चुनावों की निष्पक्षता और पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। मीडिया को संबोधित करते हुए जेआईआईएच के उपाध्यक्ष मलिक मोतसिम खान और अन्य नेताओं ने नागरिक समाज, मानवाधिकार संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों से इन मुद्दों का संज्ञान लेने और प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता दिखाने का आग्रह किया। जमात-ए-इस्लामी हिंद ने दोहराया कि सभी नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा करना राष्ट्र के संवैधानिक और लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखने के लिए मौलिक है। मलिक मोतासिम खान ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में दिल्ली, बांद्रा, फरीदाबाद, विरामगाम (गुजरात), गोरेगांव (महाराष्ट्र), वाराणसी, संभल, जयपुर, भायंदर, पीसीएमसी और इटावा में तोड़फोड़ अभियान चलाए गए। उन्होंने आगे कहा कि पिंपरी चिंचवड में अधिकारियों ने कई धार्मिक ढांचों को नोटिस जारी किए और देर रात चलाए गए अभियान में कई ढांचों को ध्वस्त कर दिया। सूरत के नासिर नगर में तीन दिनों में 106 मकान ध्वस्त किए गए और जयपुर में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत नूरानी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कई प्रभावित परिवार बिना उचित आश्रय और पुनर्वास संबंधी किसी स्पष्ट जानकारी के वंचित रह गए हैं।

राम मंदिर के दानपात्र में करते हैं घपलेबाजी और हमें पढ़ाते हैं मूल्यों का पाठ : अधीर रंजन

मुर्शिदाबाद। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राम मंदिर दानपात्र के घपलेबाजी में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। ऐसी घटनाओं को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राम मंदिर के निर्माण के लिए सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनियाभर के श्रद्धालुओं ने अपने कदम आगे बढ़ाए थे। सभी ने खुल दिल से राम मंदिर के निर्माण में अपनी कमाई का हिस्सा योगदान के रूप में दिया था, क्योंकि सभी के जेहन में इस बात को लेकर खुशी थी कि इतने लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या नगरी में राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसी को देखते हुए लोगों ने खुले दिल से योगदान दिया था। अब जब राम मंदिर के दानपात्र में घपलेबाजी का मामला सामने आया है, तो मैं फिर से इस बात को दोहराते हुए कह रहा हूं कि इस घपलेबाजी में शामिल लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर हमारे देश में राम मंदिर के दानपात्र में घपलेबाजी हो रही है, तो आप इस बात का अंदाजा सहज ही लगा सकते हैं कि सिस्टम कितना लचर हो चुका है। इसके बावजूद कुछ लोग इन सब बातों को भूलकर सिर्फ हमें तथ्यों और मूल्यों का पाठ पढ़ा रहे हैं। अब ऐसे में मेरा सवाल है कि क्या हम इन तथ्यों और मूल्यों को स्वीकार कर सकते हैं। एक तरफ जहां आप आस्था के नाम पर इतना बड़ा घोटाला करते हैं।

सीबीआई ने आईडीएफसी धोखाधड़ी मामले में पहला आरोप पत्र दाखिल किया

चंडीगढ़। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को चंडीगढ़ के विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) की अदालत में चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्निकल प्रमोशन सोसाइटी (सीआरईएसटी) के फंड के दुरुपयोग के संबंध में पहला आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अधिकारी, क्रेईएसटी के लोक सेवक और निजी व्यक्ति शामिल हैं। कुल 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं, जिनमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 5 बैंक अधिकारी, सीआरईएसटी (चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन) के 2 सरकारी कर्मचारी, 2 फर्जी कंपनियां और 4 निजी व्यक्ति शामिल हैं। सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी, साक्ष्य नष्ट करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। वर्तमान मामला सरकारी निधि के दुरुपयोग से संबंधित है, जिसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अधिकारियों द्वारा सीआरईएसटी के सरकारी कर्मचारियों के साथ आपराधिक मिलीभगत से सीआरईएसटी के बैंक खातों से 75.34 करोड़ रुपए की राशि निकाली गई।

गठबंधन की लुटिया डुबोने वाली कांग्रेस अब गठबंधन का पाठ पढ़ा रही : रोहन गुप्ता

अहमदाबाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा इंडिया गठबंधन के नेताओं को दी गई नसीहत पर भाजपा नेता रोहन गुप्ता ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस पर अपने राजनीतिक हितों के लिए सहयोगी दलों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज वही पार्टी दूसरों को गठबंधन धर्म का पाठ पढ़ा रही है, जिसने स्वयं इंडिया गठबंधन को कमजोर किया है। रोहन गुप्ता ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने इंडी गठबंधन की लुटिया डुबो दी, आज वही अपने सहयोगी दलों को सलाह दे रही है। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के बाद इंडिया गठबंधन पूरी तरह बिखर चुका है। हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने निजी स्वार्थों के चलते गठबंधन के साथियों के हितों की अनदेखी की। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि वह इंडिया गठबंधन का उपयोग अपनी सत्ता बचाने के लिए कर रही है या वास्तव में सहयोगी दलों के हितों के लिए।

ईरान-अमेरिका युद्धविराम समझौते में इजरायल, हिज्बुल्लाह भी पक्ष हैं : अराग्ची

तेहरान। ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता ज्ञापन पर शुक्रवार को हस्ताक्षर से पहले आज स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस समझौते में इजरायल और हिज्बुल्लाह भी पक्ष हैं तथा लेबनान में लड़ाई रोकना इस समझौते का जरूरी हिस्सा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने मंगलवार को यहां विदेशी राजनयिक मिशनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा कि ईरान, लेबनान के संगठन हिज्बुल्लाह के साथ-साथ इजरायल को भी अमेरिका के साथ हुए समझौते का एक पक्ष मानता है। अराग्ची ने कहा, "मैं एक ज़रूरी बात पर ज़ोर देना चाहता हूं। हमारे नज़रिए से, समझौते का एक पक्ष अमेरिका और इजरायल है और दूसरा पक्ष ईरान और हिज्बुल्लाह है। लेबनान में लड़ाई रोकना, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने का एक ज़रूरी हिस्सा है।"ईरान के शीर्ष राजनयिक ने कहा, "इस युद्ध के दौरान कब्ज़े में लिए गए इलाकों से इजरायली सेना के हटे बिना, युद्ध को पूरी तरह खत्म नहीं माना जा सकता। लेबनान पर इजरायल का कोई भी हमला समझौते का उल्लंघन माना जाएगा।

तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने किया हमला, ट्रंप बोले-रूस को अब समझौता कर लेना चाहिए

नई दिल्ली। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल से मॉस्को क्षेत्र को निशाना बनाने का दावा कयिा। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने मॉस्को क्षेत्र में करीब 500 किलोमीटर दूर स्थित एक तेल रिफाइनरी पर हमला कयिा। यह हमला रूस पर दबाव बढ़ाने और युद्ध समाप्त करने की रणनीति का हिस्सा है। यूक्रेन का ये हमला रूस के एक दिन पहले कएि गए हमलों के जवाब कयिा गया। रूस ने रविवार की रात 70 मिसाइलों और 611 ड्रोन की मदद से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कएि। इन हमलों में 60 से अधिक मिसाइलें तो राजधानी कीव में ही दागी गईं। इन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि कीव में 35 लोग घायल हुए हैं। पूरे देश में 53 लोग घायल बताए गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बताया, ''इस बार मॉस्को ने भी यूक्रेन की लंबी दूरी तक मार करने वाली क्षमताओं का असर देखा। लगभग 500 किलोमीटर दूर स्थित उसकी एक तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया।''

'मलबे से निकली गुड़िया पर जमी खून की बूंदें'

● साम्राज्यवादी सनक का खूनी महासंग्राम : ट्रंप-नेतन्याहू की 'ईरान फतह' की क्रूर जिद ने मध्य पूर्व को बनाया श्मशान, मध्यावधि चुनाव के खौफ में ट्रंप ने खींचे हाथ, गिड़गिड़ाते नेतन्याहू को बंद कमरे में डांटा!

● 857 जलते स्कूलों के मलबे में दफन हुआ मासूम बचपन; पेगासस व इजरायली मिसाइलें चीन-ईरान की तकनीक के आगे ढेर; होर्मुज की नाकेबंदी से बढ़ी वैश्विक महंगाई ने छीना दुनिया के दो अरब गरीबों के मुंह का निवाला!

कृष्णमोहन सिंह

नई दिल्ली। इतिहास के पन्नों पर जब भी सत्ता के गलियारों में बैठे तानाशाह संप्रभु राष्ट्रों की तकदीर व उनके तेल भंडारों को लूटने का बंद कमरों में नक्शा बनाते हैं, तो उसकी कीमत अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे सैनिकों की लाशें और भूख से बिलखते मासूम बच्चे चुकाते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कानों में एक आत्मघाती मंत्र फूंका था—"खामेनेई के मरते ही ईरान के बागी गुट हमारे तलवे चाटने लगेंगे, एक महीने में तेहरान पर हमारा कब्जा होगा, वहां अपनी पपेट (कठपुतली) सरकार बिठाएंगे और तेल के कुओं की चाबी वाशिंगटन के हाथ में होगी।" इस लालच व अहंकार में आकर ट्रंप ने इजरायल को बारूद का ऐसा खुला चेक दिया कि देखते ही देखते यह परोक्ष युद्ध सीधे 'अमेरिका बनाम ईरान' के आत्मघाती महासंग्राम में बदल गया। आज छह हफ्तों की उस खूनी तबाही के बाद युद्धविराम तो हो गया है, लेकिन पीछे छूट गया है आधी दुनिया का आर्थिक विनाश व करोड़ों बिलखते परिवारों की अंतहीन चीखें।

हिंद महासागर का वो काला दिनः भारत की 'मेहमान नवाजी' पर अमेरिकी मिसाइल का प्रहार- इस युद्ध का सबसे शर्मनाक व रूह कंपा देने वाला अध्याय भारत की दहलीज पर, हिंद महासागर में लिखा गया। भारतीय नौसेना के एक विशेष समारोह में 'राजकीय मेहमान' के तौर पर शामिल होने आया ईरानी नौसैनिक युद्धपोत (आईआरआईएस मकरान और उसके सहयोगी दस्ते) जब उत्सव के बाद वापस ईरान लौट रहा था, तब अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अमेरिकी युद्धपोत ने उस पर गाइडेड मिसाइल दाग दी। पल भर में समुद्र का नीला पानी ईरानी नौसैनिकों के खून से लाल हो गया। इस कायरतापूर्ण हमले में ईरान के 180 से अधिक जांबाज नौसैनिक व उच्च अधिकारी जिंदा जल गए या समंदर की गहराइयों में दफन हो गए।हैरत और अफसोस की बात यह थी कि जब यह हमला हुआ, तो भारत की धरती से मदद नहीं पहुंची। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका अपनी नौसेना के साथ इन डूबते हुए नौसैनिकों को बचाने और शवों को निकालने के लिए समंदर में कूद पड़ा।

यह कूटनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा 'सरेंडर' था। पाकिस्तान के साथ हुए पिछले तनावों के समय से ही ट्रंप ने भारत को जिस तरह दबाकर रखा है, उसका खौफ इस घटना में साफ दिखा।

आंकड़े नहीं, ये रूह को कंपा देने वाले जख्म हैं (जून 2026 तक का डेटा)-
जब हम सत्ता के भूखे हुक्मरानों के इस खेल का डेटा विश्लेषण करते हैं, तो आँखें पथरा जाती हैंः

- **ईरान की बर्बादी:** छह हफ्तों में ईरान को **140 से 145 अरब डॉलर** का सीधा आर्थिक नुकसान हुआ। **2,076 से अधिक सैनिक और नागरिक** मारे गए, जबकि **26,500 से अधिक लोग** जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए।
- **मलबे में तब्दील होते आशियाने: 1,00,000 से अधिक घर** और **23,500 व्यावसायिक दुकानें** मलबे का ढेर बन गईं। लाखों परिवार सड़कों पर आ गए।
- **बचपन पर बारूदी प्रहार: 857 स्कूल व शिक्षा केंद्र, 32 विश्वविद्यालय** और **339 अस्पताल** जमींदोज कर दिए गए। खोजीर, परचीन, हाकिमिया और शाहरुद जैसे मुख्य सैन्य उत्पादन केंद्र तबाह तो हुए, लेकिन ईरान का हौसला नहीं टूटा।

"मलबे से निकली गुड़िया पर जमी खून की बूंदें"- इस युद्ध की सबसे मर्मांतक तस्वीरें तेहरान और शिराज की उन गलियों से आईं, जहां स्थित **857 स्कूलों** पर इजरायली और अमेरिकी मिसाइलें गिरीं। सुबह जो मासूम बच्चियां अपनी सहेलियों के साथ कॉपियां और रंगीन पेंसिलें लेकर स्कूल गई थीं, दोपहर को मलबे से सिर्फ उनकी क्षत-विक्षत लाशें निकलीं। किसी की फ्रॉक खून से सनी थी, तो किसी के नन्हे हाथों में उसकी पसंदीदा गुड़िया अब भी दबी रह गई थी।अपनी बेटियों के बिखरे बस्ते और टूटे हुए जूतों को छाती से लगाकर दहाड़ें मारती माताओं की चीखें कूटनीति के बहरे कानों तक नहीं पहुंचतीं। जिन बच्चों को कल देश का भविष्य बनना था, वे आज बिना हाथ-पैर के अस्पतालों के टूटे बिस्तरों पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं।इस साम्राज्यवादी जंग ने दुनिया के **दो अरब आम और गरीब लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz)** की नाकेबंदी के कारण कच्चे तेल की कीमतों में जो आग लगी, उसने वैश्विक स्तर पर महंगाई का वो तांडव रचा कि गरीब की थाली से दाल-रोटी गायब हो गई। अफ्रीका के भूख से तड़पते गांवों से लेकर एशिया व भारत के स्लम इलाकों तक, अनाज, दूध और जीवन रक्षक दवाइयां इतनी महंगी हो गईं कि आज लाखों बेबस माता-पिता अपने बीमार बच्चों को सिर्फ इसलिए दम तोड़ते देखने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। तानाशाहों की इस जंग ने वैश्विक मानवता को एक दशक पीछे धकेल दिया है।

चुनाव का खौफ, सड़कों पर विद्रोह व नेतन्याहू को ट्रंप की डांट- ट्रंप का यह सोचना कि ईरान एक महीने में घुटने टेक देगा, उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई। इस युद्ध में अमेरिका के कई आधुनिक युद्धपोत, अरबों डॉलर के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और अत्याधुनिक गोला-बारूद स्वाहा हो गए। सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों के शव जब ताबूतों में बंद होकर वॉशिंगटन पहुंचे, तो अमेरिकी जनता का गुस्सा फूट पड़ा।न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया की सड़कों पर लाखों अमेरिकी नागरिक **"Stop This War"** के नारे लगाते हुए उतर आए। चूंकि अमेरिका में **मध्यावधि चुनाव (Midterm Elections)** बिल्कुल सिर पर हैं और ट्रंप को अपनी सत्ता जाती हुई साफ दिख रही थी, इसलिए उन्हें मजबूरी में इस युद्ध को रोकना पड़ा। यह युद्धविराम इजरायल की मर्जी के खिलाफ था। सूत्रों के अनुसार, जब नेतन्याहू ने इसका विरोध किया, तो आगबबूला ट्रंप ने उन्हें फोन पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहाः **"अगर अमेरिका तुम्हारे पीछे नहीं खड़ा होता, तो इजरायल अब तक दुनिया के नक्शे से मिट चुका होता। अपनी हद में रहो और जंग बंद करो!"**

बदला दुनिया का भूगोलः चीन का महाशक्ति के रूप में राज्याभिषेक- इस युद्ध ने दुनिया के सामने एक कड़वा और ऐतिहासिक सच उजागर कर दिया है—**इजरायल का विश्व प्रसिद्ध 'पेगासस' जासूसी तंत्र और उसकी अजेय समझी जाने वाली सैन्य तकनीक, ईरान के दृढ़ संकल्प और चीन-रूस के बैक-एंड तकनीकी सहयोग के आगे पूरी तरह नाकाम और कमतर साबित हो गए।** पश्चिमी देशों का एकध्रुवीय (Unipolar) साम्राज्य अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। अमेरिका इस युद्ध में अपने संसाधन और साख गंवाकर कमजोर हुआ है, जबकि **चीन बिना एक भी गोली चलाए दुनिया का सबसे शक्तिशाली 'ग्लोबल अंपायर' बनकर उभरा है।**

मध्य पूर्व से लेकर एशिया तक, अब हर बड़ा आर्थिक और रणनीतिक फैसला बीजिंग की मर्जी से हो रहा है। रूस-चीन-ईरान का यह नया ध्रुवीकरण अमेरिकी दादागिरी के ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ है। और इन सबके बीच कागजों पर हुआ यह युद्धविराम उन पिताओं के कंधों का बोझ कम नहीं कर सकता, जिन्होंने अपने मासूम बच्चों के छोटे-छोटे जनाजे उठाए हैं।

पीएम मोदी 16 महीने बाद ट्रंप से मिले : फ्रांस में जी7 समिट में साथ बैठे, 5 मिनट बात की, कल ट्रेड डील पर बात संभव

एजेंसी । नई दिल्ली/एवियन

पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की फ्रांस के एवियन शहर में जी-7 समिट के दौरान मुलाकात हुई। दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक बात की। मीटिंग में दोनों एक-साथ बैठे नजर आए। यह मुलाकात 16 महीनों के बाद हुई है। प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति जी7 आउटरीच सेशन में भी साथ-साथ बैठे। इससे पहले आखिरी मुलाकात फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस में हुई थी।

दोनों नेता 17 जून की शाम 6:30 बजे ट्रेड डील पर चर्चा कर सकते हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत-अमेरिका के बीच टैरिफ, निवेश और रणनीतिक साझेदारी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। जी-7 समिट के लिए मंगलवार दोपहर एवियन पहुंचने पर मोदी का फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने स्वागत किया। जी-7 के देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान मोदी ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर, कनाडा के पीएम मार्क कार्नी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से बातचीत करते दिखाई दिए। पार्टनर देश के तौर पर शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं मौजूदगी है। साथ ही यह 7वीं बार है जब प्रधानमंत्री इस ग्लोबल फोरम में हिस्सा ले रहे हैं। फ्रांस पहुंचने से पहले, प्रधानमंत्री ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में कुछ देर के लिए रुककर स्विस परिसंघ के राष्ट्रपति गाइ परमेलिन से मुलाकात की और अपनी यूरोपीय कूटनीतिक यात्रा की शुरुआत की।

ग्रुप फोटो सेशन के बीच मोदी ने इटली की पीएम मेलोनी से मुलाकात की, दो महीने के अंदर यह दोनों की दूसरी मुलाकात है

जी7 समिट में 12 देशों के नेता हिस्सा ले रहे : जी7 समिट में इसके सदस्य देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के नेता शामिल होंगे। इसके अलावा यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेंगे। फ्रांस ने समिट में जी7 देशों के अलावा कई अन्य देशों के नेताओं को भी सम्मेलन में आमंत्रित किया है। इनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज, नासियो लूला दा सिल्वा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यंग, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो भी शामिल हैं।

दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनी का फैसला, 'तुरंत होर्मुज नहीं भेजेंगे जहाज'

नई दिल्ली । यूएस-ईरान पीस डील पर सहमति बनने के बाद भी दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनी ने फिलहाल होर्मुज से अपने जहाज न भेजने का ऐलान किया है। जापान की मित्सुई ओएसके लाइन्स (एमओएल) का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने के बावजूद जहाज मालिक तुरंत होर्मुज से अपने जहाज नहीं भेजेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जोतारो तमूरा ने कहा कि शिपिंग कंपनियां तब तक इंतजार करेंगी, जब तक उन्हें यह विश्वास नहीं हो जाता कि अमेरिका-ईरान समझौता सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका असर जमीन पर भी दिख रहा है। तमूरा ने कहा, "सिर्फ संबंधित देशों के बीच कोई साधारण समझौता हो जाना अपने आप में काफी नहीं होगा। जरूरी यह है कि उसका असर होर्मुज के वास्तविक हालात में भी साफ तौर पर दिखाई दे। ऐसा हुआ तभी शिपिंग कंपनियां वहाँ से दोबारा सुरक्षित और निश्चिंत होकर अपने जहाज गुजारने का फैसला कर पाएंगी। उनके अनुसार, होर्मुज से तेल टैंकरों और मालवाहक जहाजों की सामान्य आवाजाही बहाल होने में अभी कई सप्ताह लग सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते की घोषणा के साथ ही दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरने का मार्ग अब "सुरक्षित, संरक्षित और पूरी तरह सामान्य" है।

इमरान खान को पांचवीं बार इलाज के लिए ले जाया गया अस्पताल

बहन अलीमा ने उठाए सवाल

एजेंसी । इस्लामाबाद

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान महीनों से आंखों की तकलीफ से जूझ

रहे हैं। सोमवार को जेल प्रशासन इलाज के लिए पांचवीं बार उन्हें अस्पताल ले गया। अब उनके परिवार ने इस मामले को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने मंगलवार को कहा कि सरकार की ओर से मुहैया कराई गई जानकारी पर उन्हें रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 15 जून की सुबह उन्हें जानकारी मिली कि इमरान खान को एक बार फिर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (पीआईएमएस) ले जाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल की ओर से पहले भी इमरान खान की स्थिति को लेकर "संदिग्ध दावे" किए गए हैं, जिनमें यह कहा गया था कि उनकी 90 प्रतिशत दृष्टि ठीक हो चुकी है, जबकि इमरान खान ने स्वयं इन दावों को खारिज किया था। अलीमा खान ने सवाल उठाया कि आखिर इमरान खान को पांचवीं बार इंजेक्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है और मांग की कि उनका इलाज स्वतंत्र और योग्य विशेषज्ञों से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इस्लामाबाद में कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की ओर से उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और अदालत के आदेशों के बावजूद परिवार को उनसे नियमित रूप से मिलने नहीं दिया जा रहा। अलीमा खान ने दावा किया कि अदालत ने इमरान खान से हर मंगलवार छह परिवार के सदस्यों को मिलने की अनुमति दी थी, लेकिन पिछले कई महीनों से इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।

इमरान खान को जेल मैनुअल के अनुसार कई अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें परिवार से नियमित मुलाकात, वकीलों से संपर्क, किताबें और समाचार तक पहुंच, तथा उचित चिकित्सा सुविधा शामिल हैं, लेकिन इन अधिकारों का पालन नहीं हो रहा। प्रमुख अंग्रेजी दैनिक डॉन के अनुसार, अस्पताल प्रशासन ने बताया कि इमरान खान को सोमवार को फॉलो-अप इलाज के लिए पीआईएमएस लाया गया था, जहां उन्हें आंखों की बीमारी के लिए एक और एंटी-वीईजीएफ इंजेक्शन दिया गया।

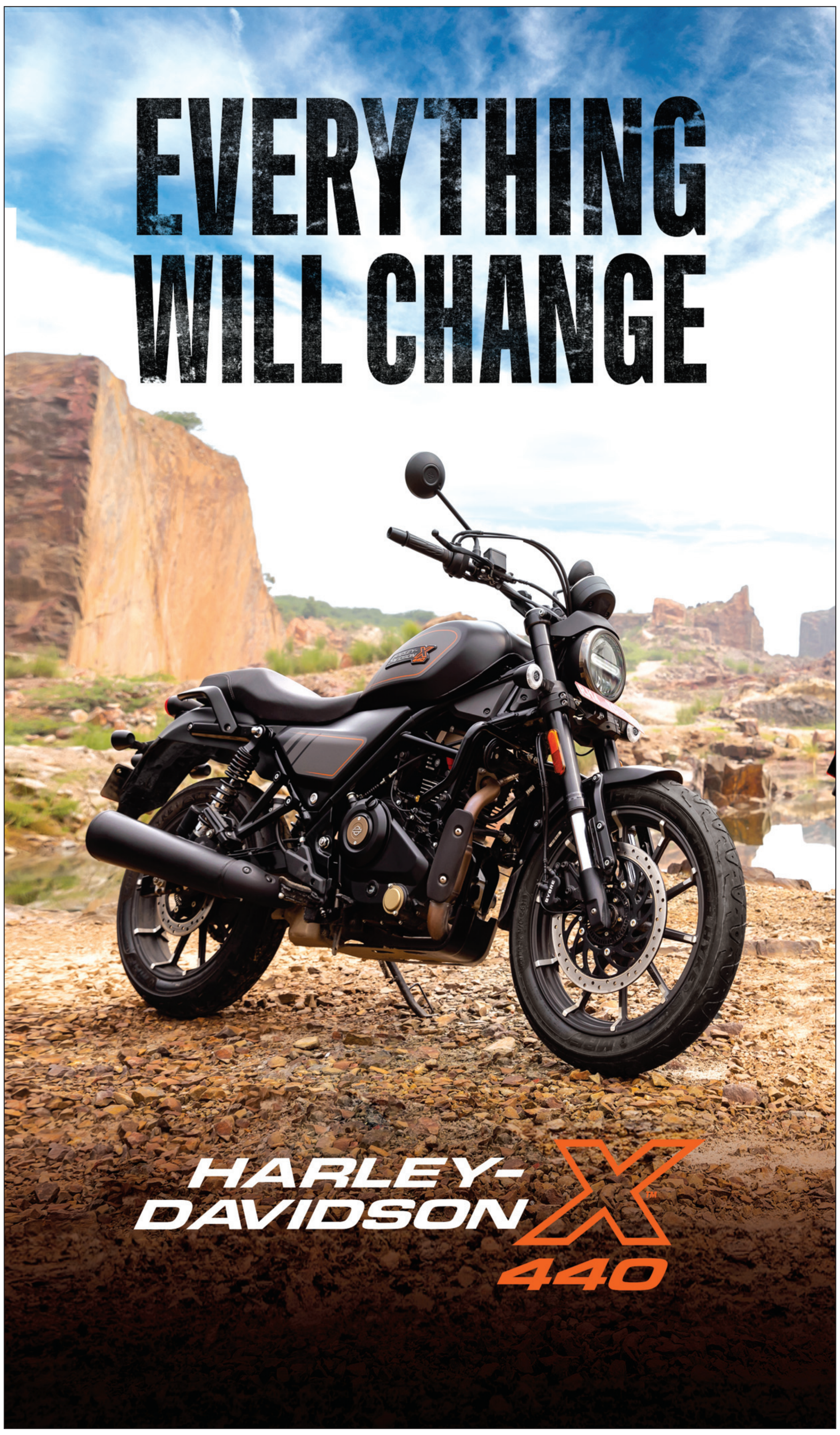

रास चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक

महागठबंधन की एकजुटता से जीत तय : दीपिका पांडेय

नवीन मेल संवाददाता

रांची। झारखंड में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा के समर्थन में चुनावी अभियान तेज हो गया है। इसी क्रम में रांची स्थित राजद के प्रदेश कार्यालय में राजद विधायकों एवं इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती और साझा राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास आवश्यक संख्या बल नहीं है और वह राज्य की जनभावनाओं के अनुरूप स्पष्ट नीति नहीं रखती। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, जिसका राजनीतिक जुड़ाव समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहा है। इसके विपरीत, महागठबंधन झारखंड के हितों व साझा मूल्यों के आधार पर पूरी तरह एकजुट है। दीपिका ने विश्वास जताया कि महागठबंधन की एकजुटता और विधायकों के समर्थन से रास उम्मीदवार बैजनाथ राम एवं प्रणव झा की जीत सुनिश्चित है। बैठक में राजद प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक संजय सिंह यादव, मंत्री संजय प्रसाद यादव, राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान, विधायक नरेश सिंह, राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ऑर्गन एवं टिश्यू डोनेशन विषयक कार्यशाला में हुए सम्मिलित, कहा

अंगदान कई व्यक्तियों के जीवन की नई शुरुआत बन सकती है

नवीन मेल संवाददाता

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ऑर्गन एवं टिश्यू डोनेशन (अंग एवं ऊतक दान) का विषय महत्वपूर्ण है। इसके लिए लोगों में जागरूकता की आवश्यकता है। इसके कानूनी पहलुओं को भी जानने होंगे। ऑर्गन एवं टिश्यू डोनेशन के लिए राज्य सरकार भी पहल कर रही है। अंगदान कई अन्य व्यक्तियों के जीवन की नई शुरूआत बन सकती है। लोगों के जीवन में नई उम्मीद और खुशियां ला सकता है। अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार, स्वास्थ्य संस्थानों, सामाजिक संगठनों तथा आम लोगों को मिलकर कार्य करनी चाहिए। मुख्यमंत्री आज बारियातू रोड स्थित एक होटल में मोहन फाउंडेशन की ओर से आयोजित 'अंग और ऊतक दान में सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां' कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यशाला का आयोजन कर संस्थान ने एक अच्छी पहल की है। स्वस्थ समाज के निर्माण को लेकर राज्य सरकार भी गंभीरता से कार्य कर रही है। अस्पतालों में किसी व्यक्ति की मृत्यु उपरांत उनके परिवारवालों से बातचीत की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंगदान मानवता, संवेदनशीलता, करुणा और सामाजिक उतरदायित्व का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में तकनीक आधारित चिकित्सा प्रणाली है। चिकित्सा जगत में बड़े पैमाने पर तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। रोबोटिक ऑपरेशन हो रहे हैं। लिवर, किडनी का प्रत्यारोपण हो रहा है। झारखंड सरकार भी स्वस्थ झारखंड निर्माण के दिशा में सकारात्मक कार्य कर रही है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, मणिपाल ऑर्गन शेयरिंग के कंट्री हेड कर्नल अवनीश, मोहन फाउंडेशन के कंट्री हेड ललिता रघुराम, क्रिटिकल केयर मणिपाल के अध्यक्ष डॉ विजय कुमार मिश्रा, कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल के संस्थापक निदेशक डॉ बी कश्यप सहित गणमान्य अतिथि उपस्थित थे।

राज्यपाल से मिलीं सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरिन, नेत्र शिविर की दी जानकारी

रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मंगलवार को सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरिन ने लोक भवन में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरिन ने राज्यपाल को अवगत कराया कि मुख्यालय पूर्वी कमान एवं मुख्यालय 111 एरिया के तत्वावधान में 15 से 19 जून तक मिलिट्री हॉस्पिटल, नामकुम में एक विशेष नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल), नई दिल्ली की विशेषज्ञ टीम के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मेगा नेत्र चिकित्सा शिविर के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों, जनजातीय समुदाय के लोगों एवं आम नागरिकों को नेत्र परीक्षण, परामर्श तथा विभिन्न उन्नत नेत्र चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के मेगा चिकित्सा शिविर समाज के सभी वर्गों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भाजपा संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह राष्ट्रीय अंबेडकर अवॉर्ड से सम्मानित

- **सामाजिक कार्यकर्ता अनिल बांसफोर ने प्रदेश कार्यालय रांची में आकर सौंपा अवॉर्ड**

नवीन मेल संवाददाता

रांची। झारखंड भाजपा के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह को राष्ट्रीय अंबेडकर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। अम्बेडकर स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स के अध्यक्ष, दर्जनों लिम्का बुक रिकॉर्ड होल्डर एवं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी सह बहुजन साहित्य अकादमी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अनिल बांसफोर के द्वारा भाजपा प्रदेश कार्यालय आकर यह अवॉर्ड संगठन महामंत्री को सौंपा। इस बाबत सामाजिक कार्यकर्ता सह रांची में अम्बेडकर स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स के अध्यक्ष अनिल बांसफोर ने बताया कि 15 मार्च, 2026 को जीएसकेआर भवन बैरागीपट्टेदा तिरुपति आंध्रप्रदेश में बहुजन साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित 18वां राष्ट्रीय सम्मेलन में झारखंड प्रदेश के भाजपा के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह को राष्ट्रीय अंबेडकर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। जिसे उन्होंने 16 जून को स्वयं राँची स्थित भाजपा कार्यालय पर आकर यह अवॉर्ड संगठन महामंत्री को प्रदान किया। उन्होंने बताया कि यह अवॉर्ड इसलिए प्रदान किया गया है क्योंकि संगठन महामंत्री झारखंड प्रदेश के दलित, गरीब, शोषित, पीड़ित, आदिवासी, खिलाड़ी एवं विशेषकर सफाई कर्मचारियों के परिवार को हरसंभव आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। बताया कि यह अवॉर्ड दलित, गरीब, वंचित समाज के उत्थान हेतु काम करने वाले विशिष्ट जनों को प्रदान किया जाता है। इधर इस मौके पर संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही जनसेवा और राष्ट्रसेवा है। भाजपा के एक एक कार्यकर्ता का जीवन देश सेवा, समाज सेवा और जरूरतमंदो की सेवा में समर्पित है। इस अवसर पर भाजपा कार्यालय में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा, विकास प्रीतम सिन्हा , सरोज सिंह आदि उपस्थित थे।

भाजपा को अपने विधायकों पर नहीं भरोसा : सोनाल शांति

नवीन मेल संवाददाता

रांची। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं रह गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वयं को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताने वाली भाजपा के नेताओं को आज अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ रहे हैं।

सोनाल शांति ने कहा कि झारखंड की जनता जानना चाहती है कि आखिर ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भाजपा को अपने विधायकों को एक स्थान पर रखने की आवश्यकता महसूस हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न राज्यों में सांसदों और विधायकों की खरीद-फरोख्त तथा सत्ता परिवर्तन की राजनीति करने वाली भाजपा आज खुद अपने विधायकों के टूटने की आशंका से घिरी हुई है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उसके सभी विधायक एकजुट हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी के भीतर मतभेद उभरकर सामने आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के कई विधायक अपने स्तर पर अलग राय रखते हैं। सोनाल शांति ने कहा कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मजबूती से काम कर रही है।

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, CHATRA, JHARKHAND
(DISTRICT PLANNING OFFICE)

2nd CORRIGENDUM NOTICE

Memo No- 424 **Dated-15-06-2026**

In reference to Very Short Term EOI related to Selection of Agency For Supply, Installation, and Training for Water Adventure Equipments at Baksa Dam, Itkhori, Chatra." **under UNTIED FUND of District Planning Officer, Chatra, Govt. of Jharkhand"** vide Memo No.- 330 Dated 21-05-2026, PR No. 380477 (Planning and Development) (26-27)#D the corrigendum notice is hereby released with modified Terms & Conditions as per following details:-

S. No.	Milestone	Date/Time
1	**EoI NO- 330 dated 21-05-2026**	
1	Last date receipt of Technical and Financial proposal (Sealed Envelope)	18-06-2026, Time- 03:00PM
2	Opening of Technical Proposals, Presentation and Financial Bids	19-06-2026, Time- 03 : 15 PM

The Details of changes in RFP may have been seen on official website-chatra.nic.in.

District Planning Officer, Chatra

PR 382518 Planning and Development(26-27).D

पेज एक के शेष

कृषक व सरकार साथ....

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर कृषि व्यापार मेला-2026 के 'लोगो' का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने टाना भगत परिवारों को चार दुधारू पशुओं के शेड निर्माण के लिए शत-प्रतिशत अनुदान पर राशि (चेक) प्रदान की। साथ ही, राज्य के उत्कृष्ट किसानों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं, विभिन्न जिला के कृषि कार्यालयों में पशु चिकित्सक एवं अनुसेवक के पद के लिए नियुक्ति पत्र एवं 209 लोगों को डिजिटल एआई किट प्रदान किया।

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की लगभग 80 प्रतिशत आबादी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। आज जलवायु परिवर्तन के कारण खेती कार्य में नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आने वाले समय में पीने और खेती के पानी का घोर संकट होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में भू-जल का लगातार सिर्फ दोहन ही हो रहा है। नियम यह है कि हम जितना धरती से लेते हैं, उसका कुछ हिस्सा हमें रिचार्ज पिट और सोक पिट के जरिए वापस लौटाना भी होगा, अन्यथा प्रकृति हमें माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि हम पानी बचाएं। जल संचय पर ध्यान केंद्रित करें। खेतों तथा बंजर भूमि पर जल संचय के लिए जगह बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा, दुनिया में आज जो चल रहा है, उससे सबसे अधिक किसान प्रभावित हो रहे हैं। जरूरत है कि इस संकट में हम किस प्रकार अपने किसानों को तैयार करें, ताकि कम पानी में अधिक उपज की जा सके। हर जगह जलवायु परिवर्तन की चिंता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज सड़कों और उद्योगों के नाम पर 50-100 साल पुराने जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, जिससे शहर कंक्रीट के बेजान जंगल में तब्दील हो रहे हैं। इसके विपरीत, कटते पेड़ों के अनुपात में वृक्षारोपण की रफ्तार चींटी की चाल से भी कम है। उन्होंने कहा, विकास की लकीर के साथ खिंच रही इस विनाश की लकीर को रोकना होगा और इसमें आम जन-भागीदारी बेहद जरूरी है। उन्होंने पशुधन का जिक्र करते हुए कहा कि ये गाय-बकरियां भी तभी बचेंगी, जब धरती पर पानी, पेड़ और हरियाली सुरक्षित रहेगी। इंसानों का वजूद भी पानी और पेड़ पौधों से ही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर स्वयं कृषि व्यापार मेले में लगे स्टॉलों का भ्रमण किया तथा अधिकारियों को कई अहम दिशा-निर्देश भी दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बिरसा कृषि रथ-2026 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 16 से 18 जून 2026 तक आयोजित इस मेले में राज्यभर के प्रगतिशील किसान, देशभर के कृषि वैज्ञानिक शामिल हो रहे हैं। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों के 200 स्टॉल मेले में लगाए गए हैं, जहां नवाचारों को प्रदर्शित किया जाएगा। विभिन्न विषयों पर आयोजित सेमिनार में किसान नई तकनीक और नवाचारों से अवगत हो सकेंगे इस अवसर पर मंत्री डॉ इरफान अंसारी, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, राज्यसभा सदस्य महुआ माजी, विधायक सुरेश कुमार बैठा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ एससी दुबे, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीक सहित राज्य सरकार के वरीय अधिकारी एवं अन्य गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद थे। मौके पर विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे कृषक भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
जिला नियोजनालय-सह-मॉडल कैरियर सेन्टर, लोहरदगा

भर्ती कैम्प संबंधी सूचना

दिनांक 18.06.2026 को जिला नियोजनालय कार्यालय, लोहरदगा में भर्ती कैम्प का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निम्नांकित निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों ने उपस्थित रहने की सहमति जताई है:–

Sl. No	Name of the Employer & Address	Name of the Post	No. of Vacancy	Qualification Required	Age	Experience	Remarks (Pay Scale)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	L.I.C. of India, Lohardaga.	Bima Sakhi.	55	10^{th} to Graduate	18 & Above	--	Stipend 5000/= to 7,000/= Per Month.
2	MAETT SKILLS, Ormanjhi Ranchi 835219.	Block Coordinators	7	Graduate	25-40	01 yrs.	20,000-40,000 (According to work (Incentive Base) Job Location : Lohardaga
		Panchayat Field Executive	30	12^{th}	20-40	--	20,000/- + Incentive Job Location : Lohardaga
		Trainees for Computer	60	10^{th}	18-25	--	Salary After Training. Place of Posting : Ranchi.
		Trainees for Sampling Trailor	60	10^{th}	18-25	--	Salary After Training. Place of Posting : Ranchi.
		Trainees for GDA (Nursing)	60	10^{th}	18-25	--	Salary After Training. Place of Posting : Ranchi.
		Trainees for Electricin	60	10^{th}	18-25	--	Salary After Training. Place of Posting : Ranchi.
3	Terrier Security Services India Pvt. Ltd., Bengaluru Karnataka.	Security Guard	250	10^{th}/12th/Graduation	18-45	Yes	Salary 17,000/= to 23000/= Job Location - PAN India.
4	Dusky Stallion Education and Training Services Pvt. Ltd., Haryana.	NAPS Trainee	200	12^{th}/Graduation/Diploma/ITI	18-28	--	Salary 15500/- to 20000/= Job Location : Ahmedabad.
Total							

योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार जो पूर्व से निबंधित नहीं है वे अपने निकटतम नियोजनालय में अथवा www.jharniyojan.jharkhand.gov.in/ www.ncs.gov.in पर अपना निबंधन कराते हुए उपरोक्त भर्ती कैम्प में नियोजक/नियोजक के प्रतिनिधि के समक्ष अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं उसकी एक छाया प्रति तथा अपना बायोडाटा 02(दो) कॉपी फोटो 4 के साथ साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो। साक्षात्कार सुबह 11:00 बजे से होगी। जो उम्मीदवार पूर्व से निबंधित है उनको पुनः निबंधन कराने की आवश्यकता नहीं है। नियोजक निजी क्षेत्र के है, अतः साक्षात्कार, रिक्ति एवं सेवा शर्तो के लिए वे उत्तरदायी है। नियोजनालय मात्र सुविधा प्रदाता है।

PR.NO.382465 Lohardaga(26-27):D **District Employment Officer, Lohardaga.**

पलामू समाहरणालय
प्रपत्र VI 'क'
झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय) या
समाहर्त्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम–30/2013 की धारा–11 (1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या :–364/भू0अ0, **पलामू, दिनांक :–16.06.2026**

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–चेड़ाबार, थाना सं0–26, थाना–चैनपुर, अंचल–चैनपुर, जिला–पलामू** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **Construction of ROB at EP No.-291/27, 291/28 between Daltonganj to Rajhara Railway near Bajraha village at Palamu in the State of Jharkhand Under Central Road Fund for the year 2022-23. Job No. (CRF-JHR-2022-23-65) पथ** निर्माण हेतु अपेक्षित है।

प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–चेड़ाबार, थाना सं0–26, थाना–चैनपुर, अंचल–चैनपुर, जिला–पलामू** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **3.025393 एकड़** यानि **1.22436** हेक्टेयर मानक माप का भू–खण्ड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :–

ग्राम–चेड़ाबार, थाना सं0–26, कुल रकबा–3.025393 एकड़

क्र0 सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	भूमि का किस्म	भूमि स्वामित्व का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0) उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	95	18	टाड तीन	बकास्त	0.020021	नवीन दुबे, पिता–जर्नाधन दुबे, सुनिल दुबे, अरविन्द दुबे, पिता–सव0 बन्धु दुबे, सुनिल दुबे, पिता–जगत दुबे	–	–	–	–
2	121	20	टाड तीन	बकास्त	0.184673	1. शारदा देवी, पति–सच्चिदानन्द राम, 2. नवीन दुबे, पिता–जर्नाधन दुबे, सुनिल दुबे, अरविन्द दुबे, पिता–सव0 बन्धु दुबे, सुनिल दुबे, पिता–जगत दुबे				
3	120	23	टाड तीन	बकास्त	0.050838	अज्ञात				
4	78	24	टांड़ दो	बकास्त	0.187648	1. उमेश्वर दुबे, रामेश्वर दुबे, दिलीप कुमार दुबे, पिता–आदित दुबे, 2. अभिनाश दुबे पिता कुन्दन कुमार दुबे				
5	10	60	टांड़ दो	बकास्त	0.027165	रामजन्म सिंह, परिखा सिंह, पिता–सुन्दर सिंह एवं अखिलेश सिंह, कमलेश सिंह, पिता–स्व0 भैरो सिंह				
6	21	61	टांड़ दो	बकास्त	0.179861	पारसनाथ सिंह, विश्वास सिंह, हरिहर सिंह, सुदर्शन सिंह, पिता–धाधुरी सिंह, अखिलेश सिंह, कमलेश सिंह, पिता–स्व0 भैरो सिंह, रामजन्म सिंह, परिखा सिंह, पिमा–सुन्दर सिंह				
7	55	70	टांड़ दो	बकास्त	0.062649	सीताराम सिंह, रामपदारथ सिंह, पिता–मटुक सिंह, कामता प्रसाद सिंह, कपिलदेव सिंह, पिता–रामअवतार सिंह				
8	42	71	टांड़ दो	बकास्त	0.055232	पारसनाथ सिंह, विश्वास सिंह, हरिहर सिंह, सुदर्शन सिंह, पिता–धाधुरी सिंह, अखिलेश सिंह, कमलेश सिंह, पिता–स्व0 भैरो सिंह, रामजन्म सिंह, परिखा सिंह, पिमा–सुन्दर सिंह				
9	106	84	टांड़ दो	बकास्त	0.007345	आर के सिंह, पिता–अमरजीत सिंह, विनय सिंह, सुनिल सिंह, पिता–अर्जुन सिंह				
10	106	85	टांड़ दो	बकास्त	0.027112	अज्ञात				
11	42	86	टांड़ दो	बकास्त	0.033417	अज्ञात				
12	10	88	टांड़ दो	बकास्त	0.025917	अज्ञात				
13	26	89	टांड़ दो	बकास्त	0.01739	अज्ञात				
14	116	90	टांड़ दो	बकास्त	0.017776	झारों कुवंर, पति–स्व0 कुवंर सिंह, राजेन्द्र सिंह, विदेशी सिंह, पिता–जानकी सिंह				
15	37	91	टांड़ दो	बकास्त	0.01715	अज्ञात				
16	28	153	टांड़ तीन	बकास्त	0.000609	अज्ञात				
17	138	156	रास्ता	गैर मजरूआ आम	0.743269	गैरमजरूआ आम, रास्ता				
18	138	157	रास्ता	गैर मजरूआ आम	0.1300	गैरमजरूआ आम, रास्ता				
19	55	160	टांड़ तीन	बकास्त	0.067469	सीताराम सिंह, रामपदारथ सिंह, पिता–मटुक सिंह, कामता प्रसाद सिंह, कपिलदेव सिंह, पिता–रामअवतार सिंह				
20	55	161	टांड़ तीन	बकास्त	0.098011	सीताराम सिंह, रामपदारथ सिंह, पिता–मटुक सिंह, कामता प्रसाद सिंह, कपिलदेव सिंह, पिता–रामअवतार सिंह				
21	34	163	टांड़ तीन	बकास्त	0.166127	कुली सिंह, बहादुर सिंह, पिता–अन्तु सिंह एवं ललन सिंह, पिता–बन्धन सिंह				
22	26	167	टांड़ तीन	बकास्त	0.050419	सीताराम सिंह, रामपदारथ सिंह, पिता–मटुक सिंह, कामता प्रसाद सिंह, कपिलदेव सिंह, पिता–रामअवतार सिंह				
23	137	169	परती कदीम	गैर मजरूआ मालिक	0.005134	गैरमजरूआ मालिक				
24	14	171	टांड़ दो	बकास्त	0.019834	अज्ञात				
25	106	176	टांड़ दो	बकास्त	0.005269	अज्ञात				
26	117	177	नदी	बकास्त	0.013742	अज्ञात				
27	1	178	नदी	बकास्त	0.029876	अज्ञात				
28	137	181	परती कदीम	गैर मजरूआ मालिक	0.042021	गैरमजरूआ मालिक				
29	34	208	टांड़ तीन	बकास्त	0.030413	अज्ञात				
30	55	367	टांड़ तीन	बकास्त	0.06567	1. प्रदीप राम, सचिदा राम, राजकुमार राम, बब्लु राम, राजु राम सभी के पिता–सीता राम 2. अज्ञात				
31	60	383	टांड़ दो	बकास्त	0.011377	अज्ञात				
32	42	391	टांड़ दो	बकास्त	0.005717	अज्ञात				
33	19	393	टांड़ दो	बकास्त	0.01995	रामेश्वर सिंह, पिता–कंगाली सिंह, श्याम बिहारी सिंह, पिता–राजमुनी सिंह				
34	106	394	टांड़ दो	बकास्त	0.01239	मैना देवी, पति–कृष्णा सिंह, सुमित्रा देवी, पति–शिवशरण सिंह				
35	14	529	टांड़ दो	बकास्त	0.034254	बासुदेव सिंह, पिता–दिनदयाल सिंह, अशोक सिंह, महेन्द्र सिंह				
36	17	530	टांड़ दो	बकास्त	0.002646	पारसनाथ सिंह, विश्वास सिंह, हरिहर सिंह, सुदर्शन सिंह, पिता–धाधुरी सिंह				
37	128	533	टांड़ दो	बकास्त	0.09095	सकेन्द्र मिस्त्री, विजय मिस्त्री, पिता–स्व0 नथुनी मिस्त्री				
38	137	612	परती कदीम	गैर मजरूआ मालिक	0.00304	गैरमजरूआ मालिक				
39	137	786	नदी	गैर मजरूआ मालिक	0.463012	गैरमजरूआ मालिक				
कुल :–					3.025393					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पलामू के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/ समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा–12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यो के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यो के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पलामू और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा–11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा–15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पलामू के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

कानूनगो, जिला भू–अर्जन कार्यालय,पलामू | जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पलामू | अपर समाहर्त्ता, पलामू | उपायुक्त, पलामू

PR 382529 Palamu(26-27).D

ईरानी फुटबॉल टीम बोली- हमें तुरंत अमेरिका छोड़ने को कहा गया

मैच के तुरंत बाद मेक्सिको जाना पड़ा, ईरानी खिलाड़ी ने गन सेलिब्रेशन किया था

एजेंसी । कैलिफोर्निया

अमेरिका में फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान ईरानी प्लेयर के गन सेलीब्रेशन पर विवाद हो गया। इस घटना के बाद ईरानी टीम को मैच के तुरंत बाद अमेरिका से मेक्सिको जाने को कहा गया। ईरान की टीम का बेस कैंप मेक्सिको है। अमेरिका में हर मैच के बाद ईरान को बेस कैंप लौटना होता है। ईरान के कोच आमिर घालेनोई ने फीफा और अमेरिकी अधिकारियों पर आरोप लगाए कि टीम को आराम का वक्त भी नहीं मिला। दरअसल लॉस एंजिल्स के मैदान पर मंगलवार सुबह न्यूजीलैंड के खिलाफ ईरान ने मैच खेला। ईरान ने न्यूजीलैंड को 2-2 की बराबरी पर रोक दिया। ईरान के मिडफील्डर मोहम्मद मोहेबी ने भी एक गोल किया। इसके बाद उन्होंने गन सेलिब्रेशन किया था। जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। कई फैंस ने आलोचना करते हुए उन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।

स्टेडियम के बाहर ईरान के खिलाफ प्रदर्शन

करीब 4 महीने लंबी जंग के बाद अमेरिका-ईरान के बीच समझौता हो गया है, लेकिन मैच के दौरान भी इस तनाव का असर देखा गया। स्टेडियम के बाहर अमेरिकी प्रशंसकों ने झंडे लहराए और ईरानी सरका के खिलाफ प्रदर्शन किया।

मोहम्मद मोहेबी के सेलीब्रेशन पर कंट्रोवर्सी हो रही है मोहम्मद मोहेबी ने गोल करने के बाद उन्होंने गन सेलिब्रेशन किया था

कप्तान तारेमी बोले... हमारे लिए सब मुश्किल

मैच के बाद ईरान के कप्तान मेहदी तारेमी ने कहा- मेक्सिको से लॉस एंजिल्स पहुंचने में टीम को पांच घंटे लगे। आमतौर पर यह समय काफी कम होता है। सुरक्षा जांच और अन्य प्रक्रियाओं के कारण बेवजह परेशानी झेलनी पड़ी। फीफा से ज्यादा सहयोग की उम्मीद थी। इस समय हमारे लिए सब कुछ मुश्किल हो गया है।

ईरानी वीजा और टिकट पर भी विवाद हुआ था

- **ईरानी फुटबॉल टीम की तैयारियां पहले से कई समस्याओं से घिरी रही है। अमेरिका ने ईरान फुटबॉल महासंघ के कुछ अधिकारियों, सहयोगी स्टाफ और मीडिया प्रतिनिधियों को वीजा नहीं दिए जाने के कारण टीम का सपोर्ट सिस्टम भी प्रभावित हुआ है।**
- **वर्ल्डकप से पहले ईरान के फुटबॉल महासंघ ने आरोप लगाया कि विश्व कप के लिए उसके लिए रिजर्व टिकटों का हिस्सा वापस ले लिया गया। इससे उन ईरानी प्रशंसकों को बड़ा झटका लगा है जिन्होंने पहले ही यात्रा की बुकिंग कर ली थी। ईरानी समर्थकों को टिकट कोटे से वंचित करना खेल भावना के खिलाफ है।**

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज 35 हजार विद्यालयों में शुरू हुआ योगाभ्यास

नवीन मेल संवाददाता

रांची। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2026 के सफल आयोजन को लेकर राज्य के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में तैयारियां तेज हो गई हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची के निर्देश पर 16 जून से 20 जून तक सभी विद्यालयों में प्रतिदिन प्रातः 7:17 बजे से 8:00 बजे तक समान योग अभ्यास पद्धति का अभ्यास कराया जा रहा है। इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम "स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग" निर्धारित की गई है। राज्य के लगभग 35 हजार विद्यालयों के 45 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं इस योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। विद्यार्थियों के साथ शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं शिक्षकेत्तर कर्मी भी उत्साहपूर्वक योगाभ्यास कर रहे हैं। योग कार्यक्रम के प्रभावी संचालन के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षकों एवं नामित नोडल शिक्षकों को जिला, प्रखंड और संकुल स्तर पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। इसी क्रम में 17 जून तक सभी विद्यालयों में योग क्लब का पुनर्गठन किया जाएगा। सात सदस्यीय योग क्लब में प्रधानाध्यापक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक अथवा नोडल शिक्षक, बाल संसद के प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तथा योग में रुचि रखने वाले या खेलो झारखंड योग प्रतियोगिता के विजेता दो छात्र-छात्राओं को शामिल किया जाएगा। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने बताया कि योग क्लब के माध्यम से प्रत्येक बुधवार और शनिवार को नियमित योगाभ्यास कराया जाएगा। इसके अलावा प्रतिदिन पहली घंटी से पहले दो मिनट का ध्यान तथा प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को विद्यालय स्तरीय योग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना तथा योग को दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना है। राज्यभर के विद्यालयों में चल रहा यह विशेष अभियान अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के साथ-साथ विद्यार्थियों में स्वस्थ जीवनशैली विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सीनियर एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का ऐलान

नई दिल्ली । फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएआई) ने 26वीं सीनियर एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 के लिए सीनियर नेशनल टीम का ऐलान कर दिया है। यह प्रतियोगिता 19 से 24 जून तक नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता में 30 से ज्यादा देशों के 400 से अधिक टॉप एथलीट्स हिस्सा लेंगे। भारतीय टीम में 24 एथलीट (12 महिला और 12 पुरुष) शामिल हैं, जिनकी अगुवाई भारत की पहली और एकमात्र फेंसिंग ओलंपियन चदलावदा आनंदा भवानी देवी कर रही हैं। फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सतेज पाटिल ने कहा, "हम नई दिल्ली में एक शानदार, वर्ल्ड-क्लास टूर्नामेंट की मेजबानी करने को लेकर बहुत उत्साहित और पूरी तरह से आश्वस्त हैं।

जापान को हराकर भारत सेमीफाइनल में महिला हॉकी टीम की लगातार दूसरी जीत

नवीन मेल संवाददाता

रांची। एफआईएच महिला हॉकी नेशन्स कप न्यूजीलैंड 2025-26 में भारतीय महिला हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में आयोजित प्रतियोगिता में भारत ने जापान को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया। मंगलवार को खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। भारत की ओर से कप्तान सलीमा टेटे और लालरेमसियामी ने एक-एक गोल कर टीम को महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई। जापान की टीम पूरे मुकाबले में केवल एक गोल ही कर सकी और भारतीय रक्षा पंक्ति को पूरी तरह भेदने में सफल नहीं हो पाई। भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार तालमेल और अनुशासित खेल का परिचय देते हुए मैच पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। रक्षा पंक्ति और गोलरक्षक के बेहतरीन प्रदर्शन के कारण जापान को बराबरी का मौका नहीं मिल सका। इससे पहले भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में अमेरिका को 3-2 से पराजित किया था। लगातार दो जीत के साथ भारतीय टीम अब अपने पूल में 6 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर बनी हुई है।

प्रतियोगिता में भारत का अगला और लीग चरण का अंतिम मुकाबला 18 जून को उरुग्वे के खिलाफ खेला जाएगा। टीम के शानदार प्रदर्शन से भारतीय हॉकी प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। भारतीय महिला हॉकी टीम की लगातार दूसरी जीत और सेमीफाइनल में प्रवेश पर खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए आगामी मुकाबलों के लिए शुभकामनाएं दी हैं।

झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी की प्रथम वार्षिक आमसभा 21 जून को

रांची। झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी (जेएसएस) की प्रथम वार्षिक आमसभा आगामी 21 जून 2026 (रविवार) को प्रातः 11 बजे मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम, मोराबादी स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में झारखंड के पूर्व ओलंपियन, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, खेल प्रशासक, खेल पत्रकार, प्रशिक्षक, खेल अधिकारी, खेल विशेषज्ञ और खेल सलाहकार शामिल होंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य पूर्व खिलाड़ियों की पहचान और अस्तित्व को सशक्त बनाए रखना, युवा खिलाड़ियों की समस्याओं पर चर्चा करना, झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी के सफल संचालन के लिए समिति का गठन करना तथा राज्य में खेल विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करना है।

- **खेल विकास और खिलाड़ियों के हितों पर होगी चर्चा**

रांची जिला ओलंपिक एसोसिएशन की बैठक संपन्न, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

नवीन मेल संवाददाता

रांची । रांची जिला ओलम्पिक एसोसिएशन की विशेष बैठक आज श्री निशीकांत पाठक की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक दिवस के आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई तथा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रांची जिला ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध विभिन्न जिला खेल संघों द्वारा वृहद रूप से मनाया जाएगा। इसके तहत प्रातः 9:00 बजे बिरसा मुंडा स्टेडियम, मोराबादी में रांची जिला ओलम्पिक एसोसिएशन के बैनर तले सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न खेल संघों के खिलाड़ी, पदाधिकारी एवं खेलप्रेमी भाग लेंगे। बैठक में झारखंड ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों के आलोक में अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक दिवस के आयोजन पर भी चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि 23 जून 2026 को प्रातः 6:30 बजे साइक्लोथॉन के साथ ओलम्पिक दिवस समारोह का शुभारम्भ किया जाएगा। यह कार्यक्रम झारखंड ओलम्पिक एसोसिएशन एवं रांची जिला ओलम्पिक एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होगा। इसी दिन बिरसा मुंडा स्टेडियम परिसर में फलदार वृक्षों का रोपण भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 28 जून 2026 को मोराबादी मैदान में मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। वहीं झारखंड ओलम्पिक परिसर में "ओलम्पिक 2036" एवं "ग्रीन फॉरेस्ट" विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ओलम्पिक सप्ताह के दौरान विभिन्न जिला खेल संघों द्वारा खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा तथा खेल, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण एवं ओलम्पिक मूल्यों से संबंधित जागरूकता सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने इन आयोजनों को सफल बनाने के लिए सभी जिला खेल संघों, खिलाड़ियों एवं खेलप्रेमियों से सक्रिय सहभागिता की अपील की।

व्यापार/लाइफ व साइंस

भारत और खाड़ी देशों के बीच गहरे पानी में एनर्जी पाइपलाइन बनाने की रिपोर्ट्स को केंद्र ने किया खारिज

एजेंसी । नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने मंगलवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया, जिसमें ये दावा किया गया था कि सरकार भारत के गुजरात से ओमान और अन्य खाड़ी देशों के बीच गहरे पानी में एक एनर्जी पाइपलाइन विकसित करने पर काम कर रही है। इन रिपोर्ट्स पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए, पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि हमारे ध्यान में ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट आई हैं जिनमें कहा गया है कि भारत सरकार 'मिडिल ईस्ट-इंडिया डीपवॉटर पाइपलाइन' (एमईआईडीपी) नाम की एक डीप-सी एनर्जी पाइपलाइन बनाने पर तेजी से काम कर रही है, जो गुजरात को ओमान और खाड़ी के अन्य देशों से जोड़ेगी। मंत्रालय ने बयान में कहा, "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय साफ तौर पर यह स्पष्ट करना चाहता है कि इस समय मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस प्रोजेक्ट को लेकर ओमान या किसी अन्य खाड़ी देश के साथ मंत्रालय के किसी भी स्तर पर कोई सक्रिय चर्चा या बातचीत नहीं हो रही है। मंत्रालय ने आगे कहा, "यह स्पष्टीकरण इस मामले से जुड़ी सभी अटकलों को खत्म करने के लिए जारी किया गया है।" इसके अतिरिक्त, भारत लगातार मध्य पूर्व से ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। माल्टा के झंडे वाला एलएनजी कैरियर 'दिशा' सोमवार को होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित गुजरा। यह जहाज गुजरात के दहेज के लिए 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर जा रहा है और इसके 18 जून को भारत पहुंचने की उम्मीद है।

इस जहाज का प्रबंधन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाला एक ग्रुप कर रहा है। सरकार ने कहा कि वह भारतीय नाविकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने और उन्हें हर तरह की मदद देने के लिए विदेश मंत्रालय, विदेशों में भारतीय मिशनों, शिपिंग कंपनियों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ लगातार संपर्क में है। पूरे भारत में बंदरगाहों का कामकाज सामान्य है। ओमान के तट पर एक कमर्शियल जहाज 'एमटी सेटेबेलो' पर अमेरिकी सेना के हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत के कुछ दिनों बाद, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग (डीजीएस) ने शिपिंग कंपनियों और समुद्री भर्ती व प्लेसमेंट एजेंसियों को सलाह दी है।

गैस पाइपलाइन परियोजना पर मंत्रालय का स्पष्टीकरण

- **मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है**
- **ओमान या किसी खाड़ी देश के साथ कोई सक्रिय वार्ता नहीं चल रही**

रांची के खुदरा कारोबारियों के लिए खुल रहे नए अवसर, आधुनिक सुविधाओं से मिल रही नई उड़ान

नवीन मेल संवाददाता

रांची। राजधानी रांची के छोटे दुकानदारों, भोजनालय संचालकों और स्थानीय कारोबारियों के लिए कारोबार बढ़ाने के नए अवसर सामने आ रहे हैं। पेय पदार्थ क्षेत्र की अग्रणी कंपनी कोका-कोला इंडिया और मून बेवरेजेज लिमिटेड की ओर से व्यापारियों को शीतलन अवसंरचना, रेफ्रिजरेटर और डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है, जिससे स्थानीय व्यवसायों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। कंपनी के अनुसार इस पहल का उद्देश्य छोटे व्यापारियों को बेहतर ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनके व्यवसाय के विस्तार में सहयोग करना है। आधुनिक सुविधाओं और तकनीकी सहायता के माध्यम से कारोबारियों को बदलते बाजार के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। कोका-कोला इंडिया एवं दक्षिण-पश्चिम एशिया के उपाध्यक्ष संदीप बजोरिया ने कहा कि स्थानीय दुकानदार किसी भी शहर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। उन्हें आधुनिक सुविधाओं और तकनीक से जोड़कर कारोबार को नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे अधिक ग्राहकों तक पहुंच बना सकें और अपनी आय बढ़ा सकें। वहीं एमएमजी समूह के उपाध्यक्ष अनंत अग्रवाल ने कहा कि डिजिटल उपकरण और बेहतर बुनियादी सुविधाएं छोटे कारोबारियों के लिए नए अवसरों का सृजन कर रही हैं। इससे न केवल व्यापार बढ़ रहा है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। कंपनी का दावा है कि इस पहल का लाभ उठाने वाले कई स्थानीय व्यवसायों ने ग्राहकों तक अपनी पहुंच बढ़ाई है, कारोबार का विस्तार किया है और रोजगार सृजन में भी योगदान दिया है। इससे रांची के खुदरा व्यापार क्षेत्र को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

झारखण्ड सरकार
GOVERNMENT OF JHARKHAND

हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

संदेश

विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस

प्रति वर्ष मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस पर हम भूमि और जल के महत्व पर चिंतन करते हैं। मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस 2026 का विषय "चारागाह पहचानें। सम्मान करें। पुनर्स्थापित करें" है। यह हमें दर्शाता है कि पृथ्वी की आधी से अधिक सतह को आच्छादित करने वाले चारागाह खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता और जलवायु सहनशीलता बनाए रखने में कितने महत्वपूर्ण हैं। कई पीढ़ियों से पशुपालक और आदिवासी समुदाय अपनी संरक्षकता के माध्यम से इन भू-भागों की सुरक्षा करते आए हैं।

झारखण्ड राज्य जो समृद्ध वनों, उपजाऊ मिट्टी और विविध पारिस्थितिक तंत्रों से संपन्न है, आज वनों की कटाई, भूक्षरण और जल संकट जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये खतरे हमारे कृषि, जल संसाधनों और असंख्य परिवारों की आजीविका को प्रभावित कर रहे हैं। वैश्विक समुदाय का हिस्सा होने के नाते हमें अपनी भूमि के मूल्य को पहचानना होगा, पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करना होगा और बंजर क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करना होगा ताकि एक सतत् भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।

यह दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारी भूमि का स्वास्थ्य हमारे लोगों की समृद्धि से जुड़ा हुआ है। जल संरक्षण, वनों की रक्षा, पर्यावरण से अनुकूल खेती अपनाने और भूमि क्षरण को रोकने के माध्यम से हम झारखण्ड की प्राकृतिक संपदा को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। हमारी भूमि ही हमारा जीवन है और इसे पहचान कर, सम्मान देकर और पुनर्स्थापित करके हम न केवल अपने पर्यावरण की रक्षा करते हैं, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित बनाते हैं।

जोहार !

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड

PR No. 382549 (Forest, Environment and Climate Changes) 2026-27